R.N.I. No.HIN/2002/8718 www.aksnews.com M.P./BHOPAL/642/2024-26

In Pursuit of Truth

पाक्षिक अक्स

वर्ष : 23 । अंक : 16
16 से 31 मई 2025
पृष्ठ : 48
मूल्य : 25 रु.

OPERATION SINDOOR

ऑपरेशन सिंदूर... आतंकिस्तान का दुस्साहस चित

25 मिनट में आतंकियों को गढ़ में ही निपटाया भारतीय सेना ने

भारत ने पाकिस्तान के साथ 2 बाहुबलियों को भी दिखा दिया दम

mycem cement

HEIDELBERGCEMENT

mycem power

Trusted German Quality

Over 150 Years

Send 'Hi' 7236955555

इस अंक में

विवाद

8 | विवादों वाला मंत्री

मप्र सरकार में मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान जो कहा वह सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और उसकी जमकर आलोचना भी की जा...

डायरी

10-11 | फॉर्मूला-16 कैबिनेट...

मप्र में 9 साल से कर्मचारियों के प्रमोशन लंबित हैं। इस मसले को सुलझाने में जुटी मोहन यादव सरकार ने प्रमोशन के लिए फॉर्मूला-16 बनाया है। दरअसल, प्रदेश में 2016 से प्रमोशन पर ब्रेक लगा है। इसलिए इसे...

विकास

13 | बदलेगा सिंचाई-व्यापार का...

मप्र और महाराष्ट्र के बीच वर्षों से चला आ रहा तापी बेसिन रिचार्ज परियोजना का विवाद समाप्त हो गया है। दोनों राज्यों ने इस पर सहमति जताते हुए आगे काम शुरू करने का निर्णय लिया है। 10 मई को मप्र-महाराष्ट्र अंतर्राज्यीय नियंत्रण मंडल की 28वीं...

घपला

18 | लोक निर्माण विभाग में...

सरकार की सख्ती के बावजूद लोक निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं भ्रष्ट अफसरों का पूरा संरक्षण मिल रहा है। विभाग की कार्यप्रणाली को देखें तो यह तथ्य सामने आता है कि लोक निर्माण विभाग में भ्रष्ट सबसे विश्वसनीय है। इसका आंकलन इससे किया जा...

आवरण कथा 24, 25, 26, 27, 28

22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकिस्तान (पाकिस्तान) ने 26 लोगों को जिस तरह धर्म पूछ-पूछकर मौत के घाट उतारा, उसका बदला भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत सूद सहित ले लिया है। हमारी तीनों सेनाओं ने आतंकिस्तान के दुस्साहस को चित तो कर ही दिया, साथ ही 2 बाहुबलियों अमेरिका और चीन को भी आपना दम दिखा दिया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ कर दिया है कि साथ-साथ नहीं बहेंगे पानी और खून।

34

37

44

45

राजनीति

30-31 | सामाजिक खाई को...

जाति एक जटिल सामाजिक व्यवस्था है जिसका स्वरूप समय और स्थान के साथ बदलता रहा है। कर्म पर आधारित चार वर्णों वाली मूल व्यवस्था कब जन्म आधारित जाति की रूढ़ि में ढल गई यह कहना तो मुश्किल है परंतु जाति की व्यवस्था ने निश्चित रूप से भारतीय समाज और उसके...

महाराष्ट्र

35 | निकाय चुनाव का रास्ता...

यदि राज्य चुनाव आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए महाराष्ट्र के सभी स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ कराने का निर्णय किया तो ये चुनाव मिनी विधानसभा चुनाव जैसा दृश्य उत्पन्न करेंगे। महाराष्ट्र में स्थानीय निकायों के चुनाव संपन्न कराने को लेकर आया...

बिहार

38 | बिहार में कैसे बढ़ा क्षेत्रीय...

बिहार में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं। इसे लेकर जदयू, राजद, भाजपा और कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बिहार की इस सियासत में गठबंधन की राजनीति की बड़ी भूमिका रही है। यहां राष्ट्रीय के साथ क्षेत्रीय दलों की पैठ लंबे समय से है।

6-7 अंदर की बात
41 महिला जगत
42 अध्यात्म
43 कहानी
44 खेल
45 फिल्म
46 व्यंग्य

पाक्षिक अक्स

वर्ष-23, अंक-16, पृष्ठ-48
16 से 31 मई, 2025

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल

सम्पादकीय कार्यालय :
प्लाट नम्बर 150, जोन-1 मनोरमा कॉम्पलेक्स,
एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर
भोपाल- 462011 (म.प्र.),
टेलीफेक्स - 0755-4017788

email : akshmagazine@gmail.com
Website : www.akshnews.com
RNI NO. HIN/2002/8718 MPBPL/642/2021-23

प्रमुख संवाददाता

भावना सक्सेना-भोपाल, जय मतानी-भोपाल,
हर्ष सक्सेना-भोपाल,
दक्ष दवे-इंदौर, संदीप वर्मा-इंदौर,
विपिन कंधारी-इंदौर, गौरव तिवारी-विदिशा,
ज्योत्सना अनूप यादव-गंजबासौदा, राजेश तिवारी-उज्जैन,
टोनी छाबड़ा-धार, आशीष नेमा-नरसिंहपुर,
अनिल सोडानी-नई दिल्ली, हसमुख जैन-मुंबई,
इंद्र कुमार बिन्नानी-पुणे।

प्रदेश संवाददाता

पारस सरावगी (इंदौर)
09329586555
नवीन रघुवंशी (इंदौर)
09827227000 (इंदौर)
धर्मेन्द्र कथूरिया (जबलपुर)
098276 18400
श्यामसिंह सिकरवार (उज्जैन)
094259 85070
सुभाष सोमानी (रतलाम)
089823 27267
मोहित बंसल (विदिशा)
075666 71111

क्षेत्रीय कार्यालय

नई दिल्ली : ईसी 294 माया इंक्लेव मायापुरी, फोन : 9811017939
जयपुर : सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर (राजस्थान) मोबाइल-09829 010331
भिलाई : नेहरू भवन के सामने, सुपेला, रामनगर, भिलाई, मोबाइल 094241 08015
देवास : जय सिंह, देवास मो.-7000526104, 9907353976

स्वात्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लाट नं. 150, जोन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा काम्पलेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं हैं समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।

अपनी बात

हादसा कोई भी इस शहर में हो सकता है...

शायर तहसीन फिराकी का एक शेर है...

मुझ सा अंजान किसी मोड़ पे खो सकता है
हादसा कोई भी इस शहर में हो सकता है

उपरोक्त पंक्तियां मप्र की उस सुशासन मॉडल पर सवाल उठाती हैं, जिसे लागू करने में अधिकारियों ने लापरवाही बरती है। सरकार बार-बार सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को दुरुस्त और सुगम बनाने के लिए अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी करती है, लेकिन अधिकारी केवल खानापूर्ति कर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर देते हैं। इसी का नतीजा है कि गत दिनों राजधानी भोपाल के सबसे सुरक्षित और पहरे वाले क्षेत्र में ब्रेक फेल हुई अनफिट बस कई निर्दोष लोगों को रौंद देती है, जिसमें युवा महिला डॉक्टर की जान चली जाती है। यह तो महज एक उदाहरण है। प्रदेश में रोजाना ऐसी अनेकों घटनाएं हो रही हैं। इसकी वजह है न फिटनेस, न वैधता, पंजीकरण भी समाप्त, फिर भी पुलिस, परिवहन और तमाम प्रशासनिक व्यवस्थाओं के सामने यमराज बनकर वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं। जब भी कोई हादसा होता है शासन-प्रशासन की नींद खुलती है और भारी भरकम निर्देश जारी कर दिए जाते हैं। उसके बाद सड़कों पर वाहनों से वसूली का सिलसिला कुछ दिन इस कदर चलता है मानों पूरी व्यवस्था सुधर जाएगी। लेकिन फिर स्थिति ढाक के तीन पात वाली हो जाती है। प्रदेश में सुशासन का आलम यह है कि अस्पताल में आग लग जाए, पटाखा फैक्ट्री विस्फोट निर्दोषों की जान ले ले, हिंदू लड़कियां लव जिहाद की शिकार हो जाएं, उनसे दुष्कर्म किया जाए या फिर सड़कों पर मौत बनकर दौड़ते वाहनों से रेड सिग्नल पर रुककर कानून का पालन करने वालों की मौत हो जाए। प्रशासनिक लापरवाही के चलते ऐसी किसी भी घटना में सरकार सुशासन मॉडल की बात दोहराते हुए ऐसे भारी-भरकम निर्देश देती है, मानो अगले दिन से सबकुछ यूं सुधर जाएगा कि घटनाओं की पुनरावृत्ति कभी होगी ही नहीं, लेकिन लापरवाही के सुशासन मॉडल का रंग प्रशासन पर कुछ यूं चढ़ा है कि यह उतरना तो दूर, हल्का भी नहीं होता। ऐसे निर्देश फौरी तौर पर भले चर्चा में आ जाएं, पर कागजों के बाहर कभी नहीं निकलते हैं। यही वजह है कि ऐसे हादसे भी कभी नहीं रुकते। सड़कों पर जांच के नाम पर वाहन चालकों को धर-दबोचने में माहिर पुलिस और परिवहन कर्मियों की नजर इस जानलेवा वाहनों पर कैसे नहीं पड़ी, यह प्रदेश का बच्चा-बच्चा भी जानता है। ऐसे न जाने कितनी बसें अभी भी प्रशासनिक लापरवाही के दम पर मौत बनकर दौड़ रही हैं, उसकी गिनती भी करना संभव नहीं। बड़ा सवाल है कि क्या ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई के लिए दिया गया निर्देश जमीन पर उतर सकेगा। अभी तक की स्थिति को देखकर तो यही कहा जा सकता है कि बिल्कुल नहीं। क्योंकि प्रदेश में कई बड़े-बड़े हादसे हुए और जांच के नाम पर सदैव ही अधिकारियों का निलंबन होता रहा है, कुछ दिन बाद वे बहाल हो जाते हैं और मामला खत्म हो जाता है। परिवहन विभाग केवल राज्य की सीमा पर चौथ वसूली के लिए चेकिंग कर रहा है। हर जिले में उसके कार्यालय में बिना रिश्वत दिए लाइसेंस नहीं बन रहे हैं। ऑनलाइन कामकाज के सारे प्रयास फेल हो रहे हैं। फिटनेस चेकिंग, नवीनीकरण के सारे कामकाज में भाड़े के कर्मचारी यानी परिवहन विभाग के दलाल मोर्चा संभाले हुए हैं। यातायात पुलिस का काम केवल सीट बेल्ट और हेलमेट की चेकिंग के नाम पर हो रही वसूली तक सिमट गया है। ऐसे में सुशासन का दावा कितना मजबूत है, समझा जा सकता है। यह बात चौंकाती है कि जहां सरकार बैठी है, वहीं अनफिट बस मौत बनकर दौड़ रही है और कोई देखने वाला नहीं है। सुशासन का दावा वहीं ध्वस्त हो जाता है, जब हादसे लापरवाही की वजह से होते हैं और सरकार बाद में चौकन्नी होती है।

- राजेन्द्र आगाल

सिंहस्थ से बढ़ेगा राजस्व

पिछली बार उज्जैन में सिंहस्थ का आयोजन केवल एक महीने के लिए ही हुआ था। वहीं, इस बार इसे दो महीने का किए जाने से श्रद्धालुओं को अधिक समय मिलेगा। इस महाकुंभ में दुनियाभर से साधु-संत और श्रद्धालु उज्जैन पहुंचेंगे, जिससे मप्र सरकार को राजस्व में भी लाभ मिलेगा।

● **शोभा नागर,** उज्जैन (म.प्र.)

दोषियों को कड़ी सजा मिले

प्राइवेट कॉलेज में मुस्लिम छात्रों के एक गिरोह ने हिंदू छात्राओं को प्रेम जाल में फंसाकर उनके साथ दुष्कर्म किया और वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग की। प्रशासन को इस पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए और दोषियों को कभी न भूलने वाली सजा देनी चाहिए।

● **आनंदी जैन,** भोपाल (म.प्र.)

किसानों की चिंता करे सरकार

गेहूं उत्पादन के मामले में मप्र देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन इससे अलग मप्र के किसान देश में सबसे ज्यादा गेहूं की फसल की कटाई के बाद खेतों में आग भी लगा रहे हैं। देश में पराली जलाने के मामले में मप्र में इस साल रिकॉर्ड टूटा है। सरकार को इस बारे में कुछ सोचना चाहिए।

● **अनिकेत साहू,** बैतूल (म.प्र.)

2029 की तैयारी में कांग्रेस

कांग्रेस 2014 से सत्ता से बाहर है और ऐसा लगता है जैसे अभी उसे 2029 तक सत्ता से बाहर ही रहना है। यदि कांग्रेस को अपनी स्थिति मजबूत बनानी है तो उसे अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर ऐसा फ्यूचर प्लान बनाना होगा जो उसकी सत्ता में वापसी करा सके। लेकिन ऐसा होना असंभव सा लगता है। आने वाले दिनों के लिए कांग्रेस का फ्यूचर प्लान क्या है, ये राहुल गांधी के अलावा कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस का फ्यूचर राहुल गांधी के फ्यूचर प्लान पर ही टिका है। कांग्रेस की जैसी तैयारी अभी दिखाई देती है उसे देखकर लगता है कि कांग्रेस के लिए सत्ता अभी भी दूर की कौड़ी जैसी ही है। कांग्रेस को छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े-बड़े नेता तक को एकसाथ जोड़कर रखना होगा।

● **विनय सिंह,** हरदा (म.प्र.)

मप्र में गहराया जलसंकट

गर्मी का मौसम आते ही प्रदेश सहित देशभर में जलसंकट गहराने लगता है। मप्र के ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट के हालात बनने लगे हैं। भूमिगत जलस्तर में गिरावट के चलते कई गांवों में जलसंकट की स्थिति के चलते ग्रामीणों को कुएं में उतरकर प्यास बुझाना पड़ रही है। मप्र के 5 हजार से ज्यादा गांवों में जल संकट है। सिंचाई, कृषि कार्य समेत पेयजल का भी संकट है। आज भी हजारों गांव ऐसे हैं जहां अभी पाइप लाइन ही बिछी हुई है।

● **प्रियांशु शिवहरे,** अनूपपुर (म.प्र.)

न्यायपालिका और विधायिका में रार

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने राज्यपाल की शक्तियों का अधिग्रहण कर विधायिका के कार्य में हस्तक्षेप तो किया ही, संघीय ढांचे में केंद्र की ओर शक्ति के झुकाव को भी कुंद किया। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने इसी पर आपत्ति जताई। उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय के जज यशवंत वर्मा के घर मिले अधजले नोटों के मामले में कोई एफआईआर न दर्ज किए जाने पर भी प्रश्न खड़े किए। उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय के जज यशवंत वर्मा के घर मिले अधजले नोटों के मामले में कोई एफआईआर न दर्ज किए जाने पर भी प्रश्न खड़े किए।

● **अनिमेष त्यागी,** रायसेन (म.प्र.)

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जोन-1, मनोरमा काम्पलेक्स,
एफ-02, 03, एमपी नगर, भोपाल

दांव-पेच

नीतीश कुमार की कुर्सी डोल रही है!

बिहार के सत्ता गलियारों में चर्चा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पकड़ कमजोर हो रही है। भाजपा खेमे के कुछ नेताओं ने केंद्रीय नेतृत्व को यह फीडबैक दिया है कि नीतीश अब वोटर्स में पहले जैसे लोकप्रिय नहीं रहे। अमित शाह ने हाल के दौरे में कार्यकर्ताओं से कहा कि बूथ स्तर पर काम फिर से मजबूत किया जाए, जिससे कयास लग रहे हैं कि भाजपा अकेले चुनावी तैयारी कर रही है। सवाल उठ रहा है कि क्या 2025 में एनडीए का नेतृत्व फिर से नीतीश के हाथ में रहेगा? इस बीच एलजेपी (रामविलास) नेता चिराग पासवान सत्ता की चुप्पी में अपनी जमीन मजबूत करने में लगे हैं। चर्चा जोरों पर है कि सीटों के बंटवारे में वह बड़ी भूमिका निभाना चाहते हैं। चिराग ने हाल में कहा कि एनडीए के भीतर सबकुछ सहज रहेगा, पर अंदरखाने उनकी मांगें तेज हो गई हैं। एनडीए में छोटे दलों के महत्व को लेकर उनकी बयानबाजी विपक्षी दलों को भी बेचैन कर रही हैं।

फिर एक्शन मोड में वसुंधरा

राजस्थान में भाजपा की सरकार भले ही हाल ही में सत्ता में आई हो, लेकिन अंदरखाने की हलचलों ने राजनीतिक तापमान काफी बढ़ा दिया है। ताजा गपशप यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कामकाज पर सीधी टिप्पणी कर संगठन और सरकार दोनों को असहज कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक वसुंधरा राजे ने हाल में एक निजी बैठक में साफ तौर पर कहा कि प्रदेश सरकार जनता से दूर होती जा रही है और नीतिगत फैसलों में अनुभवी नेताओं की अनदेखी हो रही है। इसे लेकर पार्टी में सुगबुगाहट तेज है कि क्या राजे खेमा फिर से सक्रिय होकर अपना दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है? राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह तल्खी अचानक नहीं आई है। याद कीजिए, जब विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण हुआ था, तब वसुंधरा राजे गुट खुलकर नाराज था। कई वरिष्ठ नेताओं को किनारे कर नए चेहरों को टिकट देना भाजपा के भीतर एक गहरी नाराजगी का कारण बना था। कानाफूसी यह भी है कि वसुंधरा समर्थक कुछ विधायक मुख्यमंत्री के निर्णयों से नाखुश हैं और गुपचुप ढंग से संगठन के बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। कुछ पुराने वफादारों को संगठन में कोई खास भूमिका न दिए जाने से भी बेचैनी बढ़ी है। भाजपा हाईकमान के लिए यह स्थिति असहज है क्योंकि वह राजस्थान में सत्ता स्थिरता दिखाना चाहता है, खासकर 2029 के आम चुनाव को ध्यान में रखते हुए। यह भी रोचक है कि राजस्थान में भाजपा सरकार बनने के बाद वसुंधरा राजे ने अपेक्षाकृत कम सार्वजनिक कार्यक्रम किए हैं, और उनकी दूरी साफ दिख रही है।

तृणमूल-कांग्रेस होंगे एक ?

पश्चिम बंगाल में भाजपा के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच संभावित गठबंधन की चर्चाएं तेज हो गई हैं। अधीर रंजन चैधरी की नाराजगी के बावजूद कांग्रेस आलाकमान राज्य में तालमेल के पक्ष में दिख रहा है। सूत्र बताते हैं कि दोनों दलों के बीच चुनावी समझौता सीट-वार फॉर्मूले पर हो सकता है। अगर यह गठबंधन होता है तो यह भाजपा के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने पश्चिम बंगाल में सभी 294 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर राजनीतिक विश्लेषकों को चौंका दिया है। अब चर्चा यह है कि क्या ओवैसी की पार्टी मुस्लिम वोटों में सेंध लगाकर तृणमूल कांग्रेस को चोट पहुंचा पाएगी? ममता बनर्जी के रणनीतिकार इस कदम को भाजपा की बी-टीम वाली चाल के रूप में देख रहे हैं। एआईएमआईएम तेजी से सदस्यता अभियान भी चला रही है, खासकर सीमावर्ती जिलों में। भाजपा ने भी अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। फिल्म अभिनेता और भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती एक बार फिर एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने बंगाल में सनातनियों से ममता बनर्जी की सरकार को साफ करने की अपील की है। चर्चा है कि भाजपा मिथुन चक्रवर्ती को बंगाल में हिंदू चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट कर सकती है।

उप्र में का बा!

उप्र की राजनीति में इस समय सतह के नीचे कई गुप्त हलचलें चल रही हैं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व को लेकर सवाल खड़े कर रही हैं। कुछ अर्सा पहले गाजियाबाद की लोनी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिससे पार्टी के भीतर असंतोष की स्थिति स्पष्ट हुई है। मार्च में विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य सरकार को अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि वरिष्ठ अधिकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गुमराह कर रहे हैं और सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। गुर्जर ने यह भी दावा किया कि पुलिस ने उनकी कलश यात्रा को रोकने के दौरान उनके कपड़े फाड़े और उन्हें जान से मारने की साजिश रची गई। भाजपा ने गुर्जर को अनुशासनहीनता के आरोप में कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसमें उनसे सात दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया कि उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए?

हिचक रहा है विपक्ष

आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि देश की विपक्षी पार्टियां किसी मसले पर इतने लंबे समय तक सरकार के साथ रहीं। चीन और पाकिस्तान के साथ 1962 और 1971 में हुए युद्ध के समय भी तत्कालीन विपक्ष कांग्रेस की सरकार के साथ इतनी देर तक नहीं खड़ा था। इस बार बहुत सीमित युद्ध हुआ, जिसे आतंकवाद के खिलाफ लक्षित सैन्य कार्रवाई कहा जा रहा है कि लेकिन विपक्ष लगातार सरकार के साथ खड़ा रहा। युद्ध स्थगित हो जाने और उस पर सत्तारूढ़ दल यानी भाजपा की ओर से राजनीति शुरू कर देने के बावजूद विपक्षी पार्टियां सरकार को चुनौती देने से हिचक रही हैं। किसी भी मुद्दे पर सवाल नहीं उठा रही हैं। यहां तक कि संसद का विशेष सत्र बुलाने की कांग्रेस की मांग का भी समर्थन नहीं कर रही हैं। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर सर्वदलीय बैठक बुलाने और संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है।

सरकार पर भारी अफसर का जुगाड़

कहा जाता है कि जुगाड़ से बड़े-बड़े काम साधे जा सकते हैं। इस तथ्य को मप्र के एक आईएफएस अधिकारी ने साबित भी कर दिया है। दरअसल, उक्त अधिकारी को गत दिनों सरकार के मुखिया ने उनकी जिम्मेदारी से चलता कर दिया था, लेकिन साहब ने दिल्ली दरबार में जुगाड़ लगाया और सरकार के मुखिया को आईना दिखा दिया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गत दिनों सरकार के मुखिया कूनो नेशनल पार्क गए थे तो वहां उन्हें उक्त आईएफएस अफसर के खिलाफ कुछ शिकायतें मिलीं और वहीं उन्होंने कई खामियां भी देखीं। मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार के मुखिया ने जब इस संदर्भ में जवाब-तलब किया तो उन्हें मामला गंभीर लगा और उन्होंने नेशनल पार्क में बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे उक्त अधिकारी को वहां से चलता करने का निर्देश दे दिया। सरकार के मुखिया अपना काम करके राजधानी वापस आ गए, वहीं उक्त अफसर भी अपनी पर आ गए और उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी की ओर अपना रुख किया। बताया जाता है कि अपने विभाग से संबंधित मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने वाले मंत्रीजी से मिले। उन्होंने मंत्रीजी को अपनी आपबीती सुनाई और कहा कि मैं अच्छी तरह काम कर रहा हूं। यह बात केंद्रीय मंत्री को जच गई और उनकी पहल पर सरकार को अपना आदेश बदलना पड़ा। साहब फिर से उसी जगह काम करने लगे हैं।

मंत्रीजी का प्यार... अवैध खनन

भोपाल संभाग के एक जिले के प्रभारी मंत्री का एक फरमान चर्चा का केंद्र बना हुआ है। इसकी वजह यह है कि मंत्रीजी को अवैध खनन से प्यार हो गया है। सूत्रों का कहना है कि जिले के प्रभारी मंत्री ने कलेक्टर से कहा है कि जिले में रेत, गिट्टी, पत्थर, मुरम और मिट्टी का खनन करने वालों पर किसी तरह की कार्यवाही न की जाए। बताया जाता है कि जिले में अवैध रूप से बड़े पैमाने पर खनन होता है। इस काम में बड़े-बड़े लोग लगे हुए हैं। सूत्रों का कहना है कि जिले में जबसे युवा आईएएस अधिकारी कलेक्टर बने हैं, उन्होंने अवैध खनन करने वालों के खिलाफ अभियान चला दिया है। इससे परेशान होकर अवैध खनन करने वाले लोगों ने मंत्री से गुहार लगाई। मंत्री ने बिना सोचे-समझे कानून व्यवस्था को दरकिनार करते हुए कलेक्टर को निर्देश दे डाला कि अवैध खनन करने वालों पर सख्ती न बरती जाए। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार मंत्री को अवैध खनन से इतना प्यार क्यों उमड़ रहा है। वहीं जानकारों का कहना है कि अवैध खनन करने वाले मंत्रीजी के पास उनका हिस्सा पूरी ईमानदारी से पहुंचा रहे हैं, इसलिए मंत्रीजी उनके संरक्षक बन गए हैं। यहां बता दें कि इस क्षेत्र से जीतकर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सांसद बने हैं और वर्तमान में केंद्र सरकार मंत्री हैं।

फर्जी शिकायत से आईएएस परेशान

अवैध काम-धंधा करने वाले लोगों के निशाने पर ईमानदार और कर्त्तव्यनिष्ठ अफसर रहते हैं। इन दिनों प्रदेश की व्यवसायिक राजधानी के नगर निगम में पदस्थ आईएएस अफसरों के खिलाफ ब्लैकमेलरों का एक गैंग काम कर रहा है। सूत्र बताते हैं कि पहले तो ये अफसर के पास पहुंचकर उन पर अपना काम करवाने का दबाव बनाते हैं, जब अफसर गलत काम करने से मना कर देता है तो वे उसके खिलाफ अभियान शुरू कर देते हैं। इसके लिए तरह-तरह के आरोपों का पुलिंदा तैयार किया जाता है और लोकायुक्त या ईओडब्ल्यू में उक्त आईएएस अधिकारी के खिलाफ शिकायत की जाती है। हैरानी की बात तो यह है कि बिना जांच-पड़ताल के लोकायुक्त भी मामला दर्ज कर लेता है। जिससे आईएएस अधिकारी परेशान हैं। एक आईएएस अधिकारी के खिलाफ फर्जी कागजातों के आधार पर लोकायुक्त में शिकायत की गई तो वे परेशान हो उठे थे। हालांकि हाल ही में उनका तबादला राजधानी में हो गया है। लेकिन नगर निगम में पदस्थ आयुक्त सहित अन्य अफसर अभी भी अपनी ईमानदारी का खामियाजा भुगत रहे हैं। ब्लैकमेलरों का गैंग लगातार इन पर अवैध कार्य कराने का दबाव बना रहा है। साथ ही ऐसा न करने पर लोकायुक्त में शिकायत करने की धमकी भी दे रहा है। लेकिन अफसर भी दमदारी से मुकाबला करने में जुटे हुए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि ब्लैकमेलरों के खिलाफ किसी भी स्तर पर कार्यवाही नहीं हो रही है।

अनुमोदन का खेल

राजधानी की नगर निगम में इस समय अनुमोदन-अनुमोदन का खेल चल रहा है। दरअसल, नगर निगम द्वारा पारित बजट को लेकर ननि अध्यक्ष और महापौर में ठन गई है। सूत्रों का कहना है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश हुआ तो उसे नगर निगम अध्यक्ष ने अनुमोदित नहीं किया, तो नगर निगम आयुक्त ने उसे शासन के पास मार्गदर्शन के लिए भेज दिया। शासन ने उक्त फाइल को महापौर के पास भेज दिया, जिसे महापौर ने अनुमोदित कर दिया। लेकिन जैसे ही फाइल आयुक्त के पास पहुंची तो उन्होंने उसे फिर से शासन के पास भेज दिया। इस तरह नगर निगम में अनुमोदन-अनुमोदन का खेल चल रहा है। हैरानी की बात यह है कि किसी ने अध्यक्ष से बात करने की कोशिश नहीं की। इसका परिणाम यह हो रहा है कि पिछले तीन महीने से बजट अनुमोदन के लिए फुटबॉल बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ बजट न मिल पाने के कारण नगर निगम के कर्मचारियों के वेतन-भत्तों का भुगतान नहीं हो पा रहा है। यही नहीं बजट के अभाव में शहर सरकार द्वारा कराए जाने वाले विकास कार्य भी ठप्प पड़े हैं। हालांकि अब मामला सुधरने के आसार हैं।

इतनी हड़बड़ी क्यों?

देश इस समय भारत-पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध जैसे हालातों से गुजर रहा है। इस बीच प्रदेश सरकार के एक मंत्री ने सेना की एक अधिकारी के खिलाफ अनैतिक शब्दों का उपयोग कर दिया तो इससे देशभर में तूफान आ गया है। आलम यह है कि देशभर से आवाज उठ रही है कि उक्त मंत्री को हटाया जाए और गिरफ्तार भी किया जाए। लेकिन इस मामले में न तो सरकार और न ही उक्त मंत्री की पार्टी सख्त कदम उठाते दिख रही है। लेकिन प्रदेश के सबसे बड़े संभाग के कमिश्नर को न जाने ऐसी क्या सूझी कि उन्होंने शहर में मंत्रीजी के लगे पोस्टर और फोटो हटवाना शुरू कर दिया। बताया जाता है कि उन्होंने शहर के इस कोने से उस कोने तक के सारे उन पोस्टर और बैनरों को हटवा दिया, जिनमें मंत्रीजी के फोटो लगे हुए थे। लोग इस दृश्य को देखकर हैरान भी हुए कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। खुद संभाग के अफसर भी इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार साहब को इतनी हड़बड़ी क्यों दिखानी पड़ रही है, जबकि शासन की तरफ से कोई दिशा-निर्देश भी जारी नहीं हुए हैं।

भर्तियां अनेक... परीक्षा एक

मप्र की मोहन सरकार सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली चयन परीक्षा में बड़ा परिवर्तन करने जा रही है। जिसके तहत प्रदेश में होने वाली भर्ती परीक्षाएं बार-बार नहीं देनी पड़ेंगी। जानकारी के अनुसार जिस तरह यूपीएससी की एक परीक्षा होती है और उसमें प्राप्तांक और इंटरव्यू के आधार पर विभिन्न पदों पर सिलेक्शन होता है, अब मप्र में भी उसी आधार पर नौकरियां मिलेंगी। यानि राज्य लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से होने वाली भर्ती परीक्षाएं अब बार-बार नहीं होंगी। संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर वर्ष में एक बार परीक्षा होगी और सभी श्रेणी के पदों के लिए मेरिट के हिसाब से सूची बन जाएगी। यानि भर्तियां भले ही अनेक रहें, लेकिन परीक्षार्थी को परीक्षा एक ही देनी होगी।

प्रतीक्षा सूची भी एक ही रहेगी। इसके लिए पदों की संख्या सभी विभागों से वर्ष में एक बार पूछ ली जाएंगी और उसके आधार पर सितंबर में कैलेंडर निर्धारित हो जाएगा। जनवरी 2026 से चयन की यह प्रक्रिया लागू करने की तैयारी में सामान्य प्रशासन विभाग जुटा है। प्रदेश में द्वितीय और कार्यपालिक तृतीय श्रेणी के पदों की भर्ती राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से होती है तो तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के लिए कर्मचारी चयन मंडल परीक्षाएं कराता है। अभी जैसे-जैसे विभागों की ओर से पद उपलब्ध होते हैं, वैसे-वैसे भर्ती वाली ये दोनों एजेंसियां अपने कैलेंडर के हिसाब से परीक्षाएं कराती हैं। इसमें न केवल समय लगता है बल्कि अभ्यर्थियों को बार-बार फीस देनी पड़ती है तो एजेंसियों को परीक्षाएं आयोजित करने के लिए मानव संसाधन से लेकर अन्य व्यवस्थाएं करनी होती हैं। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भर्ती परीक्षाओं की व्यवस्था को परिवर्तित करने के निर्देश दिए थे। इसके अनुरूप सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन मंडल के परीक्षा के साथ विभागीय भर्ती नियम सहित अन्य प्रक्रियाओं में परिवर्तन का खाका तैयार किया है। सूत्रों के अनुसार, जिस तरह संघ लोक सेवा आयोग एक परीक्षा कराता है और विभिन्न श्रेणी के उपलब्ध पदों के लिए मेरिट के हिसाब से चयन हो जाएगा।

विभागीय अधिकारियों का कहना है कि अभ्यर्थियों से आवेदन के समय विकल्प मांगे जाते, मेरिट के हिसाब से यदि उसका चयन दो पदों के लिए हो गया, तो उसे कॉल लेटर भी भेज दिया और वह जिस पद का चयन करता है तो दूसरा पद प्रतीक्षा सूची वाले को मिल जाएगा। प्रतीक्षा सूची एक बार बनाई जाएगी और उसमें ही पद उपलब्ध होने पर चयनित अभ्यर्थी को मौका मिलता रहेगा। दरअसल, अभ्यर्थी एक साथ कई परीक्षाएं देते हैं और अलग-अलग स्थान पर चयन होने पर वे अपनी इच्छा के अनुसार सेवा का चयन करते हैं। ऐसे में पद रिक्त हो जाता है।

सूत्रों का कहना है कि पारदर्शिता के लिए नियम से लेकर परीक्षा का पूरा ब्यौरा ऑनलाइन रहेगा। अभी राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से होने वाली परीक्षा में कई चीजें सार्वजनिक नहीं की जाती हैं, जिससे अभ्यर्थी कोर्ट चले जाते हैं। परीक्षा परिणाम या चयन सूची पर रोक लगा जाती है। इससे पूरी प्रक्रिया रुक जाती है। आगे ऐसा न हो, इसके लिए सभी जानकारियां ऑनलाइन की जाएंगी ताकि किसी को सूचना के अभाव में कोई भ्रम या संदेह ना रहे। विभागों के भर्ती नियम भी अब एक जैसे होंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ही इन्हें बनाकर अधिसूचित करने के लिए देगा। यह व्यवस्था इसलिए की जा रही है ताकि एकरूपता रहे। इसमें समान प्रकृति के पदों के लिए एक जैसे नियम हो जाएंगे। साथ ही यह लाभ भी होगा कि परीक्षा कराने वाली एजेंसियों को **विज्ञापन** निकालते समय विभागीय भर्ती नियम के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा और समय पर विज्ञापन जारी हो जाएंगे।

प्रदेश में आगामी दो-तीन साल में दो से ढाई लाख सरकारी पदों पर भर्तियां होनी हैं। इसमें रिक्त पदों के साथ पदोन्नति होने पर खाली होने वाले पद भी शामिल हैं। ये सभी पद समयसीमा में भर जाएं, इसके लिए चयन प्रक्रिया में व्यापक परिवर्तन किया जा रहा है। सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे का कहना है कि मुख्यमंत्री की मंशा है कि परीक्षाएं समय पर और पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए। विवाद की स्थिति ही नहीं बननी चाहिए और अभ्यर्थी को बार-बार परीक्षा भी ना देनी पड़े। इसके लिए नियमों में संशोधन करके पूरी व्यवस्था में ही परिवर्तन किया जा रहा है। प्रयास यह है कि सितंबर तक यह प्रक्रिया पूरी करके जनवरी 2026 से लागू कर दी जाए।

● रजनीकांत पारे

सामान्य प्रशासन विभाग को मिली जिम्मेदारी

मप्र के सभी विभागों में कर्मचारियों की भर्ती के नियम समान करने की तैयारी है। इसके लिए आदर्श भर्ती नियमावली बनाई जा रही है। शासन ने इसकी जिम्मेदारी सामान्य प्रशासन विभाग को दी है। इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों से इस बारे में सुझाव मांगे हैं। दरअसल, प्रदेश में विभिन्न विभागों में अगले दो-तीन साल में करीब ढाई लाख पदों पर भर्तियां होनी हैं। इसके लिए ही सभी विभागों के भर्ती नियम एक जैसे करने का निर्णय लिया गया है, ताकि कोई नियमसंगत समस्या खड़ी न हो। ऐसा इसलिए, क्योंकि अब तक कई विभागों में भर्ती के कुछ नियमों में भिन्नता है। मसलन, वन विभाग, शिक्षा विभाग और नगर तथा ग्राम निवेश सेवा भर्ती के कुछ नियम अलग-अलग हैं। इनके आधार पर राज्य लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन मंडल भर्ती नियम तैयार करके अलग-अलग विज्ञापन निकालते हैं। नियम अलग होने से इन चयन एजेंसियों को विभागवार भर्ती करने में परेशानी होती है और समय भी अधिक लगता है। चूंकि, अब प्रदेश में बड़े पैमाने पर भर्तियां होनी हैं, इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि सभी विभागों के भर्ती नियमों में एकरूपता रहे ताकि भर्ती विज्ञापन जारी करने में विलंब न हो। एक जैसी प्रकृति के विभागों के लिए भर्ती एक साथ करवा दी जाएंगी।

मप्र में जल जीवन मिशन में गड़बड़ी

मप्र के 51 हजार से अधिक गांवों में हर घर को नल से जल उपलब्ध कराने वाली जल जीवन मिशन योजना में बड़े स्तर पर गड़बड़ी और फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है। इस गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस और भाजपा दोनों के विधायक आवाज उठा रहे हैं। मामला विधानसभा में भी उठ चुका है। इसी कड़ी में जल जीवन मिशन में बड़े स्तर पर गड़बड़ी सामने आई है। जानकारी के अनुसार अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से गड़बड़ी की गई है। इसके तहत फर्जी बैंक गारंटी से लगातार अरबों रुपए के प्रोजेक्ट लिए गए हैं।

मिली जानकारी के अनुसार जल जीवन मिशन में योजना पर अमल की जिम्मेदारी संभाल रहे मप्र जल निगम में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। यहां 311 करोड़ रुपए फर्जी बैंक गारंटी लगाकर कंपनियों ने अरबों के प्रोजेक्ट हासिल कर लिए। बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से यह फर्जीवाड़ा किया। जल निगम के अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं लगी, जबकि बैंक प्रबंधन ने डेढ़ साल पहले ही यह फर्जीवाड़ा पकड़ लिया था। निगम को इसकी जानकारी अब दी। मप्र जल निगम के एमडी वीएस चौधरी कोलसानी का कहना है कि 6 फर्जी बैंक गारंटी का मामला सामने आया है। दोनों ठेकेदारों को टर्मिनेशन लेटर जारी कर रहे हैं।

जल जीवन मिशन में हुई इस गड़बड़ी का मामला मुख्य सचिव तक पहुंच गया है। मुख्य सचिव की नाराजगी के बाद ईओडब्ल्यू में आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई गई है। बताया जा रहा है एक-दो दिन में ठेकेदार कंपनियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है। पीएचई के साथ जल निगम मिशन को अमलीजामा पहना रहा है। बताया जा रहा है कि निगम के पास ही 30 हजार करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट हैं। इनको निजी ठेकेदारों की मदद से किया जा रहा है। सामान्य तौर पर किसी विभाग में कार्य के लिए जब ठेकेदार परफॉर्मेंस गारंटी के तौर पर बैंक गारंटी लगाता है, तो इसका सत्यापन कराना संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी होती है। वह किसी अधिकारी या कर्मचारी को भेजकर बैंक प्रबंधन से इसकी पुष्टि कराता है। बताया जा रहा है कि जल निगम के अधिकारियों ने बैंक को ई-मेल भेज कर पुष्टि चाही थी। फर्जीवाड़े में शामिल बैंक अफसरों ने इसका सत्यापन भी कर दिया और ठेकेदार कंपनियों ने काम शुरू कर दिया।

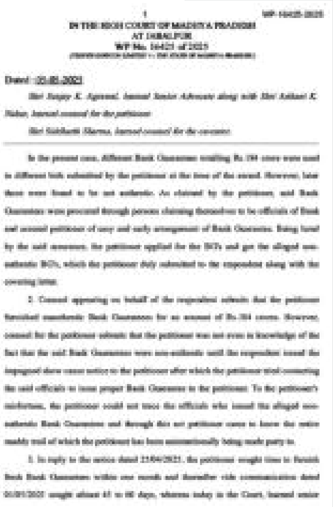

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH
AT JABALPUR

निजी कंपनियों के इंजीनियरों को पास करनी होगी परीक्षा

मप्र में जल जीवन मिशन योजना में पारदर्शिता लाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब प्राइवेट कंपनियों के माध्यम से काम करने वाले इंजीनियरों को परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा। इसको लेकर जल निगम के एमडी केवीएस चौधरी ने एमपी ऑनलाइन से परीक्षा कराने का आग्रह किया है। दरसअल प्रदेशभर में जल जीवन मिशन के मॉनिटरिंग का काम निजी कंपनी द्वारा करवाया जा रहा है। इसमें करीब 2000 से ज्यादा इंजीनियर काम करते हैं। इन इंजीनियरों की भर्ती निजी कंपनियां करती हैं और साक्षात्कार जल निगम के अधिकारी लेते हैं। लेकिन लगातार आरोप लगाते हैं कि अनस्किल्ड लोगों की भर्ती की जा रही है। इस तरह की शिकायत से उबरने के लिए एमडी ने नई रणनीति तैयार की है और एमपी ऑनलाइन से परीक्षा करने का निर्णय लिया है। जल निगम के एमडी केवीएस चौधरी ने बताया कि यह परीक्षा विभाग में पारदर्शिता लाने के लिए की जा रही है। कई जगह से शिकायत आ रही है कि इंजीनियरों की भर्ती में लापरवाही की जा रही है।

सूत्रों के मुताबिक शुरुआती जांच में दो ठेकेदार कंपनियों के नाम सामने आए हैं। इनमें तीरथ गोपीकॉन लिमिटेड और एमपी बावरिया लिमिटेड-अंकित कंस्ट्रक्शन के संयुक्त उपक्रम का नाम शामिल है। इनको करीब दो साल पहले पेयजल योजनाओं का जिम्मा सौंपा गया था। इसके एवज में उन्हें कुल लागत की 10 फीसदी राशि परफॉर्मेंस बैंक गारंटी और मोबिलाइजेशन एडवांस के लिए गारंटी जमा की थी। इसके आधार पर निगम ने ठेकेदार से करार कर लिया। बताया जा रहा है इन दो ठेकेदार कंपनियों ने काम लेने के लिए फर्जी बैंक गारंटी लगा दी। इसकी भनक संबंधित अधिकारियों को नहीं लगी। बैंकों को शक हुआ तो उन्होंने जांच कराई और नवंबर 2023 में ही इसका खुलासा हो गया। इसके बाद बैंक ने अपने अफसरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी, लेकिन जल निगम को अप्रैल 2025 में इसकी जानकारी दी।

गौरतलब है कि जल जीवन मिशन की गड़बड़ियां लगातार उजागर हो रही हैं। केंद्र की एक रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि जिन गांवों में एक भी नल नहीं लगा, वहां मिशन के तहत काम पूरा होना दिखा दिया गया है। वहीं, जिन गांवों में इस मिशन के तहत पानी सप्लाई हो रहा है, उनमें से कई जगह पीने का पानी साफ नहीं है। दरअसल, 2024 में भी मिशन का काम पूरा होता न देखकर केंद्र ने जुलाई में इसकी जमीनी स्तर पर जांच कराई। इसके लिए एक निजी एजेंसी को मप्र के 1,271 सर्टिफाइड गांवों में हुए कार्यों की जांच का जिम्मा सौंपा गया। जांच में केवल 209 गांवों में सभी जरूरी मानक पूरे पाए गए। वहीं, 217 गांवों में नल कनेक्शन तो हुए, लेकिन पानी की सप्लाई नहीं हो रही है।

● सुनील सिंह

फॉर्मूला-16 कैबिनेट में जाएगा

मप्र में 9 साल से कर्मचारियों के प्रमोशन लंबित हैं। इस मसले को सुलझाने में जुटी मोहन यादव सरकार ने प्रमोशन के लिए फॉर्मूला-16 बनाया है। दरअसल, प्रदेश में 2016 से प्रमोशन पर ब्रेक लगा है। इसलिए इसे फॉर्मूला-16 नाम दिया गया है। गत दिनों सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) के अफसरों ने मुख्यमंत्री को प्रमोशन के फॉर्मूले की जानकारी दी। लेकिन फिलहाल इसके क्रियान्वयन पर अंतिम निर्णय नहीं हो सका है। मुख्यमंत्री ने जीएडी अफसरों के फॉर्मूले पर कुछ सुझाव देकर उसके आधार पर प्रस्ताव तैयार करने को कहा है। इसके चलते इस पर अंतिम फैसला टल गया है। दूसरी ओर जीएडी के प्रस्ताव में कर्मचारी संगठनों का विरोध आड़े आ रहा है।

कर्मचारी संगठन सरकार के प्रस्तावित प्रमोशन फॉर्मूले का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर वर्ष 2016 से 2024 तक की डीपीसी अलग-अलग नहीं की गई और प्रत्येक संवर्ग में वर्टिकल आरक्षण नहीं रखा गया, तो फिर सभी वर्ग के साथ न्याय नहीं हो पाएगा। कर्मचारियों के इसी विरोध के चलते जीएडी के प्रस्ताव को फाइनल नहीं किया जा सका है। मुख्यमंत्री ने इसको लेकर मुख्यमंत्री निवास के समत्व भवन में मीटिंग बुलाई और अफसरों से पूरा मामला समझा। अफसरों ने प्रमोशन फॉर्मूले का प्रजेंटेशन दिया। लेकिन सभी तथ्यों को देखते हुए इस पर अंतिम राय नहीं बन सकी। सरकार एक बार में ही प्रमोशन देकर कर्मचारियों को खुश करना चाहती है और अपना वित्तीय संतुलन भी बनाए रखना चाहती है। जबकि साल दर साल प्रमोशन दिए जाने पर सरकार पर आर्थिक बोझ बढ़ना तय माना जा रहा है। इसके चलते यह मामला फिर दो से तीन हफ्ते के लिए लटक गया है।

सरकार द्वारा एक माह पहले प्रमोशन देने की तैयारी शुरू करने के लिए जो फॉर्मूला तय किया गया था, उसे लेकर मंत्रालय सेवा अधिकारी कर्मचारी संघ ने विरोध जताया था। कर्मचारियों ने मुख्य सचिव, एसीएस मुख्यमंत्री कार्यालय, सामान्य प्रशासन और प्रमुख सचिव वित्त को ज्ञापन सौंपा था। इसमें 9 सालों की अलग-अलग पदोन्नति कराने की बात कही गई। कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुधीर नायक ने कहा है कि पदोन्नति प्रक्रिया में पात्र शासकीय सेवकों को केवल एक पदोन्नति का ही लाभ दिए जाने का प्रावधान किया जा रहा है। पदोन्नति में हर संवर्ग में वर्टिकल आरक्षण का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। संघ की शुरू से यह मांग है कि पदोन्नति के हर संवर्ग में 16 प्रतिशत एससी, 20 प्रतिशत एसटी और हर संवर्ग में शेष सभी पदों पर अनारक्षित वर्ग को पदोन्नति दी जानी चाहिए। अधिकारी वर्ग इस तरह का पदोन्नति प्रस्ताव तैयार नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं करने पर आंदोलन की स्थिति बनना तय है।

इंदौर की कैबिनेट में आएगा मेट्रोपॉलिटन रीजन का प्रस्ताव

राजवाड़ा में आयोजित होने वाली कैबिनेट बैठक की तैयारी जहां जोर-शोर से चल रही है, तो दूसरी तरफ नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के साथ नगर तथा ग्राम निवेश इंदौर-भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन के ड्राफ्ट को तैयार करने में जुटे हैं और यह भी चर्चा है कि इंदौर में आयोजित होने वाली कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री के समक्ष इस ड्राफ्ट का प्रजेंटेशन दिया जाएगा और उसी के साथ उसे मंजूरी भी मिल सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशा है कि मेट्रोपॉलिटन रीजन पर जल्द से जल्द अमल हो सके। दोनों मेट्रोपॉलिटन रीजन में 5-5 जिलों को शामिल किया गया है और इसके लिए कई राज्यों का अध्ययन भी अधिकारियों ने किया। महाराष्ट्र, हरियाणा, तेलंगाना, दिल्ली के मेट्रोपॉलिटन एक्ट को भी देखा-समझा जा रहा है, साथ ही जो मेट्रोपॉलिटन रीजन पहली बार प्रदेश में अमल में लाया जाएगा, उसमें अथॉरिटी के अध्यक्ष तो मुख्यमंत्री ही रहेंगे, वहीं अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आला अधिकारी को सौंपी जाएगी, ताकि सभी विभागों में सामंजस्य आसानी से हो सके। इंदौर रीजन में संपूर्ण जिले को तो शामिल किया ही है, वहीं देवास, उज्जैन, धार और शाजापुर को भी लिया गया है। पिछले दिनों प्राधिकरण बोर्ड ने मेट्रोपॉलिटन रीजन को लेकर तैयार प्रतिवेदन शासन को भेज दिया था।

... ताकि कैबिनेट हो सके

प्रदेश में हर सप्ताह के मंगलवार को कैबिनेट की बैठक होना सुनिश्चित किया गया है। अगर देखा जाए तो कुछ अपवादों को छोड़कर हर मंगलवार को कैबिनेट की बैठक की जा रही है। ऐसे में कैबिनेट के लिए विषय ढूंढना भी अफसरों के लिए बड़ी चुनौती हो गया है। सूत्रों का कहना है कि लगभग सभी विभागों के उच्च पदस्थ अधिकारियों को यह काम सौंप दिया गया है कि वे कैबिनेट के लिए विषय ढूंढते रहें। बताया जाता है कि अफसर सप्ताह भर इसी काम में लगे रहते हैं कि अगली कैबिनेट बैठक के लिए कौनसा ऐसा प्रस्ताव तैयार किया जाए, जिस पर मंत्रिमंडल के सदस्य चर्चा कर सकें। जानकारों का कहना है कि कभी-कभी तो ऐसे प्रस्ताव भी कैबिनेट में आ जाते हैं जो सरकार की प्राथमिकता में नहीं रहते हैं। इस संदर्भ में अफसरों का कहना है कि सरकार के निर्देशों का पालन करने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही है। गौरतलब है कि सरकार ने कैबिनेट में कई बड़े फैसलों को मंजूरी दे दी है, लेकिन अभी भी वे फैसले अधर में लटके हुए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार सरकार कैबिनेट में बेवजह के मुद्दों पर चर्चा का समय क्यों गवाती है। वहीं अफसरों का अधिकांश समय भी मुद्दों की पड़ताल में बीत जाता है।

एक को प्रभार...बाकी को भूल गई सरकार

करीब पांच महीने पहले यानी नए साल पर सरकार ने चार आईपीएस अधिकारियों को प्रमोशन का तोहफा दिया था। लेकिन उनमें से एक अधिकारी को प्रमोशन का मान मिला है, जबकि तीन यथावत हैं। गौरतलब है कि 31 दिसंबर को गृह विभाग ने चार उप पुलिस महानिरीक्षकों को पुलिस महानिरीक्षक के पद पर प्रमोट किया गया था। प्रमोशन देने के साथ ही यह निर्देश भी दिया गया था कि उनकी पदस्थापना यथावत रहेगी। तबसे वे अफसर उसी जगह जमे हुए हैं। लेकिन पांच माह बाद भी स्थिति यह है कि इनमें से एक अफसर को आईजी का प्रभार मिला है। जबकि तीन आईजी बन जाने के बाद भी डीआईजी का काम कर रहे हैं। यही नहीं उन्हें अभी भी अपने रेंज के आईजी को रिपोर्टिंग करनी पड़ रही है। इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार सरकार ने उन्हें प्रमोशन क्यों दिया।

दरअसल, नए साल से ठीक एक दिन पहले 31 दिसंबर को गृह विभाग ने चार डीआईजी को आईजी के पद पर प्रमोट किया। इनमें छिंदवाड़ा रेंज के डीआईजी सचिन कुमार अतुलकर, चंबल रेंज के डीआईजी कुमार सौरभ, और विशेष सशस्त्र बल की डीआईजी कृष्णावेनी देसावतु और योजना पुलिस मुख्यालय के डीआईजी जगत सिंह राजपूत को आईजी बनाया गया। इनमें से केवल सचिन कुमार अतुलकर को आईजी का प्रभार दिया गया है, जबकि अन्य तीन आईजी तो बन गए हैं लेकिन अब भी रेंज के आईजी के अंडर में ही काम करना पड़ रहा है। ये अफसर महीनों से तबादले का इंतजार कर रहे हैं, ताकि पद के अनुसार उन्हें काम करने को मिले। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर क्या वजह है कि सरकार ने अभी तक इन्हें दूसरी जगह पदस्थ क्यों नहीं किया।

मनमर्जी से दिया पदभार

अभी हाल ही में प्रदेश में इंस्पेक्टर से डीएसपी बनाए गए अफसरों को मनमानी पोस्टिंग देने का मामला सामने आया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस पोस्टिंग में मंत्रियों का तनिक भी ध्यान नहीं रखा गया। हालांकि अभी सूची जारी नहीं हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि मंत्रियों से सलाह लिए बिना ही उनके जिले में नए डीएसपी की पदस्थापना करने की सूची बना ली गई है। बताया जाता है कि इसकी शिकायत ऊपर तक पहुंची तो मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी असमंजस में फंस गए। बताया जाता है कि उन्होंने इस पर घोर आपत्ति जताई। यही नहीं गत दिनों गृह विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने यह मुद्दा भी उठाया और विभाग के बड़े साहब की जमकर क्लास लगाई। सूत्र बताते हैं कि उन्होंने यहां तक कह दिया कि सरकार के निर्देशों की ऐसी अवहेलना अब नहीं होनी चाहिए। जब भी जिलों में पदस्थापना की जाए इसके लिए मंत्रियों से जरूर पूछा जाए। दरअसल, सरकार के निर्देश हैं कि जिलों में पोस्टिंग प्रभारी मंत्रियों और विधायकों से सलाह लेकर की जाए। अब देखना यह है कि जो सूची तैयार की गई है, उसमें किस हद तक बदलाव किया जाता है और अधिकारी सरकार के निर्देशों का कितना पालन कर पाते हैं।

मंत्री की नहीं सुनते अफसर

मप्र में एक तरफ सरकार सुशासन पर जोर दे रही है, दूसरी तरफ स्थिति यह है कि प्रदेश के ब्यूरोक्रेट्स मंत्रियों की सुन ही नहीं रहे हैं। मंत्रालयीन सूत्रों का कहना है कि अधिकांश अफसर आलाकमान के नजदीक हैं। इसलिए उनका पूरा फोकस आलाकमान को खुश करने में लगा रहता है। इसकी शिकायत मिलने के बाद भी सरकार ने इस दिशा में कोई कोशिश नहीं की है। पूर्व मुख्यमंत्री के कार्यकाल में भी ऐसी स्थिति बनती थी तो खुद पूर्व मुख्यमंत्री मामला संभालते थे और अधिकारियों को निर्देश देते थे कि मंत्रियों की सुनो और उनसे समन्वय बिठाकर रखो।

ई-ऑफिस का मजा

मंत्रालय सहित अधिकांश कार्यालयों में ई-ऑफिस सिस्टम लागू हो गया है। इसका फायदा यह हो गया है कि कई विभागों में पदस्थ आईएएस अब अपने कार्यालय में अपनी जगह पर कम बैठ रहे हैं। विंध्याचल और सतपुड़ा भवन में तो स्थिति यह है कि एचओडी पहली पाली में ऑफिस तो आते हैं, लेकिन दूसरे पाली में गायब हो जाते हैं। बताया जाता है कि ई-ऑफिस होने के कारण वे घर पर या फिर इधर-उधर कहीं भी बैठकर ऑनलाईन काम करते रहते हैं। हालांकि मंत्रालय में अफसरों का आना मजबूरी हो गया है। क्योंकि प्रशासनिक मुखिया खुद समय से मंत्रालय आते हैं और जाते हैं। ऐसे में मंत्रालय में बैठने वाले अफसर पूरे समय काम में लगे रहते हैं।

● राजेंद्र आगाल

कलेक्टर मैडम की चालाकी... प्रमुख सचिव असमंजस में

किसी भी जिले के कलेक्टर के पास वह सारे अधिकार होते हैं, जिसका उपयोग कर वह प्रशासनिक फैसले ले सकता है। लेकिन देखा यह जा रहा है कि अधिकांश अफसर इस कोशिश में रहते हैं कि कोई भी कदम उठाया जाए तो उससे उन पर आंच न आए। इसी तरह का मामला खरगोन जिले में सामने आया है। यहां पर 2014 बैच की आईएएस अधिकारी भव्या मित्तल कलेक्टर हैं। मैडम के पास एक शिकायत पहुंची है कि 2016 में कर्मचारी चयन मंडल द्वारा समूह-4 हेतु आयोजित संयुक्त परीक्षा में सहायक ग्रेड-3 के पद पर चयनित अभ्यार्थियों में से 7 ने सीपीसीटी परीक्षा पास नहीं की है, फिर भी वे नौकरी कर रहे हैं। इस मामले को मैडम ने गंभीरता से लिया। लेकिन स्वयं इस मामले की जांच करने और दोषियों पर कार्यवाही करने की जगह उन्होंने प्रमुख सचिव राजस्व विभाग को पत्र लिखकर प्रकरण में शासन स्तर से मार्गदर्शन प्राप्त कर नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए मार्गदर्शन मांग डाला। जानकारों का कहना है कि जिला कलेक्टर के पास स्वयं यह अधिकार होता है कि वह ऐसे मामलों में खुद फैसले ले सकता है। लेकिन कलेक्टर भव्या मित्तल ने अपने आप को इस मामले से अलग करते हुए प्रमुख सचिव से मार्गदर्शन की मांग कर डाली है। दरअसल, देखा यह जा रहा है कि अधिकांश अफसर छोटी-छोटी बात पर अपने वरिष्ठ अफसरों से मार्गदर्शन मांगते हैं ताकि अगर उक्त मामले में कोई कार्यवाही होती है तो उन पर आंच न आए। इसका परिणाम यह हो रहा है कि कई गलत मामले आज भी अधर में लटके हुए हैं।

मान्यता का खेल, कायदे-कानून फेल

मान्यता मिलने की प्रक्रिया कड़ी, फिर भी लगा दी सेंध

नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए ऑफलाइन व्यवस्था बंद है। आवेदन ऑनलाइन होता है। दस्तावेज ऑनलाइन जमा होते हैं। हार्डकॉपी भी ली जाती है, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है। आवेदनों की स्क्रूटनी के बाद टीम कॉलेज का भौतिक निरीक्षण करती है। टीम में राज्य स्तर से नर्सिंग काउंसिल या चिकित्सा शिक्षा के सदस्य व स्थानीय सदस्य होते हैं। कलेक्टर के प्रतिनिधि भी होते हैं। टीम में 3 लोग होते हैं, यह संख्या बढ़ सकती है। कॉलेज तय मापदंडों पर दस्तावेज देते हैं। टीम स्थानीय स्तर पर अस्पताल की भौतिक जांच कर सत्यापित रिपोर्ट देती है। भवन-जमीन, कर्मी, संसाधन व अन्य मानक देखे जाते हैं। निरीक्षण में मापदंड पर खरे उतरे कॉलेजों की अनुशंसा होती है। रिपोर्ट नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रार को देते हैं। कार्यकारिणी बैठक में मंजूरी मिलती है। फिर मान्यता मिलती है। काउंसिल कार्यकारिणी या रजिस्ट्रार स्तर पर खामी पकड़ी गई तो मंजूरी नहीं मिलती। छोटी कमियां दूर करने का वक्त देते हैं। नर्सिंग काउंसिल से मंजूरी के बाद मान्यता सूची जारी की जाती है। चिकित्सा शिक्षा विभाग को भी सूची भेजी जाती है। डीएमई नर्सिंग काउंसिल में रहते हैं, इसलिए उनकी मंजूरी भी लगती है। पहले वे नर्सिंग काउंसिल के प्रमुख होते थे, अब अलग से नर्सिंग काउंलिस के प्रभारी बनाए गए हैं। यदि किसी कॉलेज की मान्यता प्रक्रिया के बीच या मान्यता मिलने के बाद शिकायत आने पर जांच होती है। शिकायत डीएमई या उसके ऊपर के अधिकारी के पास आए तो काउंसिल जांच कर उन्हें भी रिपोर्ट देती है। यदि काउंसिल के स्तर पर ही शिकायत हुई तो रजिस्ट्रार स्तर तक ही फाइल जाती है।

मप्र में नर्सिंग शिक्षण संस्थाओं की मान्यता को लेकर ऐसा खेल खेला जा रहा है, जिसमें कायदे-कानून ताक पर रखे जा रहे हैं। मान्यता की कसौटी पर खरे न उतरने वाले नर्सिंग कॉलेजों को हर स्तर पर अफसरों ने खुली छूट दी। कॉलेजों की जांच के लिए राज्य व स्थानीय स्तर के साथ नर्सिंग काउंसिल के तीन मुख्य चेक प्वाइंट बने हैं। लेकिन तीनों स्तर पर अफसरों का ऐसा गठजोड़ रहा कि सब जानते हुए भी वे आंखें मूंदे रहे। नतीजा, नर्सिंग कॉलेज घोटाला हो गया। जिम्मेदारों ने हजारों विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ किया। कहने को सरकार ने पारदर्शिता के लिए ऑफलाइन व्यवस्था खत्म कर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अपनाई। फिर स्क्रूटनी और भौतिक सत्यापन के लिए बनी टीम में राज्य से लेकर स्थानीय स्तर तक सदस्य रखे। फिर भी नर्सिंग काउंसिल ने बिना भवन, शिक्षक और अस्पताल के कॉलेजों को मान्यता दी।

सवाल है कि आखिर किस स्तर पर चूक हुई। भौतिक सत्यापन करने वाली टीम ने काउंसिल को गलत रिपोर्ट दी या फिर काउंसिल ने सब जानते हुए नियम ताक पर रखकर मान्यता दी। इतना ही नहीं, काउंसिल की मान्यता के बाद डायरेक्ट्रेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन ने कैसे अपनी मुहर लगा दी। यही नहीं घोटाले की जांच कर रही सीबीआई टीम भी कॉलेज माफिया से गठजोड़ कर बैठी और अपनी रिपोर्ट में ही अनसूटेबल कॉलेजों को सूटेबल बता दिया। यानि नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देने में हर स्तर पर फर्जीवाड़ा किया गया है। गौरतलब है कि नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता देने के लिए एक टीम बनाई जाती है, जिसमें तहसीलदार और नायब तहसीलदार को भी रखा जाता है। ये जमीन संबंधी जानकारी देते हैं और टीप लिखते हैं। कई जगह यह देखने को मिला है कि इनके द्वारा टीप में लिखा गया है कि उक्त कॉलेज मान्यता के लिए सूटेबल नहीं हैं, फिर भी उसे मान्यता दे दी गई। ऐसे में जब फर्जीवाड़ा सामने आया तो आनन-फानन में राजस्व विभाग ने नर्सिंग कॉलेजों की रिपोर्ट देने वाले 14 नायब और तहसीलदारों को नोटिस दिया है। इन पर आरोप है कि जांच के लिए गठित निरीक्षण दल के सदस्य के रूप में गलत निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने में इन्होंने सहयोग किया है। इसके अलावा राजस्व विभाग के कुछ और कर्मचारियों के विरुद्ध भी एक्शन हो सकता है। साथ ही जांच से जुड़े अन्य विभागों के अफसरों की भूमिका की भी जांच की जा रही है ताकि कार्रवाई की जा सके। हैरानी की बात तो यह है कि जिन तहसीलदारों ने कॉलेजों के खिलाफ अनसूटेबल की रिपोर्ट दी थी, उन्हें भी मान्यता दे दी गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इनका दोष क्या है? जिन अधिकारियों को नोटिस जारी किए गए हैं, उसमें पल्लवी पौराणिक तत्कालीन तहसीलदार इंदौर, अंकिता यदुवंशी, तत्कालीन नायब तहसीलदार विदिशा, ज्योति ढोके तत्कालीन नायब तहसीलदार नर्मदापुरम्, रानू माल नायब तहसीलदार अलीराजपुर, अनिल बघेल नायब तहसीलदार झाबुआ, सुभाष कुमार सुनेरे तत्कालीन नायब तहसीलदार देवास, जगदीश बिलगावे नायब तहसीलदार बुरहानपुर, यतीश शुक्ला नायब तहसीलदार रीवा, छवि पंत तत्कालीन नायब तहसीलदार छिंदवाड़ा, सतेंद्र सिंह गुर्जर तत्कालीन नायब तहसीलदार जिला धार, रामलाल पगोर नायब तहसीलदार बुरहानपुर, जितेंद्र सोलंकी तत्कालीन नायब तहसीलदार झाबुआ, अतुल शर्मा तत्कालीन नायब तहसीलदार सीहोर एवं कृष्णा पटेल तत्कालीन नायब तहसीलदार खरगोन के नाम सम्मिलित हैं।

इन लोगों को भेजे गए नोटिस में लिखा गया है कि विगत वर्ष 2022-23 में उपरोक्तानुसार गठित विभिन्न दलों द्वारा प्रदेश के कई जिलों में स्थित नर्सिंग संस्थाओं का भौतिक निरीक्षण किया गया था। कुछ दलों द्वारा कुछ नर्सिंग संस्थाओं को निरीक्षण रिपोर्ट में सूटेबल रिमार्क दिया गया था एवं मान्यता हेतु अनुशंसा की गई थी। मप्र नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल द्वारा नियम विरुद्ध एवं त्रुटिपूर्ण दस्तावेजों के आधार पर नर्सिंग स्कूल-महाविद्यालयों को मान्यता प्रदाय किए जाने के संबंध में रिट याचिका क्रमांक 1080/2022 उच्च न्यायालय में प्रचलित है। इस संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा सीबीआई को जांच सौंपी गई है। नर्सिंग काउंसिल द्वारा गठित दलों द्वारा इस प्रकार सूटेबल प्रतिवेदित की गई संस्थाओं में से 66 संस्थाओं को सीबीआई जांच के आधार पर उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा उपरोक्त रिट याचिका पर पारित आदेश दिनांक 12.02.2024 से अनसूटेबल श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। इस दल, जिसमें आप भी उपरोक्तानुसार सदस्य थे, ने निरीक्षण रिपोर्ट में इस संस्था को सूटेबल दर्शाया गया था और मान्यता हेतु अनुशंसा की गई थी। इस संदर्भ में आप अपना स्पष्टीकरण दें।

● धर्मेंद्र कथूरिया

बदलेगा सिंचाई-व्यापार का नक्शा

मप्र और महाराष्ट्र के बीच वर्षों से चला आ रहा तापी बेसिन रिचार्ज परियोजना का विवाद समाप्त हो गया है। दोनों राज्यों ने इस पर सहमति जताते हुए आगे काम शुरू करने का निर्णय लिया है। 10 मई को मप्र-महाराष्ट्र अंतर्राज्यीय नियंत्रण मंडल की 28वीं बैठक का आयोजन किया गया। इसमें मप्र के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित रहे। दोनों मुख्यमंत्रियों ने बहुप्रतीक्षित तापी बेसिन ग्राउंड वॉटर रिचार्ज परियोजना के एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही विश्व कर सबसे बड़ी परियोजना पर मुहर लग गई। इस परियोजना से मप्र और महाराष्ट्र के किसानों को बहुत फायदा होगा। 20 हजार करोड़ की इस परियोजना से सिंचाई और व्यापार का नक्शा बदलेगा। वहीं पानी से खेत लबालब हो जाएंगे।

यह परियोजना दुनिया की सबसे बड़ी ग्राउंड वॉटर रिचार्ज परियोजनाओं में से एक मानी जा रही है। इससे भूजल स्तर सुधरेगा और सिंचाई बेहतर होगी। बता दें कि तापी बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना विश्व की सबसे बड़ी ग्राउंड रिचार्ज परियोजना है। इस परियोजना को राष्ट्रीय जल परियोजना घोषित कराने के लिए केंद्र सरकार से बात चल रही है। इस मेगा रिचार्ज परियोजना में 31.13 टीएमसी पानी का उपयोग होगा। इसमें से 11.76 टीएमसी मप्र को और 19.36 टीएमसी पानी महाराष्ट्र के हिस्से में आएगा। इस प्रोजेक्ट से मप्र के 1 लाख 23 हजार 82 हेक्टेयर और महाराष्ट्र के 2 लाख 34 हजार 706 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी। इससे मप्र के बुरहानपुर-खंडवा जिले की बुरहानपुर, नेपानगर, खकनार और खालवा की 4 तहसीले लाभांवित होंगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस एमओयू को दोनों राज्यों के बीच सहयोग का नया अध्याय बताया। परियोजना पर 20 हजार करोड़ रुपए की लागत आएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस परियोजना की 90 प्रतिशत लागत वहन करेगी। वहीं, दोनों राज्य 5-5 प्रतिशत राशि लगाएंगे। साथ ही यह भी बताया कि मप्र नदियों की भूमि है और यहां से निकलने वाली नदियों से कई राज्यों को लाभ मिलता है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का आभार जताते हुए कहा कि इस परियोजना की नींव उन्हीं के कार्यकाल में पड़ी थी। यह परियोजना तापी नदी के बाढ़ के पानी को दो चट्टानों के बीच स्थित 250 वर्ग किमी के प्राकृतिक बजाड़ा जोन में भूमिगत स्टोर करेगी। यह भू-वैज्ञानिक संरचना जल संरक्षण के लिए उपयुक्त मानी जाती है और इससे 50 किलोमीटर के दायरे में हर साल भूजल स्तर में लगभग 2 मीटर तक वृद्धि संभव होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि तापी बेसिन मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट प्राकृतिक है। पूरे विश्व में इससे अच्छा प्रोजेक्ट कहीं नहीं है। पानी की कमी से कई लोगों को कष्ट था। मुझे इस बात की खुशी है कि ये प्रोजेक्ट पूरे निमाड़ के लिए जीवन रेखा का काम करेगा। इससे भूजल स्तर सुधरेगा और सिंचाई बेहतर होगी। हम महाराष्ट्र से जुड़कर अपनी पुरानी विरासत को जीवित करेंगे। महाराष्ट्र बंदरगाहों से व्यापार बढ़ाएंगे। जबलपुर से नागपुर तक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जाएगा। इससे लागत में बचत होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश के महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर को नासिक के त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर और घृष्णेश्वर से जोड़कर धार्मिक पर्यटन का सर्किट बनाएंगे। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मैं महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के नागपुर से आता हूं। नागपुर पहले मध्य भारत की राजधानी रहा है। ऐसे में मप्र से मेरा आत्मीय संबंध है। फडणवीस ने कहा, मोहन यादव ने इस मामले में बहुत रुचि दिखाई और बड़ी तेजी के साथ यहां तक लेकर आए। तापी मेगा प्रोजेक्ट दुनिया का अजूबा है। हम जब साइट पर गए तो लगा कि एक गुप्त नदी आती है और पानी कुएं में जाता है। लगातार 24 घंटे तक पानी जाने के बावजूद भी कुएं का पानी ओवरफ्लो नहीं होता। इस प्रोजेक्ट से दोनों राज्यों को बड़ा फायदा होगा और इससे ओकाला, बुलढाणा, अमरावती की सूरत बदल जाएगी। किसानों का जीवन बदल जाएगा, साथ ही दोनों राज्यों की अर्थव्यवस्था को भी गति देगा। चार जल संरचनाएं प्रस्तावित हैं, जिनमें **खरिया गुटीघाट बांध स्थल पर लो डायवर्सन वियर:** यह वियर दोनों राज्यों की सीमा पर मप्र की खंडवा जिले की खालवा तहसील एवं महाराष्ट्र की अमरावती तहसील में प्रस्तावित है। इसकी जल भराव क्षमता 8.31 टीएमसी प्रस्तावित है। **दाईं तट नहर प्रथम चरण:** प्रस्तावित खरिया गुटीघाट वियर के दाएं तट से 221 किलोमीटर लंबी नहर प्रस्तावित है, जो मप्र में 110 किलोमीटर बनेगी। इस नहर से मप्र के 55 हजार 89 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी। **बाईं तट नहर प्रथम चरण:** प्रस्तावित खरिया गुटीघाट वियर के बाएं तट से 135.64 किलोमीटर लंबी नहर प्रस्तावित है जो मप्र में 100.42 किलोमीटर बनेगी। इस नहर से मप्र के 44 हजार 993 हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई प्रस्तावित है। **बाईं तट नहर द्वितीय चरण:** यह नहर बाईं तट नहर प्रथम चरण के आरडी 90.89 किमी से 14 किमी लंबी टनल के माध्यम से प्रवाहित होगी। इसकी लंबाई 123.97 किलोमीटर होगी।

● **प्रवीण सक्सेना**

तापी-बेसिन प्रोजेक्ट निमाड़ के लिए जीवन रेखा

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मप्र नदियों का मायका है। यहां से 247 से ज्यादा नदियां बहती हैं। हमारी नदियां देश के अन्य राज्यों की नदियों से जुड़ी हैं और उन्हें लाभ प्रदान कर रही हैं। तापी बेसिन मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट प्राकृतिक है। यह प्रोजेक्ट पूरे निमाड़ की जीवन रेखा के लिए काम करेगा। इससे भूजल स्तर सुधरेगा और सिंचाई बेहतर होगी। हम महाराष्ट्र से जुड़कर अपनी पुरानी विरासत को जीवित करेंगे। महाराष्ट्र के बंदरगाहों से व्यापार बढ़ाएंगे। जबलपुर से नागपुर तक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जाएगा। इससे लागत में बचत होगी। डॉ. मोहन ने कहा, प्रदेश के महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर को नासिक के त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर और घृष्णेश्वर से जोड़कर धार्मिक पर्यटन का सर्किट बनाएंगे। डॉ. मोहन यादव ने बीते वर्षों की असफलताओं पर टिप्पणी करने से परहेज करते हुए कहा कि अब दोनों राज्यों के बीच जल वितरण का संतुलित और व्यावहारिक समाधान निकलेगा। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग में संतुलन जरूरी है और इस दिशा में यह परियोजना एक मील का पत्थर साबित होगी।

मंत्रियों, विधायकों, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ जांच को लेकर सुर्खियों में रहने वाले लोकायुक्त संगठन को गोपनीयता के आवरण में इस कदर ढक दिया गया है कि संगठन क्या कर रहा है किसी को पता ही नहीं चलता। दरअसल, लोकायुक्त के अनुशंसाओं और प्रकरणों का क्या हुआ पता नहीं चल पाता है। इसकी वजह यह है कि लोकायुक्त संगठन के 9 वार्षिक प्रतिवेदन सामान्य प्रशासन विभाग को प्राप्त हो जाने के बाद भी विधानसभा में पटल पर नहीं रखे गए हैं। इनसे जुड़े विभागों से लोकायुक्त की अनुशंसाओं और प्रकरणों पर की गई कार्यवाही की जानकारी नहीं दी जा रही है इसलिए ये विधानसभा में पेश नहीं हो पाए हैं।

लोकायुक्त का 33वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 सामान्य प्रशासन विभाग को फरवरी 2023 में प्राप्त हो गया था। 35वां प्रतिवेदन भी इसी अवधि में प्राप्त हो चुका है। 36वां प्रतिवेदन 2019 में, 37वां प्रतिवेदन 2020 में, 38वां प्रतिवेदन 22 में और 39वां, 40वां और 41वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023 में आ चुके हैं लेकिन इन्हें विधानसभा में पटलित नहीं किया गया है। इन प्रतिवेदनों पर संबंधित विभागों से प्रतिवेदन में उल्लेखित अनुशंसाओं और महत्वपूर्ण प्रकरणों पर की गई कार्यवाही की जानकारी प्राप्त की जाती है। विभागों से यह जानकारी नहीं प्राप्त हो पाई इसलिए ये प्रतिवेदन पटल पर नहीं आ पाए हैं। विभाग जैसे ही जानकारी देंगे ये प्रतिवेदन पटल पर आ जाएंगे।

गौरतलब है कि मप्र में लोकायुक्त संगठन भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार अभियान चला रहा है। वहीं संगठन में लगातार भ्रष्टाचार की शिकायतें भी पहुंच रही हैं। वहीं सरकार भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात तो करती है पर वह विभागों की कार्यप्रणाली में नजर नहीं आता। इसका सबसे बड़ा उदाहरण लोकायुक्त संगठन की अनुशंसा रिपोर्ट है, जो प्रतिवर्ष राज्यपाल और सरकार को प्रस्तुत तो की जा रही है, लेकिन इसे विधानसभा के पटल पर ही नहीं रखा जा रहा। जबकि, सरकार को संगठन की अनुशंसाओं पर अमल करके रिपोर्ट सदन के पटल पर रखनी होती है। रिपोर्ट सामने नहीं आने से यह पता नहीं चल रहा है कि किस मामले में सरकार ने क्या कार्रवाई की है। इसमें अभियोजन स्वीकृति के प्रकरण भी शामिल होते हैं। दिसंबर 2024 में परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा की 100 करोड़ रुपए से अधिक की काली कमाई का मामला उजागर हुआ। कांग्रेस ने मामले में सरकार को जमकर घेरा। विधानसभा के बजट सत्र में यह मुद्दा छाया रहा। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के विरुद्ध लोकायुक्त संगठन में शिकायत की। कांग्रेस विधानसभा में भी लोकायुक्त का प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किए जाने का मुद्दा उठाती रही है। ऐसे में माना जा रहा था कि सरकार बजट सत्र में लोकायुक्त का प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकती है, पर नहीं किया। आज स्थिति यह है कि लोकायुक्त में दर्ज प्रकरणों में से 284 और आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में दर्ज प्रकरणों में से 30 में अभियोजन की स्वीकृति ही नहीं मिली है। लोकायुक्त में अभियोजन स्वीकृति के लिए लंबित प्रकरणों में से अकेले 25 पूर्व आईएएस अधिकारी रमेश थेटे के हैं। बता दें, लोकायुक्त की रिपोर्ट में अधिकारियों-कर्मचारियों के विरुद्ध दर्ज प्रकरणों की विभागवार जानकारी, वर्षवार विवरण, अभियोजन और सजा की स्थिति, स्वीकृत और पदस्थ स्टाफ की जानकारी रहती है। इस रिपोर्ट पर सरकार कार्रवाई करती है।

राज्य सरकार भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, पर अभी भी विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त में दर्ज प्रकरणों में आरोपित 180 अधिकारी-कर्मचारियों के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति के मामले संबंधित विभागों में लंबित हैं। इनमें कुछ आईएएस अधिकारी भी शामिल हैं। नियमानुसार यदि किसी प्रकरण में विधिक सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है या अन्य कोई समस्या नहीं है तो प्रकरण प्राप्त होने के 45 दिन के भीतर अभियोजन की स्वीकृति मिल जानी चाहिए, पर ऐसा नहीं हो रहा है। अभियोजन स्वीकृति के लिए लंबित मामलों की निगरानी और निराकरण के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में समिति बनी हुई है। इसके बाद कई अधिकारी-कर्मचारी अपने प्रभाव का उपयोग करके स्वीकृति नहीं मिलने देते। इस कारण उनके विरुद्ध न्यायालय में प्रकरण नहीं चल पा रहा है। उधर, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) में 35 अधिकारी-कर्मचारियों के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति आना बाकी है।

● विकास दुबे

लोकायुक्त के प्रतिवेदन नहीं रखे जा रहे विस में

जांच के बाद भी खोली जा रही फाइलें

मप्र में लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू की जांच पर लगातार सवाल उठते रहते हैं। कई बार तो ऐसी स्थिति बन जाती है कि जांच पूरी होने के बाद भी अदालत के हस्तक्षेप से फाइलें खोलनी पड़ती हैं। पूर्व परिवहन आरक्षक सौरभ शर्मा के विरुद्ध अनुपातहीन संपत्ति का मामला हो या फिर आजीविका मिशन घोटाले के आरोपित ललित मोहन बेलवाल का या दूसरे प्रकरण हों, जांच एजेंसियां लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू की कार्रवाई पर कई बार सवाल उठते रहे हैं। लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू की जांच को लेकर विपक्ष सरकार को घेरता रहता है। इसकी वजह है कि जांच एजेंसियां छोटे कर्मचारियों पर तो तत्काल कार्रवाई कर देती हैं, लेकिन बड़े अफसरों के मामले दबे रहते हैं। ऐसे ही मामलों को लेकर विपक्ष सड़क से सदन तक मुद्दे उठाता है। सरकार की घेराबंदी भी होती है, पर कई बड़े मामलों की कार्रवाई में तेजी नहीं दिखती। ऐसे एक नहीं कई उदाहरण हैं, जब आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच नहीं हुई तो शिकायतकर्ता को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। ताजा मामला पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन का है, जिसमें शिकायतकर्ता पूर्व विधायक किशोर समरोते ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, तब जांच प्रारंभ हुई। प्रदेश में ऐसे मामले भी हैं, जब जांच एजेंसी ने पर्याप्त साक्ष्य नहीं होने का हवाला देकर कोर्ट में खात्मा रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, पर कोर्ट ने रिपोर्ट को अस्वीकार कर दोबारा जांच करने के लिए कहा।

वन विभाग में भ्रष्टों को क्लीनचिट देने की तैयारी!

भले ही सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है, लेकिन अफसरशाही उसकी इस नीति को पलीता लगाने का कोई मौका नहीं छोड़ती है। अगर मामला अखिल भारतीय सेवा के अफसरों का हो तो फिर मान लीजिए की उसका दोषी साबित हो पाना बड़ा मुश्किल है। अगर दोषी साबित हो भी गए तो फिर कार्रवाई होना मुश्किल है। इसके एक नहीं कई मामले उदाहरण के रूप में मौजूद हैं। दरअसल प्रदेश सरकार ने हाल ही में नगर निगम ग्वालियर के तत्कालीन कमिश्नर रहे वेद प्रकाश शर्मा, विनोद शर्मा तथा एनबीएस राजपूत को क्लीनचिट देने की तैयारी लगभग कर ली है। इस बीच भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसे आईएफएस अधिकारियों को भी सेवानिवृत्ति के ठीक पहले या फिर रिटायर होते ही क्लीनचिट देकर उपकृत करने का काम किया जा रहा है।

विभागीय जांच के लिए सरकार द्वारा तीन माह की समय सीमा निर्धारित है, लेकिन आला अफसर हों या फिर रसूखदार कर्मचारी उनकी जांच तय सीमा में कभी भी पूरी नहीं हो पाती है। इस देरी के लिए जिम्मेदार अफसर, सरकार व शासन भी कोई कार्रवाई नहीं करता है। इसका फायदा जांच अधिकारी जमकर उठाते हैं। अब वन विभाग की बात की जाए तो प्रदेश वन महकमे के भारतीय वन सेवा तथा राज्य वन सेवा के 125 अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर मामलों में लोकायुक्त पुलिस और ईओडब्ल्यू में केस दर्ज हैं। इनमें लोकायुक्त में दर्ज 33 प्रकरणों में से 22 मामलों की जांच कर कार्रवाई करने रिपोर्ट सरकार को भेजी जा चुकी है। वहीं, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) ने 92 मामलों में से 35 अधिकारियों के मामलों की जांच रिपोर्ट सरकार को भेजी गई है। इसके बाद अब प्रदेश सरकार इन अफसरों पर कार्रवाई करने से पहले वन मुख्यालय स्तर पर परीक्षण कराएगा और परीक्षण के बाद उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्णय लेगी। ऐसा ही तीन आईएएस के मामले में किया गया है। उधर, सरकार ने स्वयं कहा कि 6 आईएफएस और 6 स्टेट फॉरेस्ट अफसरों के खिलाफ डीई चल रही है। छिंदवाड़ा लोकायुक्त पुलिस में वीसी मेश्राम उप वन मंडल अधिकारी, अनादि बुधौलिया एसडीओ, ग्वालियर लोकायुक्त पुलिस, राजीव कौशल एसडीओ, इंदौर लोकायुक्त पुलिस में ओपी उचाडिया तत्कालीन वन मंडल अधिकारी अलीराजपुर, अमृतलाल प्रजापति एसडीओ राजस्व सागर, जबलपुर लोकायुक्त पुलिस में एनएस डुगरियाल एपीपीसीसीएफ और क्षेत्रीय महाप्रबंधक राज्य वन विकास निगम, खंडवा लोकायुक्त पुलिस में प्रदीप मिश्रा डीएफओ, नर्मदापुरम लोकायुक्त पुलिस में पूजा नागले उप संचालक सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, रीवा लोकायुक्त पुलिस में गौरव चौधरी वन मंडल अधिकारी, आरबी शर्मा तत्कालीन वन मंडलाधिकारी सीधी, शहडोल लोकायुक्त पुलिस में आरएस सिकरवार वन मंडल अधिकारी उमरिया, यूके सुबुद्धि वन संरक्षक और तत्कालीन प्रबंध संचालक तथा उज्जैन लोकायुक्त पुलिस में शैलेंद्र कुमार गुप्ता वन मंडल अधिकारी, शंकरलाल यादव उप वनमंडलाधिकारी कन्नौद के खिलाफ मामला दर्ज है।

बैतूल लोकायुक्त पुलिस में प्रशांत कुमार सिंह वन मंडल अधिकारी पश्चिम सामान्य और आईएस गड़रिया सहायक वन संरक्षक और अनिल सिंह तत्कालीन मुख्य वन संरक्षक सामाजिक वानिकी बैतूल के खिलाफ मामला दर्ज है। भोपाल लोकायुक्त पुलिस में पुष्कर सिंह प्रबंध संचालक और तत्कालीन प्रबंध संचालक, यूके सुबुद्धि वन मंडल अधिकारी, अशोक कुमार सिंह वन मंडल अधिकारी, मनोज अग्रवाल वन मंडल अधिकारी, विजय कुमार नीमा वन मंडल अधिकारी और वीवी सिंह उप वन मंडल अधिकारी, धर्मेंद्र भदौरिया एसडीओ और आरके सिंह उप संभागीय प्रबंधक के खिलाफ मामला दर्ज है। छत्तरपुर लोकायुक्त पुलिस में ओपी उचाडिया तत्कालीन वन मंडल अधिकारी और बीएल वर्मा तत्कालीन उप वन मंडल अधिकारी, ओपी उचाडिया तत्कालीन वन मंडल अधिकारी और आरके अवधिया सहायक वन संरक्षक, आरके निरंजन, डीके महाजन (तत्कालीन उप वन मंडल अधिकारी), ओपी उचाडिया और अजय कुमार वाजपेयी (तत्कालीन परिक्षेत्र अधिकारी लवकुश नगर), शीतला प्रसाद शाक्य सहायक वन संरक्षक और चंद्रशेखर सिंह वन मंडल अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज है।

● लोकेश शर्मा

15 आईएफएस के खिलाफ विभागीय जांच लंबित

भ्रष्टाचार के आरोपों में 15 आईएफएस अधिकारियों के खिलाफ अभी भी विभागीय जांच लंबित है। सालों चलने वाली डीई की वजह से 7 अफसर तो सेवानिवृत्त हो चुके हैं , लेकिन उनकी जांच पूरी नहीं हो सकी है। इसी तरह से राज्य वन सेवा के एक दर्जन अधिकारियों के विरुद्ध भी भ्रष्टाचार के मामले लंबित पड़े हुए हैं। उधर, विभागीय जांच का समय पर निर्णय नहीं होने की वजह से चार अफसरों को प्रमोशन का लाभ नहीं मिल सका। जिन अफसरों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में विभागीय जांच चल रही है, उनमें आईएफएस अधिकारी वीएन प्यासी, निजाम कुरैशी, आरएस सिकरवार, ओपी उचाडिया, डीएस कनेश, डीएफओ वीएस होतगी, एम कालीदुरई, आरपी राय, सीएस निनामा, शैलेंद्र कुमार गुप्ता, डीएफओ किरण बिसेन, प्रशांत कुमार सिंह, देवांशु शेखर, नरेश कुमार दोहरे तथा वन संरक्षक अजय कुमार पांडेय का नाम है। इनमें से प्यासी, कुरैशी, सिकरवार, उचाडिया, कनेश, कालीदुरई, राय, निनामा और गुप्ता रिटायर हो चुके हैं। गुप्ता हाल ही में सेवानिवृत्त हुए हैं, जबकि डीई पेंडिंग होने की वजह से डीएफओ वीएस होतगी, किरण बिसेन, प्रशांत कुमार तथा देवांशु शेखर को वन संरक्षक के पद पर प्रमोशन नहीं दिया गया है। वहीं भ्रष्टाचार के आरोप में राज्य वन सेवा के अधिकारी सहायक वन संरक्षक आरके गुरूदेव, कैलाश वर्मा, आरएन द्विवेदी, मनीषा पुरवार, सुरेश कुमार अहिरवार, मनोज कटारिया, सुधीर सिंह, वाईएस परमार, सुधीर पाठक, केबी गुप्ता, अंत सिंह ओहारिया तथा आईबी गुप्ता का नाम शामिल है।

मप्र में राजनीति में भी महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। मप्र सरकार ने पंचायतों और शहरी निकायों में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण लागू किया है, जिसका लक्ष्य इन संस्थाओं में 50 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना है। यह कदम ग्रामीण और शहरी स्तर पर महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करने और उनकी आवाज को मजबूती देने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। लेकिन कई महिला जनप्रतिनिधि चूल्हे-चौके तक सिमट गई हैं। उनकी जगह पति-बेटों के हाथ में उनके पद और अधिकार की कमान है।

चूल्हे-चौके तक सिमटीं महिला जनप्रतिनिधि

मप्र में राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी निरंतर बढ़ रही है। प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय जैसी संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने 50 प्रतिशत महिला आरक्षण दिया है लेकिन यहां 60 प्रतिशत महिलाएं चुनाव जीतकर प्रतिनिधित्व कर रही हैं। यही स्थिति नगर निगमों की है। प्रदेश के 16 नगर निगमों में से 9 में महिला महापौर हैं। तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो शहरों की तुलना में ग्रामीण महिलाएं राजनीति में आगे हैं। विधानसभा और लोकसभा में महिला आरक्षण नहीं है फिर भी यहां महिलाओं की संख्या कम नहीं है।

मप्र विधानसभा में लगभग 11 प्रतिशत से ज्यादा यानी कुल 230 सदस्यों वाले सदन में 27 है। वहीं, लोकसभा में 29 में से 6 सांसद महिलाएं हैं। वहीं जनपद सदस्य 313, इनमें महिलाएं 167, सरपंच 22,924 में 12,600 महिलाएं और पंच 3,63,350 में से 2,09,754 महिलाएं हैं। मप्र विधानसभा चुनाव में वर्ष 2008 में सर्वाधिक महिलाओं ने चुनाव लड़ा था। तब कांग्रेस ने 37 महिलाओं को प्रत्याशी बनाया था, जिनमें 8 ने चुनाव जीता। जबकि भाजपा ने 25 महिलाओं को प्रत्याशी बनाया। इनमें से 14 ने जीत दर्ज की, एक अन्य सीट पर बसपा की उषा चौधरी को विजय मिली थी। वर्ष 2013 में भाजपा ने 28 महिला प्रत्याशियों को उतारा और 22 पार्टी के भरोसे पर खरी उतरीं। जबकि कांग्रेस ने 23 महिलाओं को टिकट दिया लेकिन केवल 6 ही जीत सकीं। इस चुनाव में दो अन्य दलों की भी महिलाएं जीतीं। पंद्रहवी विधानसभा 2018 में महिलाओं की संख्या में कमी आई और यह घटकर 9 प्रतिशत यानी 21 हो गई थी। जो 2024 में बढ़कर फिर 27 पर पहुंच गई।

15 प्रतिशत टिकट भी महिलाओं को नहीं मिलते

लोकसभा और राज्यसभा से नारी शक्ति वंदन विधेयक पारित होने के बाद से ही राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाए जाने को लेकर देश में बहस छिड़ी हुई है। महिलाओं को आरक्षण संबंधी कानून बनने के बाद उन्हें लोकसभा और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा लेकिन हकीकत ये है कि वर्तमान स्थिति की बात करें तो कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है, जो 15 प्रतिशत टिकट भी महिलाओं को देता हो। भाजपा प्रवक्ता नेहा बग्गा का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में सशक्त बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। स्थानीय निकाय चुनाव में 50 प्रतिशत आरक्षण की वजह से लाखों की संख्या में आज पंच-सरपंच नगर निगम अध्यक्ष महापौर पार्षद आदि नेतृत्व कर रहे हैं। मप्र में 40 लाख माताएं-बहनें स्वसहायता समूह से जुड़कर आत्मनिर्भर बनी हैं। भाजपा ने संगठन में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए पन्ना जैसी इकाई पर 33 प्रतिशत का आरक्षण महिला कार्यकर्ताओं के लिए रखा है। वहीं महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल का कहना है कि हम लगातार महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। पंचायत चुनाव हो या फिर नगरीय निकाय चुनाव सभी में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। मतदान केंद्र स्तर तक महिलाओं की टीम तैयार करके मतदान बढ़ाने पर फोकस किया है।

महिलाओं के लिए नगरीय निकाय चुनाव में 33 प्रतिशत और पंचायत चुनाव में 50 प्रतिशत आरक्षण है। इसके बावजूद महिलाएं राजनीतिक रूप से सक्षम नहीं बन पा रही हैं। जानकार कहते हैं कि महिलाओं की राजनीति में हिस्सेदारी सबसे पहली सीढ़ी से बढ़ाने की जरूरत है। हालांकि, पंचायत के चुनावों में इस वर्ग के लिए 50 प्रतिशत का आरक्षण जरूर है, लेकिन अधिकांश मामलों में देखा जाता है कि वे सिर्फ नाम की जनप्रतिनिधि हैं। उनके सारे अधिकार पति अथवा पुत्र के हाथों में रहते हैं। गौरतलब है कि समाज के हर क्षेत्र में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ी है। राजनीति में भी महिला सशक्तिकरण की दिशा में लगातार प्रगति हुई है। महिलाएं नेतृत्व की अग्रिम पंक्ति में तेजी से अपनी पहचान बना रही हैं। मप्र के 413 नगरीय निकायों में से 220 में भले ही महापौर-अध्यक्ष की कुर्सी पर महिलाएं हैं, लेकिन इनमें से 26 प्रतिशत यानी 57 में कमान पूरी तरह उनके पति-बेटों के हाथ में है। वहीं 48 प्रतिशत यानी 105 निकायों में रिश्तेदारों की दखलंदाजी है, लेकिन पूरी तरह नहीं। केवल 26 प्रतिशत यानी 58 निकायों में ही महिला अध्यक्ष और महापौर नगर सरकार के फैसले खुद ले रही हैं।

मप्र के 16 नगर निगमों में से 9 में महापौर महिलाएं हैं। वहीं इन्हीं नगर निगमों में 884 पार्षद पदों में से करीब 450 पर महिलाओं का कब्जा है। लेकिन विडंबना यह है कि केवल 4 महापौर ऐसी है जो खुद फैसले ले रही हैं। इनमें भाजपा की 3 और कांग्रेस की 1 मेयर शामिल हैं। भोपाल में मालती राय पहली बार की मेयर हैं। नगर निगम से जुड़े सभी फैसले वह खुद लेती हैं। सरकारी कामकाज में उनके परिवार के किसी भी सदस्य का प्रत्यक्ष तौर पर दखल नहीं हैं।

ग्वालियर की मेयर शोभा सिकरवार हैं। वे हर हफ्ते जनता दरबार का आयोजन करती हैं। पति सतीश सिकरवार विधायक हैं, मगर पत्नी के काम में दखल नहीं देते। खंडवा की मेयर अमृता अमर यादव पहली बार चुनी गई हैं। जब उनका कार्यकाल शुरू हुआ तो पति अमर यादव ने सांसद प्रतिनिधि बनकर कामकाज में हस्तक्षेप किया, लेकिन कमिश्नर सविता प्रधान से विवाद के बाद नगर निगम में उनकी एंट्री बंद हो गई। बुरहानपुर की माधुरी पटेल दूसरी बार मेयर बनी हैं। उनके कामकाज में परिवार के किसी भी सदस्य का दखल नहीं है। वह अपने फैसले खुद लेती हैं। उनके पति भी मेयर रह चुके हैं, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आते। वहीं मुरैना की शारदा सोलंकी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतीं। जनता दरबार में आने वाली समस्याएं भी पुत्र सौरभ ही सुनता है। नगर निगम की बैठकों में शामिल होता है। निरीक्षण के दौरान वह महापौर के साथ रहता है। देवास में भाजपा की मेयर गीता अग्रवाल के साथ उनके पति दुर्गेश अग्रवाल कामकाज देखते हैं। हर गतिविधि में साथ रहते हैं। पदभार ग्रहण के दौरान गीता यादव की कुर्सी पर उनके पति दुर्गेश अग्रवाल बैठे दिखाई दिए थे। सागर में भाजपा की मेयर संगीता तिवारी के साथ बैठक और कार्यक्रमों में उनके पति सुशील तिवारी दिखाई देते हैं। निर्माण कार्यों के लोकार्पण और भूमिपूजन के कार्यक्रमों में वे नजर आते हैं। मेयर से किसी को काम हो तो पहले पति से मिलते हैं। कटनी में साल 2022 में प्रीति सूरी बतौर निर्दलीय ये चुनाव जीती थीं। बाद में वह भाजपा में शामिल हो गईं। उनके साथ अधिकांश समय पति संजीव सूरी मौजूद होते हैं। वार्ड का दौरा भी दोनों साथ करते हैं। संजीव सूरी ने भी पार्षद का चुनाव लड़ा था, मगर वे हार गए। सिंगरौली एकमात्र नगर निगम आम आदमी पार्टी के पास हैं। मेयर रानी अग्रवाल पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनका कामकाज पति प्रेम अग्रवाल देखते हैं। निगम के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में पति साथ होते हैं।

प्रदेश की नगर पालिकाओं की बात करें तो नगर पालिका की 17 अध्यक्ष अपना कामकाज खुद करती हैं। इनमें भाजपा की 13 और कांग्रेस की 4 अध्यक्ष हैं। वहीं 27 नगर पालिकाओं की अध्यक्ष ऐसी है जो 50 प्रतिशत जिम्मेदारी संभालती हैं। इनमें से 23 नगर पालिकाओं पर भाजपा, तो कांग्रेस 3 पर काबिज है। एक नगर पालिका अध्यक्ष निर्दलीय हैं। यहां महिलाएं आधी जिम्मेदारी खुद संभालती हैं और आधी जिम्मेदारी उनके रिश्तेदार संभालते हैं। सीहोरा नगर पालिका में संध्या दुबे नगर पालिका अध्यक्ष हैं। उनके पति दिलीप दुबे पूर्व विधायक रहे हैं। अध्यक्ष के कामकाज में उनका दखल रहता है। दिलीप दुबे जब किसी फैसले पर अंतिम मुहर लगाते हैं उसी के बाद पत्नी उस पर आगे बढ़ती हैं। मंडीदीप नगर पालिका में प्रियंका अग्रवाल अध्यक्ष की कुर्सी पर काबिज हैं। उनके कामकाज में पति राजेंद्र अग्रवाल का पूरा दखल होता है। राजेंद्र अग्रवाल पहले भाजपा जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। श्योपुर नगर पालिका में रेणु सुजीत गर्ग पहली बार अध्यक्ष बनी हैं। उनका आधा काम पति सुजीत गर्ग संभालते हैं। वो सार्वजनिक कार्यक्रमों के साथ बैठकों में भी शामिल होते हैं। 11 नगर पालिकाएं ऐसी हैं जिनमें पूरी जिम्मेदारी रिश्तेदारों के हाथ में हैं। इनमें से 7 पर भाजपा और 4 पर कांग्रेस काबिज है। इन नगर पालिकाओं में महिला अध्यक्ष केवल नाम की हैं। सारा कामकाज उनके पति-बेटे और रिश्तेदार संभालते हैं। छतरपुर नगर पालिका में भाजपा की ज्योति चौरसिया अध्यक्ष हैं। उनके पति सुरेंद्र चौरसिया नगर पालिका का पूरा कामकाज देखते हैं। वो भाजपा के जिला महामंत्री होने के साथ-साथ नगर पालिका अध्यक्ष के प्रतिनिधि भी हैं। वे नगर पालिका के तहत आने वाले कामों की मॉनीटरिंग करते हैं। सारी व्यवस्थाओं का जायजा खुद लेते हैं और अधिकारियों को निर्देश भी देते हैं। बालाघाट नगर पालिका में भारती सुरजीत सिंह ठाकुर पहली बार अध्यक्ष बनी हैं। उनके कामकाज में पति सुरजीत सिंह ठाकुर का सीधा दखल होता है। प्रशासनिक जमावट भी उन्हीं के हिसाब से होती है। विकास कार्य और कार्यक्रमों में वो पत्नी के साथ नजर आते हैं। दतिया नगर पालिका में शांति ढेंगुला नगर पालिका अध्यक्ष हैं। उनका पूरा कामकाज बेटे प्रशांत ढेंगुला के जिम्मे है। वह खुद भी पार्षद रह चुके हैं। इस बार दतिया महिला सीट होने से मां को चुनावी मैदान में उतारा था। बैनर पोस्टर में मां की जगह खुद के नाम और फोटो का इस्तेमाल पद के साथ करते हैं।

● **श्याम सिंह सिकरवार**

156 नगर परिषद अध्यक्ष महिलाएं

258 में से 156 नगर परिषद अध्यक्ष की कुर्सी पर महिलाएं काबिज हैं। लेकिन इनमें से 119 नगर परिषद में रिश्तेदारों का दखल है। इनमें से 46 नगर परिषद का कामकाज तो पूरी तरह से पति-बेटों और रिश्तेदारों के हाथों में हैं। केवल 37 नगर परिषद ऐसी हैं, जहां महिला अध्यक्ष खुद ही फैसले लेती हैं। सीधी जिले की चुरहट नगर परिषद की अध्यक्ष मोनिका गुप्ता 2022 में अध्यक्ष चुने जाने से पहले गृहिणी थीं। उनका राजनीति से दूर-दूर तक कोई नाता नहीं था। हालांकि, उनके पति विजय गुप्ता कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता थे। चुरहट नगर परिषद अध्यक्ष का पद महिला के लिए आरक्षित हुआ, तो विजय गुप्ता ने पत्नी को चुनाव लड़ाया। बहुमत के आधार वह अध्यक्ष चुन ली गईं, मगर सारा कामकाज विजय गुप्ता ही देखते हैं। अप्रत्यक्ष तौर पर अध्यक्ष की भूमिका में गुप्ता ही हैं। रतलाम जिले की नामली नगर परिषद की अध्यक्ष अनीता परिहार हैं, मगर परिषद का सारा कामकाज उनके देवर सत्येंद्र परिहार के हाथ में है। अध्यक्ष प्रतिनिधि के तौर पर वह सारा कामकाज करते हैं।

लोक निर्माण विभाग में भ्रष्ट सबसे विश्वसनीय

सरकार की सख्ती के बावजूद लोक निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं भ्रष्ट अफसरों का पूरा संरक्षण मिल रहा है। विभाग की कार्यप्रणाली को देखें तो यह तथ्य सामने आता है कि लोक निर्माण विभाग में भ्रष्ट सबसे विश्वसनीय है। इसका आंकलन इससे किया जा सकता है कि विभाग में भ्रष्टाचार में फंसे अफसरों को बड़े-बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी जा रही है। ताजा मामला पीडब्ल्यूडी सेतु में पदस्थ चीफ इंजीनियर जीपी वर्मा का सामने आया है। 83 करोड़ के घोटाले में वर्मा को आरोप पत्र देने के बाद भी सरकार ने इन्हें 2 हजार करोड़ से ज्यादा के 46 फ्लाईओवर और आरओबी के निर्माण की जिम्मेदारी सौंप दी है।

गौरतलब है कि मप्र सरकार एक तरफ जहां भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉरलेंस की बात करती है, वहीं भ्रष्टाचार में फंसे अफसरों को बड़े और करोड़ों के प्रोजेक्ट भी सौंपने में लगी है। तत्कालीन मुख्य अभियंता (भवन) इंदौर में पदस्थ रहे जीपी वर्मा पर आरोप है कि इन्होंने 83 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले जिला अदालत के निर्माण में कथित तौर पर अनियमितताएं कीं। इन्होंने न्यायालय भवन इंदौर के निर्माण में द्वितीय निविदा आमंत्रण के दौरान न्यूनतम निविदाकार मेसर्स एरकॉन इंफ्रा लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत टर्नओवर की विधिवत पुष्टि नहीं की और टेंडर खोलकर काम को मंजूरी दे दी। जबकि मुख्यमंत्री कार्यालय से 8 मई 2024 को मिली शिकायत में मेसर्स एरकॉन इंफ्रा गुजरात के द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी होने का उल्लेख है। उक्त शिकायत की जांच मुख्य अभिंयता भवन इंदौर द्वारा किए जाने पर ठेकेदार का अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया। इसके बाद एरकॉन इंफ्रा को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, जिसके कारण जिला अदालत के भवन का निर्माण समय पर नहीं हो सका और सरकार को करोड़ों की चपत लगी। इसके चलते लोक निर्माण विभाग ने 27 सितंबर 2024 को चीफ इंजीनियर जीपी वर्मा को आरोप पत्र थमा दिया।

जीपी वर्मा पीडब्ल्यूडी सेतु में चीफ इंजीनियर के पद पर पदस्थ हैं। भ्रष्टाचार में फंसे होने के बावजूद सरकार ने वर्मा को इस साल कई प्रमुख प्रोजेक्ट सौंप दिए हैं। इनमें शिप्रा नदी पर नवीन फोरलेन लागत 23.48 करोड़, नरसिंह घाट पर सामतिर पुल का निर्माण 10.53 करोड़, शंकराचार्य चौराहा, शिप्रा नदी पर पुल निर्माण-43.82 करोड़, रेलवे पुल के सामांतर लालपुल 4 लेन का निर्माण-17.32 करोड़, उज्जैन-मक्सी मार्ग टू-लेन आरओची का निर्माण-52.03 करोड़, उज्जैन-लालपुर, आरओबी पंचक्रोशी का निर्माण -46.52 करोड़, हरिफाटक पार्किंग से महाकाल लोक पाने अंडापास 49.50 करोड़, दुर्गादास को छत्री से गोन्सा चौराहा 4 लेन पुल सहित 67.27 करोड़, शाजापुर बायपास सहित दो उच्च स्तरीय पुलों का निर्माण-152 करोड़, वेदा नदी पर रपटा के स्थान पर ब्रिज निर्माण लागत-20.06 करोड़, चकनार नदी पर गाडासरई मार्ग के लिए पुल का निर्माण-12.50 करोड़, पीडब्ल्यूडी मार्ग पर कारी नदी पर पुल का निर्माण लागत-24.00 करोड़, सिंध नदी पर मिहाबरा व दोनों के बीच पुल निर्माण लागत-49.23 करोड़, थांदला में ग्राम केसरपुरा में माही नदी पर पुल का निर्माण-15.22 करोड़, ग्राम खडेंदरा से सुडके बीच सिंध नदी पर पुल निर्माण 17.78 करोड़, अमरावती राजमार्ग रेलवे फाटक के पास ओवर ब्रिज 80 करोड़, सोधी में संजय गांधी महाविद्यालय तक फ्लाईओवर 188.20 करोड़ और निवाड़ी झांसी मानिकपुर रेलवे लाइन पर ओवर ब्रिज-23.53 करोड़ का प्रोजेक्ट शामिल हैं। जीपी वर्मा पर पूर्व में भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। इससे पहले जीपी वर्मा कार्यपालन यंत्री के रूप में दतिया में पदस्थ थे और वहां इनके द्वारा कराए गए निर्माण कार्यों में अनियमितताओं के चलते इनके खिलाफ सरकार द्वारा विभागीय जांच की जा रही है। भ्रष्टाचार के मामले में आरोप पत्र सौंपने के बाद भी सरकार ने इन्हें इंदौर से हटाकर भोपाल में सेतु निर्माण की जिम्मेदारी सौंप दी। इधर, भोपाल के ही डॉ. अंबेडकर ब्रिज जो कि गणेश मंदिर से डीबी मॉल के सामने से होते हुए मंत्रालय की सड़क को जोड़ता है, उसमें भी अनियमितताओं के चलते विभाग ने इन्हें शोकॉज नोटिस जारी किया था।

हाल ही में इस मामले की शिकायत एसीएस पीडब्ल्यूडी नीरज मंडलोई से की गई है। शिकायत में 156 करोड़ की लागत के जीजी फ्लाईओवर ब्रिज के घटिया निर्माण कार्य में ठेकेदार और चीफ इंजीनियर की मिलीभगत बताई जा रही है। सेतु निर्माण के चीफ इंजीनियर जीपी वर्मा भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसे होने के बाद भी सरकार इन पर मेहरबान नजर आ रही है। जिला अदालत इंदौर के भवन निर्माण में हुई अनियमितताओं को लेकर इनके विरुद्ध जारी आरोप पत्र का वर्मा ने समय पर जवाब नहीं दिया। वहीं जीजी ब्रिज, जिसे अब डॉ. अंबेडकर फ्लाईओवर के नाम से जाना जाता है, में हुई गड़बड़ियों में शामिल कार्यपालन यंत्री को बचाने का काम किया जा रहा है। ऊपर से सरकार ने 2 हजार करोड़ से अधिक की लागत के 46 फ्लाईओवर और आरओबी के निर्माण की जिम्मेदारी भी इन्हें सौंप दी है, जिसमें तीन आरओबी और फ्लाईओवर भोपाल में निर्मित कराए जाने हैं। इस संबंध में जीपी वर्मा से बात करनी चाही, तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया।

● नवीन रघुवंशी

इनके विरुद्ध भी है केस

मप्र भवन विकास निगम के प्रभारी उप महाप्रबंधक डिवीजन ऑफिस मंडला ललित चौधरी के विरुद्ध सीएम राइज स्कूल के निर्माण में केंद्र और राज्य सरकार की राशि का दुरुपयोग करने और भ्रष्टाचार किए जाने की शिकायत ईओडब्ल्यू में की गई है। यह शिकायत वर्ष 2024 में की गई है जिसकी जांच चल रही है। लोकायुक्त पुलिस में राघवेंद्र सिंह किरार सहायक जनरल मैनेजर लोक निर्माण विभाग के भवन विकास निगम के विरुद्ध वर्ष 2023 में की गई है। भवन विकास निगम के उप महाप्रबंधक तकनीकी संविदा पद पर पदस्थ निशांत पचौरी के विरुद्ध ईडब्ल्यूएस कोटे का फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी पाने और अधिक आय अर्जित करने के मामले में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) में एक साल पहले अप्रैल 2024 में शिकायत की गई है जिसकी जांच अभी जारी है। शिकायत में कहा गया है कि आर्थिक स्थिति मजबूत होने के बाद भी ईडब्ल्यूएस का फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी हासिल की गई है।

संगठन मजबूत करने में जुटी कांग्रेस

मप्र कांग्रेस संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है। इसे लेकर तरह-तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं और अलग-अलग व्यक्तियों को दायित्व दिए जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव के करीब साढ़े तीन साल पहले कांग्रेस ने पहली बार चुनाव प्रबंधन विभाग का अलग से गठन किया है। कांग्रेस के प्रदेश संगठन प्रभारी डॉ. संजय कावले कहते हैं कि इससे पहले चुनाव के समय चुनाव प्रबंधन कमेटी बनाई जाती थी। पहली बार इस तरह का प्रयोग किया गया है। इस विभाग का प्रभार पूर्व मंत्री प्रियव्रत सिंह को दिया गया है।

वही संगठन प्रभारी में भी बदलाव किया गया गया है। पूर्व मंत्री प्रियव्रत सिंह की जगह पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे को प्रभार सौंप गया है। दरसअल चार महीने पहले मप्र कांग्रेस के संगठन में दो-दो प्रभारी नियुक्त किए गए थे। पूर्व मंत्री प्रियव्रत सिंह और प्रदेश महामंत्री संजय कामले को संगठन का प्रभारी बनाया गया था। चार महीने में ही प्रियव्रत सिंह की जगह संगठन का प्रभार पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे को दिया गया है। कांग्रेस की चुनाव प्रबंधन समिति में प्रियव्रत सिंह-प्रभारी, गौरव रघुवंशी-अध्यक्ष, गोरकी बैरागी-सदस्य, मृणाल पंत-सदस्य, शैलेंद्र पटेल-सदस्य और मयंक तेनगुरिया-सदस्य बनाए गए हैं। मप्र कांग्रेस द्वारा गठित चुनाव प्रबंधन विभाग अब निचले स्तर के संगठन पर काम करेगा। यानि हर विधानसभा में चुनाव प्रबंधन का प्रभारी नियुक्त किया जाएगा। इसके बाद पंचायत और वार्ड समितियों का गठन होगा। इन समितियों के गठन में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि चुनावी लिहाज से पंचायत और वार्ड समिति के सदस्य कितने कैपेबल हैं।

सोशल मीडिया पर सक्रियता के साथ ही स्थानीय राजनीतिक परिस्थिति और तकनीक के जानकार लोगों को सदस्य बनाया जाएगा। विधानसभा के प्रभारियों के बाद पंचायत और वार्ड समितियों को चुनावी लिहाज से ट्रेनिंग देने का काम चुनाव प्रबंधन विभाग द्वारा किया जाएगा। वहीं भाजपा ने जिस तरह से मतदाता सूची पर पन्ना प्रभारी और अर्द्ध पन्ना प्रभारी नियुक्त किए हैं। कांग्रेस भी अब पन्ना प्रभारियों की काट खोजने के लिए पंचायत और वार्ड समितियों के गठन के बाद वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर बारीकी से काम करेगी। कांग्रेस के चुनाव प्रबंधन विभाग द्वारा पंचायत और वार्ड समितियों के जरिए स्थानीय स्तर के सार्वजनिक मुद्दे संकलित कराए जाएंगे। उनका पूरा दस्तावेजीकरण होगा। चुनाव में नैरेटिव सेट करने में ये मुद्दे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। कौन से ऐसे स्थानीय मुद्दे हैं जिन्हें जिला स्तर पर और प्रदेश स्तर पर उठाते हुए इलेक्शन का नैरेटिव सेट करना है ये काम भी चुनाव प्रबंधन विभाग करेगा। कांग्रेस के मीडिया विभाग में बदलाव किया गया है। पिछले साल 27 मार्च को पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने मीडिया विभाग के अध्यक्ष केके मिश्रा की जगह मुकेश नायक को अध्यक्ष नियुक्त किया था। साथ ही 9 मुख्य प्रवक्ता और 22 प्रवक्ताओं की नियुक्ति की थी। कांग्रेस ने अब मुख्य प्रवक्ता का पद खत्म कर दिया है।

कांग्रेस के संगठन प्रभारी संजय कामले ने अब 53 प्रवक्ताओं की नियुक्ति की है। जिन लोगों को प्रवक्ता बनाया गया है इसमें अजीत भदोरिया, अपराजिता पांडेय, अब्बास हफीज, अभिनव बरोलिया, अमित चौरसिया, अमित तावड़े, अम्बिका शर्मा, अवनीश बुंदेला, आनंद जाट, आनंद जैन कासलीवाल, आरपी सिंह, कुंदन पंजाबी, गुंजन शुक्ला, जितेंद्र मिश्रा, ज्योति पटेल, धर्मेंद्र शर्मा, नीलाभ शुक्ला, नूरी खान, प्रतिभा विक्टर, प्रमोद द्विवेदी, प्रवीण धोलपुरे, प्रियंका शर्मा, फिरोज सिद्दिकी, भूपेंद्र गुप्ता, मिथुन अहिरवार, मुकेश पंथी, मृणाल पंत, योगेश यादव, रवि वर्मा, रवि सक्सेना, राजेश चौकसे, राम पांडेय, राहुल राज, रितेश त्रिपाठी, रोशनी यादव, विक्रम चौधरी, विनय सक्सेना, विनोद शर्मा, विवेक त्रिपाठी, शहरयार खान, शैलेंद्र पटेल, संगीता शर्मा, संतोष सिंह गौतम, संतोष सिंह परिहार, संदीप सबलोक, समर सिंह, साबिर फिटवाल, सीताशरण सूर्यवंशी, सुनील मिश्रा, स्पर्श चौधरी, स्वदेश शर्मा, हर्ष जैन और हिमानी सिंह शामिल हैं। पिछले साल मार्च में 9 मुख्य प्रवक्ताओं और 22 प्रवक्ताओं सहित मीडिया विभाग में कुल 31 नियुक्तियां की गई थीं। इस बार 53 प्रवक्ताओं की नियुक्ति हुई है। इसमें कई प्रवक्ताओं की छुट्टी कर दी गई है। इनमें पूर्व विधायक कुणाल चौधरी (कालापीपल), डॉ. अशोक मर्सकोले (निवास), बैजनाथ कुशवाह (सबलगढ़), विपिन वानखेड़े (आगर) को हटाया गया है। राजकुमार केलू उपाध्याय, रीना बौरासी, अवनी बंसल, अमित शर्मा को भी प्रवक्ताओं की लिस्ट से बाहर किया गया है।

● जितेंद्र तिवारी

वक्फ बिल के विरोध में अभियान चलाएगी कांग्रेस

वक्फ संशोधन बिल के विरोध में अब कांग्रेस भी जन जागरूकता अभियान चलाएगी। भोपाल में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की बैठक हुई। इस बैठक में मप्र कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की बैठक में पूर्व विधायक हमीद काजी और एआईसीसी अल्पसंख्यक विभाग के प्रभारी निजाम कुरैशी के साथ मप्र कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष शेख अलीम और सभी जिलों के अल्पसंख्यक कांग्रेस के अध्यक्ष और प्रदेश पदाधिकारी मौजूद थे। कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष शेख अलीम ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल के विरोध में कानूनी लड़ाई कैसे लड़ना है, कैसे जन चेतना फैलाना है, बैठक में इसकी पूरी कार्ययोजना बनाई है। हमारे नेता राहुल गांधी के संविधान बचाओ अभियान, जातिगत जनगणना जैसे विषयों पर चर्चा हुई है। जिला अध्यक्षों ने जो बातें रखीं हैं उस पर हमने रणनीति बनाई है। शेख अलीम ने कहा कि अभी पहलगाम में जो घटना हुई, उस घटना पर भाजपा को एक दिन भी हिंदू-मुस्लिम करने का मौका नहीं मिला और हमारा अल्पसंख्यक समाज मैदान में आया। आतंकवाद और पहलगाम में हुए घिनौने कृत्य के विरोध में पूरे प्रदेश में अल्पसंख्यक समाज ने पुतले जलाए। उसकी एक अलग ही पूरे प्रदेश में बात पहुंची कि हिंदुस्तान का मुसलमान अपने देश और हिंदू भाईयों के साथ है। गंगा-जमुनी तहजीब के साथ है। ये वो लोग हैं जब हिंदुस्तान-पाकिस्तान अलग हो रहे थे तो छोड़कर नहीं गए।

276 करोड़ में बुझेगी गांवों की प्यास

मप्र में जल जीवन मिशन का काम गति नहीं पकड़ पा रहा है। इसकी वजह से लोगों को नल से जल नहीं मिल पा रहा है। ठेकेदार और अफसर मौज काट रहे हैं, जबकि ग्रामीण इलाकों के लोग गर्मी के मौसम में पानी के लिए भटक रहे हैं। यह हाल उस योजना के हैं, जिसे छह साल पहले लागू किया गया था। हालत यह है कि इस योजना को इस साल के अंत तक पूरा करना है, लेकिन जिस तरह से काम हो रहा है, उससे लग रहा है कि अभी इसे पूरा होने में दो से तीन साल और लग सकते हैं। उधर, प्रदेश में गर्मी के प्रचंड रूप लेते ही ग्रामीण इलाकों में पेयजल संकट गंभीर रूप लेने लगा है। ऐसे में सरकार द्वारा ग्रामीण इलाकों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर गांव में सभी घरों को पाइप लाइन द्वारा जलापूर्ति योजना के जरिए पानी पहुंचाने की योजना पर सवाल उठाए जाने लगे हैं। सरकार ने 30 जून तक सभी ग्रामीण इलाकों में पेयजल व्यवस्था के लिए 276 करोड़ रुपए खर्च करने का प्लान बनाया है पर मई का महीना शुरू होने के बाद भी गहराते जल संकट से निदान को लेकर शिकायतों का दौर तेज होने लगा है। ऐसे में कलेक्टरों को बोरिंग खनन पर प्रतिबंध लगाना पड़ा है तो ग्रामीणों को पानी खरीदना मजबूरी बना है।

मोहन सरकार ने गर्मी में पेयजल संकट के निदान के लिए यह निर्णय लिया था कि गर्मी के मद्देनजर ग्रामीण बसाहटों में हैंडपंपों के माध्यम से पेयजल व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखना है लेकिन अब इसमें दिक्कतें सामने आने लगी हैं। सरकार के दावे हैं कि नल जल योजना के माध्यम से भी पानी की व्यवस्था की जा रही है जो गहराते जल संकट के चलते सरकार की व्यवस्थाओं की पोल खोल रही है। बजट सत्र के दौरान सरकार ने यह तय किया था कि गर्मी में 1 अप्रैल से 30 जून तक जहां पेयजल संकट की स्थिति बनेगी वहां पीएचई विभाग द्वारा ग्रीष्मकालीन कार्ययोजना के अंतर्गत पानी दिया जाएगा। ऐसे गांवों में हैंडपंपों और नलकूपों में राइजर पाइप बढ़ाकर, नए हैंडपंप लगाकर, पानी का प्रेशर कम होने पर नलकूपों में हाइड्रोफैक्चरिंग करके, सफाई कराने का काम कराया जाएगा। साथ ही अनुपयोगी होने से बंद नल जल योजनाओं में नए नलकूप स्त्रोत खनन कराकर प्रभावित बसाहट वाले इलाकों में काम कराया जाएगा। पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जिन जिलों में सर्वाधिक राशि खर्च की जाएगी उनमें धार में 1486.93 लाख, अलीराजपुर में 1274.92 लाख, शाजापुर में 1232.15 लाख, छिंदवाड़ा पांढुर्णा में 1224.72 लाख, नीमच में 1100.74 लाख, खरगोन में 1086.52 लाख, उज्जैन में 1058.90 लाख, रतलाम में 997.06 लाख, देवास में 966.09 लाख, झाबुआ में 804.66 लाख खर्च होगा। इसके अलावा सिवनी में 635.17 लाख, मंडला में 616.49 लाख, बालाघाट में 615.21 लाख, सागर में 581.38 लाख, इंदौर में 563.35 लाख, खंडवा में 508.77 लाख, मंदसौर में 503.29 लाख, शिवपुरी में 499.09 लाख, श्योपुरकला में 476.05 लाख, मैहर में 458.99 लाख, मुरैना में 435.54 लाख, आगर में 433.70 लाख, जबलपुर में 414.79 लाख, शहडोल में 405.04 लाख, छतरपुर में 410.60 लाख, रीवा में 410.24 लाख, भोपाल में 263.45 लाख, रायसेन में 394.67 लाख, सीहोर में 376.99 लाख, राजगढ़ में 321.59 लाख, विदिशा में 379.20 लाख, नर्मदापुरम में 291.79 लाख, बैतूल में 359.49 लाख, हरदा में 279.99 लाख, बड़वानी में 396.90 लाख, सीधी में 352.79 लाख, सिंगरौली में 281.29 लाख, अनूपपुर में 367.40 लाख, उमरिया में 269.84 लाख, भिंड में 320.60 लाख, दमोह में 319.29 लाख, पन्ना में 336.79 लाख, टीकमगढ़ में 318.34 लाख, निवाड़ी में 130.84 लाख, कटनी में 280.78 लाख, नरसिंहपुर में 295.59 लाख, डिंडोरी में 280.78 लाख, मऊगंज में 335.04 लाख, बुरहानपुर में 270.30 लाख, ग्वालियर में 370.84 लाख, दतिया में 277.27 लाख, गुना में 375.58 लाख और अशोकनगर में 314.90 लाख खर्च होगा। सरकार का दावा है कि इन कार्यों को जून के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा, ताकि ग्रामीण इलाकों में पेयजल संकट से राहत मिल सके। हालांकि, अब तक की स्थिति को देखते हुए ये दावे जमीनी स्तर पर कितने कारगर साबित होंगे, यह आने वाला वक्त बताएगा।

55 जिलों वाले मप्र में दो साल पहले दो जिलों को जल प्रमाणित जिला घोषित किया गया था, इसके बाद से एक भी जिला जल प्रमाणित घोषित नहीं हो सका है। जुलाई, 2022 में सबसे पहले बुरहानपुर को हर घर जल प्रमाणित जिला घोषित किया गया। इसके 11 महीने बाद जून, 2023 में निवाड़ी प्रदेश का दूसरा हर घर जल प्रमाणित जिला घोषित हुआ। निवाड़ी को हर घर जल प्रमाणित जिला घोषित हुए दो साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद से अब तक तीसरा जिला हर घर जल प्रमाणित जिला घोषित नहीं हो सका है।

● नवीन रघुवंशी

51 हजार से ज्यादा गांवों में की जानी है सप्लाई

अधिकारियों का कहना है कि जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश में 51 हजार से ज्यादा गांवों में नल से जल की सप्लाई की जानी है। जल जीवन मिशन में गांवों की भौगोलिक स्थिति और जल स्रोतों की उपलब्धता के आधार पर दो तरह की योजनाओं पर काम चल रहा है। एकल नल जल योजना और समूह नल जल योजना। प्रदेश के 27 हजार 990 गांवों में एकल नल जल योजनाओं से पानी की सप्लाई की जानी है। शेष गांवों में समूह नल जल योजनाओं पर आधारित प्रोजेक्ट चल रहे हैं। एकल नल जल योजना का काम तेज गति से चल रहा है। इसमें कोई रुकावट नहीं आ रही है। इस योजना का लगभग 90 प्रतिशत काम पूरा हो गया है, जबकि समूह नल जल योजना में कई तरह की रुकावटें आ रही हैं। समूह नल जल योजनाओं का काम अटका होने के कारण कई जिले हर घर प्रमाणित घोषित नहीं हो पा रहे हैं। इनमें भोपाल जिला भी शामिल है। देश के प्रत्येक गांव के हर घर में नल से पानी की सप्लाई के लिए केंद्र सरकार ने 15 अगस्त, 2019 को जल जीवन मिशन लॉन्च किया था। इसकी डेडलाइन मार्च, 2024 तय की गई थी। निर्धारित अवधि में मप्र समेत अधिकतर राज्यों में यह काम पूरा नहीं हो पाया। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन की अवधि वर्ष 2028 तक बढ़ा दी है।

शिकारियों के पंजे में टाइगर स्टेट

मप्र के जंगलों में शिकारियों का जाल इस कदर फैला हुआ है कि यहां रोजाना वन्य प्राणियों के शिकार हो रहे हैं। प्रदेश में प्रोफेशनल शिकारियों का नेटवर्क इतना मजबूत है कि राजधानी भोपाल का वन क्षेत्र हो या प्रदेश का कोई टाइगर रिजर्व, शिकारी आसानी से शिकार कर लेते हैं। चिंता की बात यह है कि सुरक्षा के तमाम दावों के बावजूद मप्र के जंगल में वन्य प्राणियों के शिकार हो रहे हैं। विगत 10 वर्षों में फंदे एवं बिजली लाइन में तार बिछाकर वन्य जीवों के शिकार से संबंधित 750 से अधिक प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जिसमें 35 टाइगर के शिकार प्रकरण भी शामिल हैं। दरअसल, टाइगर स्टेट शिकारियों के पंजे में है। अंतरराष्ट्रीय तस्कारों की डिमांड पर यहां वन्य प्राणियों के शिकार और उनके अंगों की तस्करी हो रही है।

दरअसल, वन्य जीवों के अवैध शिकार के तरीकों में से एक प्रचलित तरीका है फंदा या करंट लगाकर वन्य जीवों का शिकार करना। फंदा, करंट, खटका ऐसे साधन हैं, जो कम जोखिम एवं बिना किसी विशेष तकनीक के शिकारियों को आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। शिकार के इस तरीके में कई बार छोटे वन्य जीवों के अलावा बाघ, तेंदुआ, हाथी, भालू आदि भी शिकार बन जाते हैं। वन विभाग सूत्रों की मानें तो इस तरह के प्रकरणों की समीक्षा में वर्ष 2014 से वर्ष 2024 तक दर्ज हुए प्रकरणों को देखा जाए तो फंदा डालकर या फिर बिजली के तार से 311 जंगली सूअर, 116 नीलगाय, 91 तेंदुए, 77 चीतल, 48 सांभर, 36 भालू, 35 बाघ एवं 17 मोर आदि सहित अन्य वन्य प्राणियों की मृत्यु हुई है।

मप्र फॉरेस्ट और पुलिस की एसटीएफ ने दो महीने पहले जिस पारदी गैंग को पकड़ा था। उससे पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। गैंग के सदस्यों ने बताया कि उन्होंने पिछले 10 सालों में अलग-अलग राज्यों में 10 बाघों का शिकार किया है। उन्होंने ये भी बताया कि म्यांमार के तस्कर लाल नी सुंग के कहने पर उन्होंने शिकार किया है। शिकार के बाद बाघ की खाल और बाकी अंगों को लाल नी सुंग तक पहुंचाने के लिए एक पूरा नेटवर्क काम करता था। इस नेटवर्क में बीएसएफ जवान की पत्नी लिंग सान लून की भी अहम भूमिका थी। एसटीएफ एसपी राजेश भदौरिया बताते हैं, पहले सूचना वन्य प्राणियों के तस्करों से जुड़े होने की ही थी। हमने इनके डेरे पर नजर रखनी शुरू की। पुलिस और फॉरेस्ट की 5 टीमों ने जैसे ही छापा मारा, डेरे के ज्यादातर पुरुष सदस्य जंगल में भाग गए। चार सदस्यों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें नाबालिग भी शामिल था। घर की तलाशी में कुछ नहीं मिला, लेकिन गिरोह के अपराध करने और बचने के तरीके पर ध्यान दिया गया, तो तस्वीर बदल गई। दरअसल, गुना से लेकर राजगढ़ तक सक्रिय पारदी समुदाय लूट के माल को जमीन में गाड़ देता है। इस लीड पर आगे बढ़े। डेरे और आसपास खुदाई की तो 2-3 फीट खोदने पर गांजे के पैकेट मिले। इसके बाद जेसीबी से पूरे इलाके की खुदाई की तो 940 किलो गांजा बरामद हुआ। यहां से वन्यप्राणियों के अंग भी मिले थे। वन्यप्राणियों के अंग और शिकार में इस्तेमाल होने वाले जो फंदे मिले हैं, उसे लेकर महिलाओं ने बताया कि अजीत पारदी के लिए वो वन्य प्राणियों का शिकार करतीं थी। जिस दिन एसटीएफ ने इन तीनों को पकड़ा उस वक्त भी वह वन्य प्राणियों की तस्करी कर रहीं थी। इनके पास से पेंगोलिन की खाल बरामद की गई। महिलाओं ने बताया कि उन्होंने अजीत पारदी के कहने पर बाघों से लेकर कई दूसरे वन्य प्राणियों का शिकार किया। इसके एवज में उन्हें कमीशन मिलता था। साथ ही वन्य प्राणियों की खाल और अंगों को वह असम तक पहुंचाने का काम करती थीं। वन विभाग की स्टेट एसटीएफ के प्रभारी और उप वन संरक्षक रितेश सिरोठिया बताते हैं कि महाराष्ट्र एसटीएफ ने अजीत पारदी से जब पूछताछ की तो पता चला कि वह मप्र में बालाघाट रेंज में शिकार कर चुका है। यहां उसने दो बाघों का शिकार किया था। उसके इकबालिया बयान के आधार पर 18 फरवरी को वन्य प्राणी अधिनियम के तहत दर्ज अपराध क्रमांक 237/17 में नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। सिरोठिया के मुताबिक पूछताछ में पता चला कि म्यांमार के तस्कर लाल नी सुंग के इशारे पर पारदी गिरोह बाघों का शिकार करता था। सिरोठिया के मुताबिक पूछताछ में शिकारियों ने बताया कि वो बाघ को न तो गोली मारते थे, न ही उसे जहर देते थे। गोली मारकर शिकार करने पर बाघ की खाल खराब होने का खतरा होता है, वहीं जहर देकर बाघ को मारने से उसका मांस खराब होने के साथ खाल का रंग भी बदल जाता है। शिकारियों ने बताया कि वो बाघ के गुजरने वाले रास्ते पर पंजा (लोहे का पंजानुमा ट्रैप) लगा देते थे। जब बाघ पंजे में फंस जाता तो उसके थकने का इंतजार करते। बाघ के पूरी तरह से सरेंडर करने के बाद ये लाठियों से उस पर हमला करते। उसकी इस तरह से पिटाई करते, जिससे उसकी जान निकल जाए और खाल भी खराब ना हो। बाघ का शिकार करने के बाद घने जंगल में बड़ी सफाई से खाल, दांत, नाखून और मांस निकालकर इसे अलग-अलग थैलियों में भर लेते थे।

● बृजेश साहू

डिलीवरी के लिए महिलाओं का इस्तेमाल

सिरोठिया बताते हैं कि शिकार के बाद गिरोह वन्य प्राणियों के अंगों को बॉर्डर तक पहुंचाने के लिए महिलाओं का इस्तेमाल करता है। इन्हें किसी सामान के बीच छिपाकर महिलाओं और बच्चों को सौंप दिया जाता है। महिलाएं और बच्चे ट्रेन की जनरल बोगी में किसी सीट के नीचे अपना सामान रखकर दूसरी सीट पर बैठ जाते हैं। वहां से सामान पर नजर रखते हैं। वह ऐसा इसलिए करते हैं, ताकि पुलिस की जांच या किसी अन्य कारण से सामान पकड़ा जाए, तो इसे लावारिस ही माना जाएगा। पूछताछ में ये भी पता चला कि बच्चों को नाबालिग बताने के लिए ग्राम पंचायत से उनका आयु प्रमाण पत्र बनवाते हैं, ताकि पकड़े जाएं तो इसके जरिए बच सकें। सिरोठिया के मुताबिक पारदी गैंग की महिलाएं वन्य प्राणियों के अंगों को मिजोरम लेकर जाती हैं। यहां से बॉर्डर पार कराने की जिम्मेदारी एक बीएसएफ जवान की पत्नी लिंग सान लून की होती है। महाराष्ट्र एसटीएफ को पूछताछ में अजीत पारदी ने बताया कि लिंग सान लून खासी समुदाय की है और म्यांमार की रहने वाली है। उसने जिस जवान से शादी की है वो म्यांमार सीमा पर ही तैनात था। सिपाही की पत्नी होने के नाते उस पर कोई शक नहीं करता था। इस मामले में आईजोल निवासी जामखानकाप उसकी मदद करता था। जामखानकाप को भी महाराष्ट्र एसटीएफ ने पकड़ा, जिसे ट्रांजिट रिमांड पर लेकर मप्र एसटीएफ ने भी पूछताछ की।

निजी निवेशकों को वनीकरण का मौका

पर्यावरणविद् कर रहे नीति का विरोध

पर्यावरणविद् और वन प्रबंधन के जानकार जयंत वर्मा का कहना है कि इस नीति में कई लूप पोल हैं। सरकार जिस जमीन को निजी हाथों में देने जा रही है उसके निजीकरण के पहले केंद्र सरकार से अनुमति लेनी होगी क्योंकि वन भूमि केंद्र का मामला है। इसमें राज्य सरकार अपने मन से कुछ नहीं कर सकती। निजी कंपनियों को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि पर्यावरण सुधरे या वनों की स्थिति सुधरे या फिर उसके क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों का भला हो। निजी कंपनियां तो अपना भला देखेंगी और वह ऐसे पेड़-पौधों का उत्पादन करेंगी, जिनसे ज्यादा मुनाफा होगा। इससे हो सकता है कि वन उपज बढ़ जाए लेकिन पर्यावरण सुधरने की कोई उम्मीद नहीं है। पर्यावरणविद् जयंत वर्मा का कहना है कि इस नीति में जिन बिगड़े वनों की बात की जा रही है, यदि वे किसी गांव के आसपास हैं तो ग्राम सभा की अनुमति लेनी होगी लेकिन यह दिखावा होगा।

मप्र की मोहन सरकार प्रदेश के 40 प्रतिशत जंगलों को निजी हाथों में सौंपने जा रही है। यह जमीन लगभग 37 लाख हेक्टेयर है। इसमें छोटे निवेशकों को 10 हेक्टेयर और बड़े निवेशकों को 1000 हेक्टेयर तक की जमीन पर जंगल विकसित करने का मसौदा तैयार किया है। निजी कंपनियों को यह जमीन 60 साल की लीज पर दी जा रही है। राज्य सरकार का दावा है कि जो बिगड़े हुए वन हैं जिन्हें निजी निवेश से सुधारने की कोशिश की जाएगी। वनीकरण की लागत 5 लाख रुपए से 8 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर के बीच होने का अनुमान है। यह वहां के स्थान, भूमि के आकार, मिट्टी की स्थिति और जलवायु जैसे कारकों पर निर्भर करता है। राज्य के वन विभाग द्वारा जारी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर), कॉर्पोरेट पर्यावरण उत्तरदायित्व (सीईआर) की एक मसौदे से पता चलता है कि मप्र के 95 लाख हेक्टेयर वन में से 37 लाख हेक्टेयर क्षरित वन के रूप में चिन्हित किया गया है। इस मसौदे का मुख्य उद्देश्य है कि वनों की बहाली के लिए निजी संस्थाओं को शामिल करना है, क्योंकि इस तरह के बड़े पैमाने पर की जाने वाली पारिस्थितिक बहाली के लिए वास्तव में सरकारी धन की कमी है।

मसौदे में बताया गया है कि इस पहल का उद्देश्य हरित आवरण को और अधिक बढ़ाना है। इससे पारिस्थितिक सेवाएं प्रदान करने और स्थानीय समुदायों के लिए वन-आधारित आजीविका को और अधिक मजबूती मिलेगी। मसौदे में कहा गया है कि वनीकरण की लागत 5 लाख रुपए से 8 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर के बीच होने का अनुमान है, जो स्थान, भूमि के आकार, मिट्टी की स्थिति और जलवायु जैसे कारकों पर निर्भर करता है। इस पहल के लिए सीएसआर और सीईआर के पैसों का उपयोग किया जाएगा। औद्योगिक समूह, कॉर्पोरेट संस्थाएं, व्यक्ति और स्वैच्छिक संगठन 60 साल की अवधि के लिए न्यूनतम 10 हेक्टेयर से लेकर अधिकतम 10,000 हेक्टेयर तक की क्षरित वन भूमि का चयन करके राज्य के वनीकरण में भाग ले सकते हैं। इस मसौदे के अंतर्गत निवेशकों को 60 साल की अवधि के लिए कार्बन क्रेडिट का अधिकार होगा, जिसमें संयुक्त वन प्रबंधन समितियां (जेएफएमसी) इन क्रेडिट में 10 प्रतिशत हिस्सा बनाए रखेंगी। निवेशक पौधारोपण के लिए पौधों की प्रजातियां और किस्मों का चुनाव कर सकते हैं, हालांकि इस मामले में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विदेशी प्रजातियों के पौधों के रोपण का उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। यही नहीं निवेशकों को कोई भी भूमि स्वामित्व का अधिकार नहीं दिया जाएगा और राज्य सरकार के पास पेड़ों से प्राप्त होने वाली लकड़ी के स्वामित्व का अधिकार होगा। मसौदे में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980, भारतीय वन अधिनियम 1927 और अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 सहित मौजूदा कानूनों का पालन कड़ाई से लागू किया गया है। निवेशकों को मप्र राज्य वन विकास निगम (एमपीएसएफडीसी) और जेएफएमसी के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा। इसमें प्रत्येक हितधारक की भूमिका और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से बताया गया है।

वन उपज का जेएफएमसी को 20 प्रतिशत, निगम को 30 प्रतिशत और निवेशक को 50 प्रतिशत का वितरण अनुपात सुनिश्चित किया गया है। निगम वन उपज की देखरेख करेगा, जिसमें लागत आनुपातिक रूप से सभी के साथ साझा की जाएगी। उपज को खुली निविदा के माध्यम से नीलाम किया जाएगा, जिसमें निवेशक को उच्चतम बोली लगाने का पहला अधिकार होगा। मसौदा नीति में कहा गया है कि निवेशकों को केंद्र सरकार के निर्धारित मानदंडों के अनुसार ही कार्बन क्रेडिट का अधिकार होगा। इन क्रेडिट का उपयोग समझौते की अवधि के लिए किया जा सकता है, जिसमें जेएफएमसी क्रेडिट में 10 प्रतिशत हिस्सेदारी बनाए रखेगा।

राज्य सरकार ने अपनी नीति में लिखा है कि वह इन जंगलों को निजी हाथों में देने जा रही है। इन जंगलों को फिर से हरा-भरा करने के लिए बड़ी कंपनियों के कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी और कॉरपोरेट एनवायरमेंटल रिस्पांसिबिलिटी के फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। दरअसल बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों को इन दोनों मदों में अपनी कुल कमाई का 3 प्रतिशत देना होता है। राज्य सरकार ने अपनी नीति में बताया है कि एक कंपनी, संस्था, व्यक्ति या स्वयंसेवी संस्था को 10 हेक्टेयर तक का बिगड़ा जंगल दिया जाएगा। ये जंगल का हिस्सा अगले 60 सालों तक निजी हाथों में रहेगा। राज्य सरकार के वन विभाग और जिसे जंगल दिया जा रहा है उसके बीच में एक अनुबंध होगा। इस अनुबंध के तहत अनुबंध के पहले ही साल में जंगल सुधारने की गतिविधि शुरू करनी होगी। वन भूमि का इस्तेमाल दूसरे किसी काम में नहीं किया जाएगा। वन विभाग की सहमति से इस पूरे इलाके में पौधे लगाने होंगे। और यदि 2 साल के भीतर पौधे नजर नहीं आएंगे तो अनुबंध रद्द भी किया जा सकता है।

● **हर्ष सक्सेना**

बुंदेलखंड में विकास की दौड़

मप्र और उप्र में फैला बुंदेलखंड एक ऐसा क्षेत्र होगा, जो दोनों बड़े राज्यों के औद्योगिक शहरों को जोड़ने का काम करेगा। यह दोनों नेशनल हाईवे बुंदेलखंड की तस्वीर बदलेंगे, जिसका फायदा इन दोनों राज्यों को भी होगा। इन दोनों नेशनल हाईवे से आप मप्र के बुंदेलखंड, इंदौर, भोपाल, देवास और उप्र के कानपुर, वाराणसी और लखनऊ जैसे बड़े शहरों से जुड़ जाएंगे। यह दोनों हाईवे जब बन जाएंगे तो इससे समय की बचत होगी। इन हाईवे से जाने पर जो शहर पड़ेंगे, उन तक पहुंचने में आधा समय लगेगा। इन दोनों हाईवे के निर्माण के बाद बुंदेलखंड में विकास के पंख लग जाएंगे। इसके अलावा यहां पर्यटन, लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में बड़ा बदलाव हो जाएगा।

उप्र में सरकार की कमान संभालने के बाद आठ वर्षों के कार्यकाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने महत्वपूर्ण फैसलों से प्रदेश के सभी हिस्सों को विकास की योजनाओं से जोड़ने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। योगी सरकार की पहलों ने उपेक्षित बुंदेलखंड को विकास की रेस में शामिल किया और इस क्षेत्र के लिए की गई पहलों ने तस्वीर को बदलने का काम किया है। विकास योजनाएं यहां तेज गति से आकर लेती दिख रही हैं। झांसी और चित्रकूट जिले में डिफेन्स कॉरिडोर को विकसित करने के अंतर्गत जमीन अधिग्रहण का काम पूरा होने के बाद अब यूनिट की स्थापना का काम भी जोर पकड़ रहा है। झांसी नोड में बीडीएल ने वर्ष 2023 में यूनिट की स्थापना का काम शुरू कर दिया था और इस पर तेज गति से काम चल रहा है। डिफेन्स कॉरिडोर क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं के विकास पर तेज गति से काम चल रहा है। सड़क, बिजली और पानी की उपलब्धता के लिए संबंधित विभागों की मदद से व्यवस्थाएं पूरी की जा रही हैं। चित्रकूट नोड में भी जमीन अधिग्रहण का काम पूरा हो चुका है।

योगी सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र को एक्सप्रेस-वे से जोड़ने का काम किया। यहां 296 किमी लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे का लोकार्पण वर्ष 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। बुंदेलखंड का यह पहला एक्सप्रेस-वे चित्रकूट से शुरू होकर बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया होते हुए इटावा में आगरा एक्सप्रेस-वे पर समाप्त होता है। बुंदेलखंड क्षेत्र को देश की राजधानी से जोड़ने और इस क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इसे तैयार किया गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे पर सरकार औद्योगिक गलियारे के निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण का काम कर रही है। बुंदेलखंड के चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा और जालौन जिलों में कॉरिडोर के अंतर्गत औद्योगिक शहर तैयार किया जाएगा। बुंदेलखंड के पांच जिलों के अलावा इस एक्सप्रेस-वे पर स्थित औरैया जिले में भी औद्योगिक शहर बसाया जाएगा। छह जिलों की 1911 हेक्टेयर जमीन पर कॉरिडोर का निर्माण होगा। सभी जिलों में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है।

बुंदेलखंड क्षेत्र में औद्योगिक विकास को गति देने और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सरकार ने नोएडा की तर्ज पर एक नया औद्योगिक शहर झांसी में स्थापित करने का निर्णय लिया, जिसे बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण का नाम दिया गया। इस परियोजना के तहत 56662 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाना है, जिसमें अब तक लगभग 17,000 एकड़ भूमि किसानों से क्रय कर ली गई है। किसानों को इसके बदले 2500 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है। सिंगापुर की प्रसिद्ध मास्टर प्लानिंग कंपनी द्वारा बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण के लिए मास्टर प्लान को अंतिम रूप दे दिया गया है। इस क्षेत्र के औद्योगिक और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए विजन डॉक्यूमेंट भी तैयार कर लिया गया है। योगी सरकार ललितपुर जिले में बल्क ड्रग पार्क का निर्माण करा रही है। ललितपुर में बल्क ड्रग फार्मा पार्क के निर्माण के लिए अधिग्रहीत भूमि को राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित किया गया है। जनपद ललितपुर में फार्मा पार्क स्थापित करने के लिए राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र सैदपुर-ललितपुर पर पशुपालन विभाग के स्वामित्व वाली भूमि में से 1472.33 एकड़ भूमि को राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण हस्तांतरित किया गया है। चयनित जमीन पर बाउंड्रीवाल बनाने सहित अन्य प्रक्रिया पूरी की जा रही है। यहां पानी के लिए सिंचाई विभाग से समझौता हुआ है।

● **सिद्धार्थ पांडे**

2 नए नेशनल हाईवे बनने से बढ़ेंगे प्रॉपर्टी के दाम

बुंदेलखंड की जल्द ही तस्वीर बदलने वाली है। यहां पर बनाए जा रहे दो नेशनल हाईवे सागर कानपुर नेशनल हाईवे तथा बुंदेलखंड विकास पथ का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। 2026 तक इन दोनों को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद बुंदेलखंड की तस्वीर और तकदीर दोनों ही बदल जाएंगी। यहां रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और बड़ा बदलाव होगा। इस समय सागर से कानपुर जाने के लिए सड़क या रेलमार्ग से 7 से 8 घंटे का समय लग जाता है। सागर-कानपुर हाईवे पूरा होने के बाद यह सफर केवल 3 घंटे में ही पूरा किया जा सकेगा। सागर से 112 किलोमीटर का कानपुर-सागर नेशनल हाईवे बनाया जा रहा है। इस पूरे प्रोजेक्ट को 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस समय यह नेशनल हाईवे दो लाइन का है। इस कारण यहां पर ट्रैफिक व्यवस्था की बहुत बड़ी समस्या है। कानपुर, वाराणसी, लखनऊ और इलाहाबाद जाने वाले वाहनों के कारण इस पर बहुत दबाव रहता है। आए दिन यहां जाम लगता रहता है। इन दोनों नेशनल हाईवे के बनने से बुंदेलखंड को व्यावसायिक रूप से बड़ा लाभ होगा। इससे खजिन व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा और पर्यटन को भी पंख लगेंगे। मप्र के बुंदेलखंड में खजुराहो, ओरछा, पन्ना के पर्यटन व्यवसाय को इससे खासा लाभ होगा। वहीं उप्र के बुंदेलखंड के झांसी, चित्रकूट और महोबा के पर्यटन स्थल भी इससे कनेक्ट हो जाएंगे। नेशनल हाईवे के किनारे लॉजिस्टिक हब, ट्रांसपोर्ट व्यवसाय, कृषि और दूसरे व्यवसाय के बाजार भी आपस में जुड़ जाएंगे।

22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकिस्तान (पाकिस्तान) ने 26 लोगों को जिस तरह धर्म पूछ-पूछकर मौत के घाट उतारा, उसका बदला भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत सूद सहित ले लिया है। हमारी तीनों सेनाओं ने आतंकिस्तान के दुस्साहस को चित तो कर ही दिया, साथ ही 2 बाहुबलियों अमेरिका और चीन को भी आपना दम दिखा दिया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ कर दिया है कि साथ-साथ नहीं बहेंगे पानी और खून।

● राजेंद्र आगाल

पहलगाम में आतंकियों के हमले के बाद भारत ने 6-7 मई की आधी रात आतंकवाद के गढ़ पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के तहत सटीक, संयमित और नैतिक प्रतिशोध का परिचय दिया। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना ने जिस सटीकता के साथ पाकिस्तान की सरपरस्ती में पल रहे आतंक के आकाओं के 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया, उससे पूरे विश्व ने भारत की सैन्य क्षमता का लोहा मान लिया। यही नहीं इस ऑपरेशन से आहत होकर पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ चीनी-तुर्किए के आधुनिक स्तरों के साथ जंग छेड़ दी, उसका हिंदुस्तान ने जिस तरह मुंहतोड़ जवाब दिया, उससे भारत की सामरिक शक्ति को पूरे विश्व ने देख लिया। यही नहीं विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर भारत ने पाकिस्तान की गुहार पर जिस तरह 4 दिन में युद्ध को रोक दिया, उससे पूरे विश्व में यह भी संदेश गया कि भारत बेवजह युद्ध करने के पक्ष में नहीं है।

ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य अभियान नहीं था, यह भारत की चेतना, उसके राष्ट्रभाव और उसकी सभ्यता पर आघात का वैचारिक उत्तर था। पहलगाम में 22 अप्रैल को धर्म पूछ-पूछ कर मार दिए गए हिंदू यात्रियों की चिताओं से उठता धुंआ आकाश में मिलने से पहले जिहादी आतंकवाद को राख करने का संकल्प लिख रहा था। जो लोग भारत को एक सांस्कृतिक राष्ट्र की बजाय राजनीतिक दलों के खांचे में बंटा देखने के आदी हैं, उनके लिए यह आंखें खोलने वाला क्षण है। भारत का यह राष्ट्रभाव केवल सीमाओं की सुरक्षा तक सीमित नहीं। यह मां की वंदना, स्त्रीत्व के गौरव और सभ्यता की अस्मिता की रक्षा का भाव है। जब आतंकियों ने बहनों से धर्म पूछकर उनका सिंदूर मिटाया, तब यह केवल दुखद घटना भर नहीं थी, यह हमारी संस्कृति, हमारी सहिष्णुता और हमारी सामूहिक चेतना पर दुस्साहसी आघात था। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इसी दुस्साहस को दहलाने वाला संदेश दिया। ऑपरेशन सिंदूर केवल भौगोलिक लक्ष्य नहीं था, केवल खाकी तक सिमटी सैन्य कार्रवाई नहीं थी। यह भारत के सम्मान को सर्वोपरि रखने वाली वैचारिक स्पष्टता थी।

अंदर घुसकर मारता है नया भारत

पहलगाम में आतंकियों के हाथों हुआ नरसंहार केवल निर्दोष लोगों के जीवन पर हमला नहीं था। यह भारत की अंतरात्मा पर भी किया गया आक्रमण था। इसके प्रत्युत्तर में भारत ने आतंकवाद रोधी कार्रवाई की नियम पुस्तिका के पुनर्लेखन का निर्णय लिया। ऑपरेशन सिंदूर वास्तव में राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों की रक्षा के लिए मोदी सरकार की आतंक को बर्दाश्त न करने और कोई समझौता न करने की नई नीति है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मौजूद जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी शिविर, पाकिस्तानी पंजाब के आतंकी प्रशिक्षण केंद्र, मस्जिदों और मदरसों की आड़ में चल रही जिहादी प्रयोगशालाएं-इन सभी को भारत ने चिह्नित कर, सटीकता से ध्वस्त किया। यह एक संदेश था कि भारत अब केवल सहिष्णु पीड़ित नहीं, सजग उत्तरदाता है। भारत ने विगत दशकों में संयम और संवाद की नीति अपनाई। किंतु 2016 में उरी सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद यह स्पष्ट हो गया कि भारत ने संयम को कमजोरी मानने वाले को सुधारने का तरीका निकाल लिया है। 2025 में ऑपरेशन सिंदूर संयम से शक्ति का अगला सोपान है। भारत ने पहली बार आतंक के अड्डों को इस स्तर पर निशाना बनाया। पाकिस्तानी मीडिया ने इसे मजहब पर हमला बताने की कोशिश की, किंतु मुद्दा लौटकर उन्हीं पर गिरा-यदि आतंक का कोई मजहब नहीं होता, तो फिर उनके ठिकानों की मजहबी पहचान क्यों?

पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों का कंट्रोल यूएसए के पास

पाकिस्तान के परमाणु बम पाकिस्तान के नहीं थे। वह सब के सब अमेरिका के थे। जिसे उसने पाकिस्तान में बेस बनाकर रखा हुआ था। सिंदूर ऑपरेशन और इस सैन्य संघर्ष ने वह सारे रहस्य और भेद उजागर कर दिए हैं जो पहले चारदीवारी तक सीमित थे। कई झूठ और भ्रांतियों की भी पोल खोली गई है जिसके बारे में फर्जी इतिहास बताया जाता हैं। अमेरिका पाकिस्तान को अपने परमाणु ठिकाने बने रहने देना चाहता है। पाकिस्तान परमाणु शक्ति नहीं है। अपितु अमेरिका द्वारा स्थापित परमाणु ठिकाने हैं वहां। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे तुर्किए में अमेरिका के परमाणु ठिकाने हैं रूस के विरुद्ध। पाकिस्तान की परमाणु धमकी पिछले 2 बार से गीदड़ भभकी इसीलिए साबित हुई। क्योंकि पाकिस्तान स्थित परमाणु केंद्रों का कंट्रोल और रिमोट अमेरिका के हाथ में है। जिस प्रकार रूस को काउंटर करने के लिए तुर्किए में परमाणु ठिकाना स्थापित किया था। अमेरिका ने उसी प्रकार एशिया में अपने शत्रुओं को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान में परमाणु ठिकाने स्थापित किए थे। अमरीका ने जब ये ठिकाने स्थापित किए गए थे उन दिनों यहां से दक्षिण सोवियत यूनियन और भारत को काउंटर करने की सोच रही इसके पीछे। अब अमेरिका को अपने द्वारा स्थापित पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने पर भारतीय सेना की ओर से खतरा जैसे ही नजर आया, वो तुरंत बिलबिला उठा और अपने स्थापित किए रणनीतिक परमाणु ठिकाने बचाने के लिए सीजफायर का खेल खेला। अमेरिका यह सब दुनियाभर पावर बैलेंस के लिए करता था। इसमें अमेरिकन डीप स्टेट के गहरे और दूरगामी हित निहित हैं। जब तक पाकिस्तान में अमेरिका के परमाणु ठिकाने बने हुए हैं, पाकिस्तान को अमेरिकी इमदाद (आर्थिक मदद) मिलती रहेगी।

आतंकवाद के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अपेक्षाएं जताते बयान हों या जिनेवा कन्वेंशन के विभिन्न बिंदु, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में सभी का अनुपालन किया।

क्षमता का कोई दुरुपयोग नहीं, सभी निशाने-पूर्व प्रमाणित आतंकी शिविरों पर। यह मानवाधिकारों का संतुलन रखते हुए आतंकवाद के विरुद्ध दृढ़ता से आगे बढ़ने की वह बात है, जो भारत का नैतिक आधिपत्य बनाए रखती है। भारत के हमलों की सटीकता के संदर्भ में पूर्व की विभिन्न मीडिया रिपोर्ट और रॉ की खुफिया सूचना लक्ष्यों के आतंकी चरित्र की पुष्टि करती हैं। यह सिद्ध करता है कि भारत ने न्यायोचित शक्ति का प्रयोग किया। यह भी उल्लेखनीय है कि ऑपरेशन के पश्चात पाकिस्तान ने न केवल अपने एयरस्पेस को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित किया, बल्कि कई अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को मोड़ दिया। आतंरिक स्तर पर सोशल मीडिया ब्लैकआउट जैसी घटनाओं और आतंकी ठिकानों की अज्ञात गंतव्य पर तैनाती से यह स्पष्ट होता है कि वह भीतर से घबराया हुआ है। यह संकेत है कि आतंक के सहारे टिका राष्ट्र अब अपने ही नेटवर्क से डर रहा है।

सभ्यता बनाम बर्बरता का संघर्ष

आज भारत केवल क्षेत्रीय शक्ति नहीं, सभ्यता और मानवता का रक्षक दिख रहा है। वैश्विक विमर्श की दृष्टि से यह सभ्यता बनाम बर्बरता का संघर्ष है। एक ओर पाकिस्तान है-ओसामा बिन लादेन को पनाह देने वाला, एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में वर्षों तक का दागी, हिंदू, सिख, ईसाई, शिया, अहमदी-सभी की आस्था और पहचान लील जाने वाला। एक ऐसा कबीलाई हुजूम जहां बाल-विवाह, भीड़ द्वारा हत्या और स्त्रियों के अधिकारों को रौंदना सामान्य ही नहीं, बल्कि सही समझा जाता है। दूसरी ओर भारत है-20 करोड़ मुसलमानों के साथ लोकतांत्रिक सह-अस्तित्व के पथ पर बढ़ता... मजहब नहीं,

पाकिस्तान की बौखलाहट

भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर पाकिस्तान द्वारा तोपों से गोलाबारी शुरू करने से तनाव बढ़ता गया। भारत भी दमदार जवाब देता रहा, लेकिन केवल एलओसी स्थित सैन्य ठिकानों पर। दुखद बात यह है कि पाकिस्तान एलओसी के पास के भारतीय गांवों पर हमला कर रहा था, जिससे भारी संख्या में नागरिक हताहत हो रहे थे। यह पाकिस्तान द्वारा जिनेवा समझौते का एक और गंभीर उल्लंघन था, जिसे भारत सरकार को संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठाना चाहिए। भारतीय सेना के ऑपरेशन के बाद 7 मई को पाकिस्तान के शेयर बाजार इक्विटी सूचकांक में करीब छह प्रतिशत की गिरावट आई। यह 2021 के बाद सबसे बड़ी गिरावट है और गंभीर चिंता का विषय है। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने इस चुनौती पर प्रकाश डाला है कि भारत के साथ तनाव जारी रहने पर पाकिस्तान का आर्थिक विकास प्रभावित होगा। कुल मिलाकर, सैन्य वृद्धि पाकिस्तान की वित्तीय कठिनाइयों से उबरने की पहले से ही कठिन यात्रा को और अधिक प्रभावित करेगी। लेकिन पूरा संयम रखते हुए अंततः 8 मई को भारत ने पाकिस्तान की बेशर्म हिमाकत का कड़ा जवाब देना शुरू किया और देखते-देखते उसे घुटनों पर ला दिया। 7 से लेकर 10 मई तक सीमा पर तनाव बना हुआ था। उसके बाद सीजफायर का ऐलान कर दिया गया और युद्ध रोक दिया गया। लेकिन भारत ने पाकिस्तान को साफ संदेश दे दिया है कि अगर भविष्य में आतंकी हमले होते हैं तो भारत चुप नहीं बैठेगा।

आतंक की पहचान के आधार पर कार्रवाई करता, अत्यंत कठिन परिस्थितियों में भी जेनेवा कन्वेंशन और मानवाधिकारों को दृष्टिगत रखता। एक और कोविड जैसी वैश्विक आपदा के दौरान विश्व के सैकड़ों देशों के लिए वैक्सीन के रूप में जीवन की सौगात देता भारत है, दूसरी ओर पूरे विश्व में जिहादी उपद्रव के लिए आतंकियों को प्रशिक्षण के बाद निर्यात करने का कारखाना-पाकिस्तान। विश्व अब तय कर सकता है-यह संघर्ष भारत बनाम पाकिस्तान नहीं, यह संघर्ष सभ्यता बनाम बर्बरता है।

भारत ने दशकों तक तटस्थता और नैतिक अपीलों की राजनीति की। लेकिन अब स्पष्ट है कि बातचीत से नहीं, नीति और साहस से भारत के हित सर्वोपरि रखते हुए उत्तर दिया जाएगा। भारत केवल अपनी रक्षा नहीं कर रहा, वह वैश्विक सभ्यता की अग्रिम पंक्ति में खड़ा है। ऑपरेशन सिंदूर ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत अब बदल चुका है। यह देश अब कश्मीर से कन्याकुमारी तक अपने हर नागरिक की अस्मिता की रक्षा करेगा। यह अब केवल लड़ाई नहीं लड़ेगा, रणनीतिक विचार की संकीर्ण व्याख्याओं को भी पुनः परिभाषित करेगा। भारत सिर्फ भूगोल नहीं है, यह कोई राजनीतिक इकाई भर नहीं है, यह एक जाग्रत राष्ट्र है। जब प्रश्न सिंदूर का हो, तब उत्तर वज्र होता है! पाकिस्तान ने पहलगाम में आतंकी हमला क्यों करवाया? यह प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। दरअसल, पाकिस्तान इन दिनों राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तानी आवाम में उसकी सेना के प्रति रोष है। पाकिस्तानी सेना की प्रतिष्ठा लगातार गिर रही है क्योंकि वह बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान के खिलाफ हो रहे विद्रोह को दबाने में अभी तक नाकामयाब रही है। ऐसे में पाकिस्तान को इन तमाम मुद्दों से अपनी आवाम का ध्यान भटकाना था। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने पहलगाम हमले से कुछ ही दिन पहले बेहद जहरीला भाषण दिया था। पाकिस्तानी आवाम और सेना में असंतोष बढ़ता देख मुनीर ने हमेशा की तरह कश्मीर राग अलापना शुरू कर दिया। नतीजतन इस हमले को अंजाम दिया गया।

भारत-पाकिस्तान समीकरण

इस मौके पर यह समझना बेहद जरूरी है कि वर्तमान में भारत और पाकिस्तान दोनों देशों की स्थिति क्या है। एक तरफ भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, वहीं पाकिस्तान अपनी मौजूदा वित्तीय प्रतिबद्धताओं को भी पूरा नहीं कर पा रहा है। उसकी आर्थिक वृद्धि दर मात्र 0.4 प्रतिशत रह गई है। जाहिर है, ऐसे में पाकिस्तान भारत को चुनौती दे पाने की स्थिति में नहीं है। यदि सेना की बात करें तो भारत रक्षा खर्च में विश्व में पांचवें नंबर पर है। पाकिस्तान भारत से बहुत पीछे है। भारत का रक्षा बजट लगभग 80 अरब डॉलर है, जबकि पाकिस्तान का बजट लगभग 10 अरब डॉलर है यानी भारत से आठ गुना कम। भारतीय सशस्त्र बल संख्यात्मक और गुणात्मक, दोनों ही स्तर पर पाकिस्तान से बेहतर हैं। यदि पाकिस्तान से युद्ध होता है तो भारत लंबे समय तक लड़ाई लड़ने में सक्षम है। पाकिस्तान की ऐसी स्थिति नहीं है। पाकिस्तानी डीप स्टेट की सोच बेहद कट्टरपंथी हैं। हम कितना भी प्रयास करें, वह भारत के प्रति अपना रवैया और सोच कभी नहीं बदल सकते।

भारत ने सैन्य कार्रवाई तो की है, लेकिन गैर सैन्य कार्रवाई के तहत भी पाकिस्तान को सबक सिखाने की पूरी तरह तैयारी कर ली है। सिंधु जल संधि को निलंबित करने के अलावा पाकिस्तान से व्यापार बंद करना आदि इसी रणनीति के तहत की गई कार्रवाई है। सिंधु जल संधि के निलंबित हो जाने से पाकिस्तान के किसानों में भय व्याप्त हो गया है। सिंधु नदी कृषि और जल आपूर्ति की दृष्टि से पाकिस्तान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यह नदी पाकिस्तान की 80 प्रतिशत खेती योग्य भूमि को पानी प्रदान करती है, जो देश की 60 प्रतिशत से अधिक आबादी का भरण-पोषण करती है। ऐसे में इस संधि का निलंबित होना पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय है। भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला करके अपनी मंशा साफ जता दी है। यह पाकिस्तान के लिए एक चेतावनी भी है कि वह जिन आतंकियों को अपने यहां पनाह देता है, वे कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। भारत की पहुंच पाकिस्तान के हर आतंकी ठिकाने तक है। भारत के हमले से बौखलाई पाकिस्तानी सेना सीमा पर लगातार गोलाबारी कर रही है। इसमें सीमा के पास के पुंछ जैसे इलाकों में रहने वाले कई निर्दोष भारतीयों की मौत हो चुकी है। भारतीय सेना पाकिस्तान को इसका कड़ा प्रत्युत्तर दे रही है। यदि पाकिस्तान ने उकसाने वाली हरकतें बंद नहीं की तो यह उसके लिए ही घातक होगा। अब यह पाकिस्तान के ऊपर है कि वह भारत के सीमावर्ती इलाकों और भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमला करके युद्ध को आगे बढ़ाता है या अपना कदम पीछे खींच लेता है। यदि पाकिस्तान नहीं मानता तो यह तय है कि भारत की तरफ से उसे कठोर प्रतिक्रिया मिलेगी। भारत ने अपना इरादा पाकिस्तान को जता दिया है।

योजनाबद्ध था हमारा हमला

लश्कर-ए-तैयबा के मुखौटा संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) ने हमले की जिम्मेदारी ली थी। बाद में जब पाकिस्तान पर दबाव बढ़ने लगा और उसके हुकमरानों को लगा कि मामला बिगड़ सकता है तो उसने अपना बयान वापस ले लिया। भारत ने पाकिस्तान में आतंकवादी संगठनों के मुख्यालय पर हमले किए, न कि सैन्य ठिकाने पर यह कार्रवाई किसी की अर्थव्यवस्था को गिराने की या नागरिकों के खिलाफ नहीं थी। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने आतंकी ठिकानों की जानकारी जुटाई, उसे सैन्य बलों के साथ साझा किया। इसके बाद बेहद सधे तरीके से कार्रवाई की गई। जिसमें बड़ी संख्या में प्रक्षिशु आतंकी और कुछ बड़े कमांडर भी मारे गए। यह संभव नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर आतंकी संगठनों ने अपने ठिकाने बना रखे हों और उसे खबर नहीं। इसके दो मायने निकलते हैं, या तो पाकिस्तान इन आतंकी संगठनों का समर्थन कर रहा है, या फिर वह इन आतंकी संगठनों से डरता है। उसके पास उन्हें काबू में रखने की क्षमता नहीं है। यदि ऐसा होता तो पाकिस्तान को भारत के इस कदम का स्वागत करना चाहिए था, क्योंकि वह यह दावा करता है कि आतंकवाद से उसका कुछ लेना-देना नहीं। ऐसे में भारत ने पाकिस्तान को आतंकवादियों से छुटकरा दिलाया है। हमने उनकी धरती पर जाकर आतंकवादी संगठनों को खत्म किया। एक तरह से हमने तो पाकिस्तान की आतंकवाद से लड़ने में मदद ही की। दरअसल, पाकिस्तान को वहां चुनी हुई सरकार नहीं, बल्कि पाकिस्तान की सेना चलाती है। पाकिस्तान के अंदर उसका ही प्रभुत्व है, सेना ऐसा चाहती भी नहीं है कि उसका रुतबा वहां कम हो। इसके चलते सोची-समझी साजिश के तहत वह भारत विरोध को हवा देती रहती है। वह लोगों को बार-बार यह अहसास करवाती है कि पाकिस्तान को भारत से खतरा है। उसका अस्तित्व खतरे में है।

कंगाली की कगार पर पाक

पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति तो बदहाल है ही, उसके पास इतना गोला-बारूद भी नहीं है। पाकिस्तान की ऐसी स्थिति ही नहीं है कि वह भारत के साथ ज्यादा दिनों तक युद्ध कर सके। कंगाली की कगार पर खड़े पाकिस्तान ने अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए पिछले दिनों बड़ी मात्रा में अपने हथियार और गोला-बारूद यूक्रेन को बेच दिए थे। उसके पास युद्ध लड़ने के लिए हथियारों की काफी कमी है। पाकिस्तान अभी तक अपने पैरों पर खड़ा है, क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब ने काफी धन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा कर रखा है। इसके बलबूते पाकिस्तान को इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से पैसा मिल जाता है। इसी के मद्देनजर पाकिस्तान को एक और बड़ी किस्त मिलने वाली थी। उस पर भी अब प्रश्नचिन्ह खड़ा हो गया है। भारत ने पाकिस्तान को मदद मुहैया कराने वाले सभी चैनलों को कहा है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को प्रश्रय देता है, आतंकवाद को बढ़ावा देता है, इसलिए उसकी मदद नहीं की जानी चाहिए।

पाकिस्तान जो उत्पाद निर्यात करता है उनको भी हम रोक सकते हैं। पाकिस्तान सबसे ज्यादा कपास निर्यात करता है, अमेरिका को भी बड़ी मात्रा में कपास का निर्यात करना है, लेकिन फिलहाल उस पर प्रश्नचिन्ह लगा हुआ है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान पर जो टैरिफ लगाया है वह भारत और बांग्लादेश के मुकाबले बहुत ज्यादा है। यदि भारत चाहे तो कपास के बाजार से पाकिस्तान को बाहर निकाल सकता है। इसके अलावा भारत को यूरोपीय संघ (ईयू) से बात करनी चाहिए, क्योंकि उसने पाकिस्तान को जेनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रीफरेंसेज प्लस (जीएसपी प्लस) दर्जा दे रखा है। इससे पाकिस्तान को फायदा मिल जाता है। यदि इसको हटा दिया जाए तो उसका निर्यात कम हो जाएगा।

अधिकांश देश नहीं चाहते युद्ध

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखें तो अधिकतर देश नहीं चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध बढ़े। दोनों परमाणु संपन्न देश हैं। ऐसे में उनकी भी कोशिश यही है कि किसी तरीके से युद्धविराम हो जाए। अमेरिका ने यह कहा भी है कि जल्दी से मामला खत्म हो जाए। चीन ने भारत की कार्रवाई को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वह आगे कुछ

भारत का अमेरिका को जवाब तीसरे पक्ष की कोई एंट्री नहीं

भारत ने आतंक के खिलाफ केवल एक नई और कठोर नीति ही नहीं अपना ली है, बल्कि आतंकियों एवं उनका साथ देने वालों में भेद करना भी छोड़ दिया है। इसके अतिरिक्त यह भी निश्चय किया है कि परमाणु हथियारों की धमकी सहन नहीं की जाएगी। पाकिस्तान को यह समझना होगा कि खून और पानी एक साथ न बहने का क्या मतलब है। यह संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दे दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान से केवल आतंक और उसके कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर पर बात होगी। यह बयान साफतौर पर पाकिस्तान के साथ ही अमेरिका को भी ध्यान में रखकर दिया गया, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव थमने का श्रेय लेने के साथ ही कश्मीर मसले पर बीच-बचाव करने की भी पहल की। हद तो तब हो गई, जब उन्होंने यह कह दिया कि दोनों देश अमेरिका के साथ व्यापार करने के कारण सैन्य संघर्ष रोकने पर सहमत हुए। ट्रंप के बयान को सिरे से खारिज करना केवल इसलिए जरूरी नहीं था कि यह जम्मू-कश्मीर पर भारत की नीति से मेल नहीं खाता, बल्कि इसलिए भी कि अमेरिकी राष्ट्रपति एक तरह से आतंक को व्यापार से जोड़ रहे हैं। यह किसी को भी स्वीकार्य नहीं हो सकता और भारत को तो कदापि नहीं, जो ऐसे आतंकवाद से जूझ रहा है, जिसका पोषण पाकिस्तान की सरकार और सेना करती है। शायद इसी कारण प्रधानमंत्री को यह कहना पड़ा कि आतंक और व्यापार साथ-साथ नहीं चल सकते। निसंदेह ट्रंप बड़बोले राष्ट्रपति हैं और किसी भी मसले पर कुछ भी अनाप-शनाप कह जाते हैं और फिर उससे पलट भी जाते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि उन्हें जवाब न दिया जाए।

करेगा। चीन की कोशिश सिर्फ वक्तव्यों तक ही सीमित रहने वाली है। चीन इस वक्त भारत से अच्छे संबंधों का इच्छुक है और वह यह नहीं चाहेगा कि इस वक्त इस विषय पर भारत से उसके संबंध खराब हों। जहां तक सवाल तुर्किए का है तो वह हम मजहबी होने के नाम पर पाकिस्तान के साथ खड़ा है। वह पाकिस्तान की मदद करने की कोशिश भी करेगा, लेकिन वह अपनी सेना को पाकिस्तान के साथ उतारेगा, ऐसा नहीं दिखाई देता। अधिकांश अंतरराष्ट्रीय समुदाय भी यही चाहेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध न हो।

सबसे बड़ा खलनायक मुनीर

पहलगाम अटैक के बाद भारत-पाक के बीच बढ़े तनाव के बीच पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान में सबसे बड़े खलनायक बनकर उभर रहे हैं। भारत ही नहीं पाकिस्तान में भी लोग मान रहे हैं कि भारत-पाक के बीच युद्ध जैसी स्थिति के लिए मुनीर ही जिम्मेदार हैं। आज 1971 के बाद पहली बार पाकिस्तान इतना कमजोर नजर आ रहा है तो उसके पीछे भी मुनीर को ही कारण बताया जा रहा है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख के रूप में उन्होंने कई ऐसे कार्य किए हैं जिनके कारण पाकिस्तान को आंतरिक और बाह्य चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जनरल आसिम मुनीर ने अपनी भड़काऊ बयानबाजी, आतंकवाद को बढ़ावा देने, और गलत रणनीतिक फैसलों के जरिए पाकिस्तान को अभूतपूर्व संकट में डाल दिया है। पहलगाम हमले और उनके टू-नेशन थ्योरी को बढ़ावा देने के कारण भारत के साथ तनाव चरम पर पहुंच गया है। जबकि बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पीओके में विद्रोह ने देश को अंदर से खोखला कर दिया है। माइकल रुबिन, एक पूर्व पेंटागन अधिकारी और अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट (एईआई) के वरिष्ठ फेलो, ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर की तीखी आलोचना की है। रुबिन ने मुनीर को आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला और अल-कायदा सरगना ओसामा बिन लादेन के समकक्ष बताया है। मुनीर की अलोकप्रियता, सेना के भीतर असंतोष, और जनता का गुस्सा दर्शाता है कि वह न केवल भारत के लिए, बल्कि पाकिस्तान के लिए भी खलनायक साबित हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि मुनीर का नेतृत्व जारी रहा, तो पाकिस्तान का विखंडन और गृहयुद्ध जैसे हालात हो सकते हैं।

आसिम मुनीर पर आरोप है कि उन्होंने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले को प्रायोजित किया, जिसमें 26 पर्यटकों की हत्या हुई। यह हमला उनके भारत-विरोधी जहरीले बयानों के ठीक बाद हुआ, जिसमें उन्होंने दो-राष्ट्र सिद्धांत को बढ़ावा देते हुए कहा कि हिंदू और मुस्लिम पूरी तरह अलग हैं और कश्मीर पाकिस्तान की रगों का हिस्सा है। समझा जाता है कि उनका ये बयान आतंकवादियों के लिए इशारा था। माइकल रुबिन का कहना है कि मुनीर के बयान ने आतंकवादी समूहों के लिए हरी झंडी का काम किया। रुबिन ने कहा कि मुनीर के इन बयानों ने लश्कर-ए-तैयबा और उसकी प्रॉक्सी द रेसिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) जैसे समूहों को पहलगाम हमले के लिए प्रेरित किया। भारत ने इस हमले के जवाब में पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले किए, जिसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। इससे दोनों देश युद्ध के कगार पर पहुंच गए। फिलहाल सीजफायर लागू है। आगे यदि तनाव बढ़ता है, तो पाकिस्तान को सैन्य और आर्थिक नुकसान हो सकता है, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था पहले से ही कमजोर है। सऊदी अरब और यूएई जैसे सहयोगी देशों ने पहलगाम हमले के लिए मुनीर की आलोचना की, जिससे पाकिस्तान की कूटनीतिक स्थिति कमजोर हुई। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी नागरिकों ने चिंता जताई कि युद्ध के कारण पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था 100 साल पीछे चली जाएगी। क्योंकि देश पहले से ही आईएमएफ, सऊदी अरब और यूएई से लिए गए कर्ज पर निर्भर है।

भारत के हमलों ने पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचाया

भारत और पाकिस्तान के बीच चार दिनों तक चली सैन्य झड़प पिछले 50 सालों में सबसे बड़ी लड़ाई थी। दोनों देशों ने एक-दूसरे की एयर डिफेंस क्षमताओं को परखा और सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इन हमलों के लिए ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल किया। दोनों ने एक-दूसरे को गंभीर नुकसान पहुंचाने का दावा किया। सैटेलाइट तस्वीरों से पता लगा कि हमले काफी ज्यादा थे, लेकिन नुकसान दावे से कहीं कम था। इनमें भी ज्यादातर हमले भारत ने पाकिस्तानी ठिकानों पर किए थे। इस हाईटेक वॉरफेयर के जमाने में दोनों पक्षों ने सटीक निशाना साधा। इस लड़ाई में दोनों पक्षों की सेनाओं को नुकसान भी उठाना पड़ा है। भारत ने 5 सैनिकों के नुकसान की बात स्वीकार की है, जबकि पाकिस्तान ने 11 सैनिकों के नुकसान की बात कही है। हमलों से पहले और बाद की हाई रिजॉल्यूशन तस्वीरों से पता चला है कि भारतीय हमलों से पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। ये हमले सीमित और सटीक थे। पाकिस्तान के बंदरगाह शहर कराची से 150 किमी से भी कम की दूरी पर मौजूद भोलारी एयरबेस को भारत ने निशाना बनाया। भारतीय सैन्य अधिकारियों के मुताबिक उन्होंने एक विमान हैंगर पर सटीक हमला किया। सैटेलाइट तस्वीरों से भारत का यह दावा सही नजर आया। तस्वीरों में हैंगर वाली जगह पर साफतौर पर बड़ा नुकसान दिखाई दे रहा है। पाकिस्तानी आर्मी के हेडक्वार्टर और प्रधानमंत्री कार्यालय से सिर्फ 25 किमी दूर भारत ने नूर खान एयरबेस को निशाना बनाया। परमाणु हथियारों की स्टोरेज फैसिलिटी और सिक्योरिटी यूनिट यहां से कुछ ही दूरी पर है। इस लिहाज से यह सबसे संवेदनशील सैन्य टारगेट था, जिस पर भारत ने हमला किया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रहीम यार खान एयरबेस को भी निशाना बनाया। यह पाकिस्तान का एक अहम एयरपोर्ट भी है। भारत के हमले से एयरबेस की एयरस्ट्रिप पर गहरा गड्ढा बन गया। सैटेलाइट तस्वीरों में नुकसान साफ देखा जा सकता है। 10 मई को पाकिस्तान की सेना ने नोटिफिकेशन जारी किया था। इसमें कहा गया था कि यह रनवे चालू नहीं हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में सरगोधा एयरबेस के दो अलग-अलग हिस्सों को भारत ने निशाना बनाया। इसके लिए सेना ने सटीक हथियारों का इस्तेमाल किया। इससे रनवे पर दो अलग-अलग गड्ढे बन गए।

विवादों वाला मंत्री

अदालत ने लगाई फटकार

मप्र उच्च न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने शाह पर कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला दर्ज किया है। उच्च न्यायालय ने उनकी टिप्पणी पर स्वतः संज्ञान लिया था। इससे पहले अप्रैल 2013 में आदिवासी बहुल झाबुआ जिले में एक सार्वजनिक समारोह को संबोधित करते हुए शाह ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस टिप्पणी से उठे राजनीतिक विवाद के चलते शाह को मंत्री पद से हाथ धोना पड़ा था। उनसे जुड़े नवीनतम विवाद ने उच्च न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया, जिसने मामले का स्वतः संज्ञान लिया। उच्च न्यायालय ने शाह को कर्नल कुरैशी के खिलाफ खतरनाक, अपमानजनक टिप्पणी करने और गटर की भाषा का इस्तेमाल करने के लिए फटकार लगाई और पुलिस को दुश्मनी और घृणा को बढ़ावा देने के लिए उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने कहा कि टिप्पणियां सशस्त्र बलों के लिए अपमानजनक थीं, जो शायद देश की आखिरी संस्था है जो ईमानदारी, अनुशासन, बलिदान, निस्वार्थता, चरित्र, सम्मान और अदम्य साहस को दर्शाती है।

मप्र सरकार में मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान जो कहा वह सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और उसकी जमकर आलोचना भी की जा रही है। मंत्री विजय शाह ने कहा कि जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, उन ..... लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेजकर उनकी ऐसी की तैसी करवाई। दरअसल, जिस समय और जिस मंच से मंत्री यह बयान दे रहे थे, उस मंच पर क्षेत्रीय सांसद और केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर के साथ विधायक उषा ठाकुर भी मौजूद थीं। मंत्री विजय शाह के इस बयान के बाद मप्र की राजनीति में हलचल मच गई है।

इस मामले में कांग्रेस ने मंत्री विजय शाह को बर्खास्त करने की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हाफिज ने विजय शाह पर जमकर हमला बोला है। उमंग सिंघार ने कहा कि विजय शाह का सेना के आला अधिकारी पर दिया गया बयान न केवल शर्मनाक है, बल्कि यह सेना और महिलाओं दोनों का अपमान है। सेना का कोई अधिकारी हो या सैनिक, उसका कोई धर्म नहीं होता, उन्हे हिंदू या मुसलमान के रूप में नहीं गिना जाता। उनका केवल एक ही धर्म होता है-देश। मजहब की बात बार-बार भारतीय जनता पार्टी करती है और इस तरह की भाषा भाजपा की सोच को उजागर करती है। यह बयान अत्यंत निंदनीय है। मैं विजय शाह के इस बयान की घोर निंदा करता हूं। उन्हें इस बयान पर तत्काल माफी मांगनी चाहिए।

कर्नल सोफिया पर अपमानजनक टिप्पणी पर कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हाफिज ने मंत्री विजय शाह ने जो बयान कर्नल सोफिया कुरैशी के संदर्भ में दिया है, वह बेहद आपत्तिजनक है। भाजपा को आगे बढ़कर विजय शाह को मंत्री पद से बर्खास्त करना चाहिए। विजय शाह ने इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री के परिवार के विषय में टिप्पणी की थी, जिस पर पार्टी ने उनका इस्तीफा ले लिया था। आज देखना है कि भाजपा के लिए एक पूर्व मुख्यमंत्री का परिवार ज्यादा महत्वपूर्ण था या सोफिया कुरैशी और उनके जैसे सेना के अधिकारी और फौजी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। हम इंतजार करेंगे कि भाजपा इस तरह के बयान पर क्या फैसला लेती है। हम मंत्री विजय शाह को उनके पद से बर्खास्त करने की मांग करते हैं। विवादित बयान के बाद मामला बढ़ता देख मंत्री विजय शाह ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि मेरी बात को गलत संदर्भ में देखा जा रहा है। विजय शाह ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री ने हमारी बहनों के सिंदूर उजाड़ने वालों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया है। मेरे भाषण को अलग संदर्भ में ना देखें। अलग संदर्भ में देख रहे हैं तो मैं कहना चाहता हूं, मेरी बात उस संदर्भ में नहीं है। हमारी बहनों ने बहुत ताकत से सेना के साथ मिलकर बदला लिया है।

कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई टिप्पणियों के कारण आलोचनाओं का सामना कर रहे मप्र के जनजातीय मामलों के मंत्री विजय शाह पहली बार किसी विवाद में नहीं उलझे हैं। इससे पहले, उन पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लग चुका है। वह मप्र में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन को रात्रिभोज का निमंत्रण देकर भी विवाद में घिर चुके हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर का विवरण नई दिल्ली में नियमित पत्रकार वार्ताओं में विंग कमांडर व्योमिका सिंह के साथ मिलकर साझा करती थीं। इन पत्रकार वार्ताओं में विदेश सचिव विक्रम मिसरी भी शामिल होते थे।

राज्य कांग्रेस महासचिव तथा पार्टी के मीडिया प्रभारी अभय तिवारी ने कहा कि शाह को 2013 में तत्कालीन मुख्यमंत्री की पत्नी के बारे में बेतुकी बातें करने के कारण मप्र मंत्रिपरिषद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा था। उन्होंने पूछा, अब जब उन्होंने सेना पर बेशर्मी भरी टिप्पणी की है, तो भाजपा चुप है। क्या यही उनका राष्ट्रवाद है? कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि जब शाह कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे थे, तो कार्यक्रम के एक वीडियो में पूर्व संस्कृति मंत्री और महू की विधायक ऊषा ठाकुर हंसती हुई दिखाई दे रही थीं। उन्होंने पूछा, क्या यही भाजपा की संस्कृति है। गुप्ता ने दावा किया कि नवंबर 2020 में जब शाह वन मंत्री थे, तब उन्होंने एक और विवाद खड़ा कर दिया था। उन्होंने कहा, उन्होंने बालाघाट जिले में फिल्म शेरनी की शूटिंग के दौरान अभिनेत्री विद्या बालन को कथित तौर पर रात के खाने पर आमंत्रित किया था। फिल्म स्टार ने प्रस्ताव ठुकरा दिया, जिसके बाद शाह के विभाग ने शूटिंग की अनुमति वापस ले ली। मीडिया की खबरों के मुताबिक, शाह के साथ रात्रिभोज से विद्या बालन के इनकार के एक दिन बाद, फिल्म की टीम के वाहनों को शूटिंग के लिए वन क्षेत्र में प्रवेश करने से कथित तौर पर रोक दिया गया था। शाह ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि उन्होंने शूटिंग के लिए अनुमति लेने वालों का भोजन का निमंत्रण ठुकरा दिया था।

● **अरविंद नारद**

सामाजिक खाई को बढ़ावा देने का डर

> जाति एक जटिल सामाजिक व्यवस्था है जिसका स्वरूप समय और स्थान के साथ बदलता रहा है। कर्म पर आधारित चार वर्णों वाली मूल व्यवस्था कब जन्म आधारित जाति की रूढ़ि में ढल गई यह कहना तो मुश्किल है परंतु जाति की व्यवस्था ने निश्चित रूप से भारतीय समाज और उसके सोच-विचार को बुरी तरह से जकड़ लिया कि उससे उबरने की कोशिश कारगर न हो सकी। जाति जनगणना को लेकर कांग्रेस और भाजपा दोनों की स्थिति में एक बहुत बड़ी समानता देखी जा सकती है। सत्ता में रहते हुए दोनों दलों ने सामाजिक और राजनीतिक जोखिमों के डर से इस मुद्दे से दूरी बनाए रखी।

आखिरकार मोदी सरकार ने जातिवार जनगणना कराने का अप्रत्याशित निर्णय ले लिया। इसके पहले 1931 में अंग्रेजों ने ऐसी जनगणना कराई थी। उसके बाद से किसी सरकार ने जातिगत जनगणना की आवश्यकता नहीं समझी। हालांकि इसकी समय-समय पर मांग होती रही। मनमोहन सरकार ने कुछ क्षेत्रीय दलों के दबाव में 2011 में सर्वेक्षण की शक्ल में सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना कराई, लेकिन उलझाऊ आंकड़ों के कारण उन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया। इधर कुछ वर्षों से राहुल गांधी जातिवार जनगणना की मांग पर बहुत जोर दे रहे थे। वे इस मामले में सपा, राजद जैसे दलों को भी पीछे छोड़ रहे थे। यह इसलिए हैरान करने वाला था, क्योंकि कांग्रेस कभी भी जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं रही।

राहुल ने ऐसा माहौल बना दिया था, जैसे जातिगत जनगणना वंचितों-पिछड़ों और विशेष रूप से ओबीसी वर्ग के कल्याण का एकमात्र उपाय है। इससे यह लगने लगा था कि भाजपा को इसकी काट खोजनी पड़ेगी। अंततः वह इसी नतीजे पर पहुंची कि जातिगत जनगणना कराना ही बेहतर है। वह शायद इस नतीजे पर इसलिए पहुंची कि कहीं जातिवार जनगणना की मांग उसके ओबीसी वोटबैंक में सेंध न लगा दे। जो भी हो, यह किसी से छिपा नहीं कि अधिकांश दल जाति और मजहब की धुरी पर ही अपनी राजनीतिक बिसात बिछाते हैं। इसी कारण जातिगत आरक्षण की घोषणा होते ही उसका श्रेय लेने की होड़ मच गई है। इसका कारण खुद को औरों से अधिक ओबीसी का हितैषी बताना और अंततः उसके वोट लेना है।

जिस कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण का सबसे अधिक विरोध किया, वही अब जाति की राजनीति करने वाले क्षेत्रीय दलों से भी आगे बढ़कर ओबीसी तबके को यह समझाने में जुटी कि जातिवार जनगणना में वे सामाजिक और आर्थिक रूप से पीछे पाए जाएंगे और इस नाते शिक्षा संस्थानों और नौकरियों में उन्हें ज्यादा आरक्षण मिलने में आसानी हो जाएगी। एससी-एसटी की तरह ओबीसी आरक्षण जातिगत पिछड़ेपन पर आधारित है। चूंकि आरक्षण के अलावा समाज कल्याण की कई योजनाओं का आधार जातिगत पिछड़ापन है, इसलिए वंचित-पिछड़ी जातियों का सही आंकड़ा होना ही चाहिए। इससे सामाजिक कल्याण की योजनाओं के साथ आरक्षण की नीतियों को सही तरह लागू करने में सहायता मिलेगी। यह किसी से छिपा नहीं कि हर आरक्षित वर्ग में कुछ समर्थ पिछड़ी जातियां आरक्षण का लाभ लेकर और आर्थिक प्रगति के चलते आए बदलावों का

2011 में जाति जनगणना को लेकर बैकफुट पर थी कांग्रेस

2010 में, अपनी दूसरी पारी के लगभग एक साल बाद, मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार उस समय असमंजस में पड़ गई, जब उसके सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल (राजद), समाजवादी पार्टी (सपा) और जनता दल (यूनाइटेड) ने मांग की कि 2011 की जनगणना के साथ जातिगत जनगणना भी की जाए। कांग्रेस के कई ओबीसी नेता इस विचार का समर्थन कर रहे थे, पर कांग्रेस इस मुद्दे पर स्पष्ट रुख नहीं बना पा रही थी। उस दौर में सरकार की सबसे बड़ी विरोधी पार्टी भाजपा भी इस मुद्दे पर अपनी कोई स्पष्ट नीति नहीं रख रही थी। यही कारण था कि कांग्रेस इस मुद्दे पर अपने सहयोगी दलों के दबाव में नहीं आ रही थी। तत्कालीन गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने तर्क दिया कि जनगणना के दौरान जाति से संबंधित सवाल शामिल करने से तकनीकी समस्याओं के चलते गलत परिणाम मिल सकते हैं। हालांकि सरकार चलाते रहने की विवशता के चलते मनमोहन सरकार ने जाति जनगणना तो कराई पर रिपोर्ट कभी लागू नहीं होने दी। 6 और 7 मई, 2010 को संसद में इस मुद्दे पर चर्चा हुई। इसने कांग्रेस के भीतर मतभेदों को उजागर किया, लेकिन अधिकांश नेताओं, जिनमें भाजपा के नेता भी शामिल थे, ने जातिगत जनगणना के पक्ष में बात की। चर्चा के बाद, तत्कालीन सरकार ने इस मामले को तत्कालीन वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह को सौंप दिया।

लाभ उठाकर सक्षम बन चुकी हैं। उन्हें अब आरक्षण की आवश्यकता नहीं, लेकिन ऐसी ही जातियों के नेताओं को देखें तो यह साफ पता चलता है कि पिछड़ों के उत्थान के नाम पर उन्होंने अपनी ही जाति वालों का भला किया। क्या यही सामाजिक न्याय है? पिछड़ों की समर्थ जातियों के आरक्षण का अधिकतम लाभ लेने से कहीं अधिक पिछड़ी जाति वालों का भला नहीं हो पा रहा है। यह विसंगति दूर हो और पात्र लोगों को ही आरक्षण का लाभ मिले तभी जातिगत जनगणना के वास्तविक उद्देश्य हासिल होंगे। यह मान लेना सही नहीं कि पिछड़े वर्ग में सभी सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। एससी-एसटी जातियों की तरह पिछड़ी जातियों का एक तबका भी पिछले चार दशक में अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है और मुख्यधारा में सम्मिलित है। ऐसे तबके के अनेक लोग यह नहीं चाहते कि उन्हें अगड़े-पिछड़े के सामाजिक चश्मे से देखा जाए।

जातिवार जनगणना की घोषणा के बाद आरक्षण की सीमा बढ़ाने की मांग और तेज होना तय है। राहुल गांधी ने ऐसी मांग फिर से कर दी है। आखिर कहां तक बढ़ेगी जातिगत आरक्षण की सीमा? वह 50 प्रतिशत तक पहले ही पहुंच गई है और कुछ राज्यों ने तो उसे 60-70 प्रतिशत कर दिया है। 10 प्रतिशत आरक्षण आर्थिक आधार पर भी है। आरक्षण की व्यवस्था ऐसी हो कि वह मेधा की अनदेखी न करने पाए। अगर देश को उन्नति करनी है तो हमें मेधा को सर्वोपरि रखना होगा। हर वर्ग के मेधावियों को आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। यदि आरक्षण के चलते मेधा की अनदेखी होगी तो देश का भविष्य उज्ज्वल नहीं हो सकता। आरक्षण की बढ़ती मांग का एक बड़ा कारण सरकारी नौकरियां हैं, लेकिन वे तो लगातार कम होती जा रही हैं। यह एक विडंबना है कि जो निजी क्षेत्र नौकरियां उपलब्ध करा रहा है, उसके प्रति सामाजिक न्याय की बातें करने वाले दलों और यहां तक कि कांग्रेस के नेताओं का रवैया अत्यधिक नकारात्मक है। आखिर ऐसे में कैसे बात बनेगी? आरक्षण कितना भी बढ़ जाए, उसका लाभ सबको देना संभव नहीं, क्योंकि सरकारी नौकरियों की एक सीमा है। आरक्षण की व्यवस्था ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो सबसे अधिक पिछड़े हैं, वे उसका लाभ पाने में भी सबसे पीछे रहें। जातिगत आरक्षण की मांग का एक अन्य कारण देश में अच्छे शिक्षा संस्थानों की कमी है। आबादी को देखते हुए तो यह कमी बहुत अधिक है और यह किसी से छिपा नहीं कि सबको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके, इसके लिए नेतागण कभी गंभीरता नहीं दिखाते।

जाति भारत की एक कड़वी हकीकत है। यह अच्छा है कि हिंदुओं के साथ मुसलमानों और अन्य समुदायों में भी जाति गणना होगी। होनी भी चाहिए, क्योंकि जाति तो हर जगह है। उन समुदायों में भी, जो खुद को जातिविहीन बताते हैं। मुस्लिम समुदाय अनेक जातियों में बंटा है। इस समुदाय की सैयद, शेख, पठान जैसी समर्थ संपन्न जातियां उसी तरह अल्पसंख्यक कल्याण की योजनाओं का अधिकतम लाभ ले जाती हैं, जैसे पिछड़े वर्ग की कुछ समर्थ जातियां जातिगत आरक्षण का। मुस्लिम की तरह जातीय भेद से ईसाई, सिख और बौद्ध समाज भी अछूता नहीं। जनगणना के साथ जातिवार गणना में कोई बुराई नहीं, लेकिन खतरा यह है कि सामाजिक न्याय की बात करने वाले नेता जातिगत जनगणना के जरिये सामाजिक खाई को बढ़ावा देंगे। यह खतरा वास्तविक है, क्योंकि कई दल जाति विशेष की बात ही नहीं करते, उन्होंने खुद को कुछ विशेष जातियों के हितैषी दल के रूप में ही उभारा है। वे साफ तौर पर कुछ जातियों को दूसरी जातियों के खिलाफ खड़ा करते हैं। यह सामाजिक न्याय नहीं, अन्याय है। यह राजनीति जातीय विभाजन और जातीय वैमनस्य को बढ़ाती है। ऐसी राजनीति सामाजिक एकजुटता को कमजोर कर सकती है। ऐसा न होने पाए, इसके लिए कुछ जतन करने ही होंगे।

2021 में भाजपा की स्थिति

2011 में जैसी कांग्रेस की स्थिति थी, वैसी ही ठीक 10 साल बाद केंद्र में सरकार भाजपा की थी और कांग्रेस विपक्ष में थी। भाजपा के सामने भी वही परेशानी थी। पार्टी ने 2021 में जातिगत जनगणना को लेकर अपरोक्ष रूप से मना कर दिया था। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में कहा कि सरकार केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की गणना करेगी, अन्य जातियों की गणना करने तकनीकी समस्याएं जैसी बातें कहकर बचने का प्रयास किया। मतलब साफ है कि दोनों ही दल जब सत्ता में होते तो जातिगत जनगणना कराने से बचते रहे। जबकि विपक्ष में आने पर जाति जनगणना का सपोर्ट करते। भाजपा जब विपक्ष में थी (2011 से पहले), तब उसने जातिगत जनगणना का समर्थन किया था। 2010 में भाजपा सांसद गोपीनाथ मुंडे ने इसकी मांग उठाई थी। लेकिन सत्ता में आने के बाद, 2021 में सरकार ने इसे प्रशासनिक रूप से जटिल और अव्यवहारिक बताया।

राजनीतिज्ञ इसका लाभ उठाते हैं। लोकतंत्र में संख्या बल का महत्व है। इसलिए आज जातिगत समीकरण का खेल हर कहीं दिख रहा है। जिस क्षेत्र में जो जाति या उपजाति अधिक संख्या में होती है वहां से उसी जाति का प्रत्याशी खड़ा किया जाता है चाहे वह योग्य हो या न हो। यह प्रकट तथ्य है कि जाति और उपजाति को इस तरह प्रमुखता देना जाति की भावना को तीव्र करने वाला है। जाति को योग्यता मानकर हो रही राजनीति सिर्फ पूर्वाग्रह, भेदभाव और शोषण को बढ़ावा देने वाली साबित हो रही है। यह भी एक सत्य है कि जाति का बंधन भारतीय समाज के एक बड़े तबके के लिए विकास के मार्ग में रोड़ा बना रहा है। स्वतंत्र भारत में जाति के आधार पर होने वाले अमानवीय भेदभाव को समाप्त करने के लिए तमाम कदम उठाए गए हैं। साथ ही पीढ़ियों से शोषित समुदायों को राहत देने और दूसरों की तरह ही विकसित होने का समान अवसर देने के लिए संविधान में विशेष सुविधाओं का प्रविधान किया गया है। इनके लिए शिक्षा और नौकरी में आरक्षण देने की व्यवस्था हुई है। इन सुविधाओं की पात्रता को लेकर समय-समय पर विचार और संशोधन भी होता रहा है। इस क्रम में जातियों को अनुसूचित और अन्य पिछड़ी जाति (ओबीसी), दलित, महादलित आदि की श्रेणियां बनाई गईं और इनके लिए आवश्यक सुविधाओं का निर्धारण किया गया है। अब लगभग एक सदी बाद भारत में जातियों का आंकलन कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण होगा।

● **विपिन कंधारी**

क्या मुफ्त की रेवड़ियां विपक्ष को आगे बढ़ने में मदद कर सकती हैं? वे ऐसा जो भी वादा करेंगे, मोदी उससे बेहतर पेशकश कर देंगे। चूंकि मोदी सत्ता में हैं, उनके वादे को ज्यादा विश्वसनीय माना जाएगा।

अबकी बार 75 पार...!

अपने तीसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ की ओर बढ़ रहे नरेंद्र मोदी आत्मविश्वास से लबालब और बेहद आश्वस्त दिख रहे हैं। पिछले चुनाव में 240 सीटें पाने के बाद उनमें जो संशय और तनाव आपको दिख रहा होगा, वह दूर हो चुका है। हरियाणा और महाराष्ट्र में विजय के अलावा इंडिया गठबंधन में बिखराव ने बेशक इस आत्मविश्वास में इजाफा किया। लेकिन आत्मतुष्टि के कगार पर पहुंचे इस आत्मविश्वास के पीछे गहरा और अधिक ठोस कारण है। यह कारण है- उन्हें चुनौती देने वालों में नए विचारों का अभाव। आज कोई भी नहीं है (न कोई नेता, न कोई पार्टी और न कोई विचार) जो राष्ट्रीय राजनीति में खलबली पैदा कर रहा हो। फिलहाल खिन्नता की राजनीति चल रही है। नाव को कोई हिला नहीं पा रहा है। यह नाव है मोदी की भाजपा। और यह नाव जिस भी हाल में है, मोदी उससे खुश हैं।

उनके प्रतिद्वंद्वी पुराने विचारों से चिपके हैं, या तो वे मोदी से मात खा चुके हैं या मोदी ने उन्हें बेअसर कर दिया है या बदल दिया है। और अगर आप भी व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड किए गए उन संदेशों पर गौर कर रहे हैं जो यह बता रहे हैं कि इस सितंबर में 75 साल के हो जाने पर मोदी रिटायर हो जाएंगे, तो मेहरबानी करके खुद को धोखे में न रखिए। मोदी कहीं नहीं जाने वाले, वे 2029 में भी भाजपा का नेतृत्व करेंगे। यह समझने के लिए किसी ज्योतिषशास्त्र या राजनीतिक दूरदर्शिता की जरूरत नहीं है। तथ्यों पर गौर कीजिए। 2029 में उनकी उम्र उतनी ही होगी जितनी आज डोनाल्ड ट्रंप की है। अगर उनके प्रतिद्वंद्वी इस मुगालते में रहना चाहते हैं कि उनका समय खत्म होने वाला है और राहुल की उम्र उनकी मदद करेगी, तो वे मोदी युग को नहीं समझ पाए हैं।

ऐसा लगता है कि मतदाताओं के लिए विरोधियों के पास कोई बेहतर पेशकश नहीं है, कम-से-कम एक दिलचस्प और उत्साहित करने वाली पेशकश। अपनी शैली, अपनी विचारधारा या राजनीतिक पेशकश के बूते कोई भी वैसी बड़ी खलबली नहीं पैदा कर रहा है जो इस सुविधाजनक गतिरोध में हलचल पैदा करने के लिए जरूरी है। उधर मोदी उस क्रिकेट टीम की तरह आगे बढ़ते जा रहे हैं जो टेस्ट मैच में 300 (यह आंकड़ा जानबूझकर चुना गया है) के लक्ष्य का पीछा कर रही है और दो विकेट गंवाकर 190 रन पर खेल रही है। सवाल यह है कि वह बड़ी खलबली पैदा करने वाला आइडिया क्या हो सकता है? यह वह सब नहीं हो सकता जो विपक्ष आज पेश कर रहा है- सांप्रदायिकता बनाम धर्मनिरपेक्षता का मुद्दा पुराना पड़ चुका है। इस हथियार की धार भोथरी पड़ चुकी है। अमीर बनाम गरीब की बहस में वे जीत नहीं सकते।

उनके मुकाबले मोदी हमेशा ज्यादा आम आदमी जैसे दिखेंगे, और मोदी की राजनीति उनकी राजनीति के मुकाबले ज्यादा गरीबोन्मुख दिखेगी। यही वजह है कि अडाणी-अंबानी का ठप्पा उन पर चस्पां नहीं हो पाता। इसलिए नहीं कि उन पर टेफ्लन का मुलम्मा चढ़ा है या वे टाइटेनियम नामक धातु से बने हैं, बल्कि इसलिए कि इस आइडिया में दम नहीं है। इसलिए कि यह आइडिया देने वालों में आत्मविश्वास की कमी है। मोदी ने उनसे मनरेगा की जो गरीबवादी सीढ़ी उत्तराधिकार में हासिल की थी उसके कई पायदान वे ऊपर चढ़ चुके हैं। आज 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है, उनके लिए आवास बनाए जा रहे हैं, शौचालय बनाने के लिए अनुदान दिए जा रहे हैं, किसानों को मुद्रा लोन आदि के जरिए मदद दी जा रही है। गरीबों को आज जितना कुछ मिल रहा है

मिडिल क्लास मोदी का आदी

भारत के आर्थिक इंजन की रफ्तार धीमी पड़ रही है और लड़खड़ा रही है, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान विशाल मध्यवर्ग को उठाना पड़ रहा है। यह केवल एक बुरी तिमाही का नतीजा नहीं है। आंकड़ों का विश्लेषण करने वाले केंद्र सरकार के संगठन भारतीय रिजर्व बैंक समेत दुनियाभर के ऐसे संगठन भी भारत की इस साल की आर्थिक वृद्धि में कमी का अनुमान लगाते हुए इसे 6.5 फीसदी के आसपास रहने का अंदाजा लगा रहे हैं। फिलहाल इस स्थिति के पलटने के कम ही संकेत मिल रहे हैं। सबसे पहला लक्षण तो यह है कि भारत का समय आ गया है जैसी सर्वविजयी बुलंद उम्मीद अब ढीली पड़ रही है। जिसे हम हवा कहते हैं वह बदल गई है। करोड़पति लोग विदेश में जमीन-जायदाद खरीद रहे हैं या इसके साथ मिलने वाली दीर्घकालिक वीसा हासिल कर रहे हैं। भारत के करोड़पति कितनी संख्या में विदेश में जाकर बस रहे हैं इसके पर्याप्त आंकड़े सबके लिए उपलब्ध हैं। हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट के अनुसार, पिछले दो साल से ऐसे लोगों की संख्या औसतन 5,000 रही है। इन अमीरों को आप कभी शिकायत करते नहीं सुनेंगे। ये इतने स्मार्ट हैं कि इस तरह के पंगे नहीं लेते। ये अपने पैरों की दिशा से अपना मत जाहिर करते हैं। तथ्य यह है कि इनके पास सरप्लस है, और ये भारत में निवेश करने की जगह विदेश का रुख कर रहे हैं।

उतना पिछली किसी भी सरकार ने नहीं दिया था। और यह सब सत्तातंत्र या भ्रष्ट स्थानीय अधिकारियों से हासिल करने में आने वाली दिक्कतों के बिना मिल रहा है। क्या इस तरह की मुफ्त रेवड़ियां विपक्ष को आगे बढ़ने में मदद कर सकती हैं? वे ऐसा जो भी वादा करेंगे, मोदी उससे बेहतर पेशकश कर देंगे। मोदी को चुनौती देने वालों को अब तक तो समझ जाना चाहिए था कि राजनीति को लेन-देनवाद में बदलने के क्या नतीजे हो सकते हैं। लेन-देन पर भरोसा करने वाला मतदाता वफादार नहीं होता। वह हमेशा उसका पक्ष लेगा, जो ज्यादा बड़ी बोली लगाएगा।

तो विपक्ष के नेता क्या करें? वे मोदी से धर्म के मुद्दे पर नहीं लड़ सकते, चाहे वे कितने भी मंदिरों में मत्था टेकें या अपनी कलाई पर कितने भी धागे बांधें या कितने भी रंग की चादर ओढ़ें। और, राष्ट्रवाद? इसका तो भूल कर भी नाम न लें। इस प्लेटफॉर्म को पिछले 11 वर्षों से तैयार किया गया है। अब आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अंतिम ट्रेन रवाना हो चुकी है। मोदी के प्रतिद्वंद्वियों के लिए फिलहाल जाति एक पसंदीदा मुद्दा बना हुआ है। जाति आधारित दलों के बावजूद, वन-स्टेट में जातीय जनगणना का पत्ता खेलकर कांग्रेस कुछ भी हासिल नहीं कर सकती। जिस पार्टी को एक ऐसी विशाल छतरी के रूप में तैयार किया गया था, जिसके नीचे सभी को सत्ता में हिस्सेदारी मिलेगी और वे फले-फूलेंगे, वह पार्टी जाति की बात करती हुई हास्यास्पद लगती है। यहां उर्दू लेखक सआदत हसन मंटो का वह यादगार वाक्य याद आता है, जो उन्होंने पाकिस्तान में बसने के लिए रवाना होते हुए कहा था, कि पंजाबी लोग (पाकिस्तान में जो भारी बहुमत में हैं) उर्दू बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि वे झूठ बोल रहे हैं।

कांग्रेस जातीय जनगणना वाली पार्टी का चोला धारण करती हुई, और इसके जरिए सामाजिक न्याय दिलाने का वादा करती हुई ऐसी लगती है मानो वह झूठ बोल रही है। जब कि उसे मुख्यधारा की राजनीति के बूते अपना विस्तार करना चाहिए था, वह उसके चारों ओर खाई खोदती दिख रही है। इसके बाद कांग्रेस क्या करेगी? क्या इस खाई में कूदना चाहेगी? जातीय जनगणना के खतरे कर्नाटक में उसकी अपनी सरकार में उभर चुके हैं। अगर किसी ने राहुल गांधी को यह समझा दिया है कि जातीय जनगणना ही वह रामबाण है जो मोदी की गद्दी हिला सकती है, तो हम यही कहेंगे कि उन्हें बेहतर सलाहकारों की जरूरत है। राजनीतिक की कोई भी समझ न रखने वाली मैकिन्से भी इस तरह का चुटकुला नहीं उछाल सकती। यह हमें वापस उसी सवाल पर पहुंचाता है जो हमने शुरू में उठाया था, कि क्या ऐसा कोई आइडिया, कोई नेता या कोई राजनीतिक आंदोलन है जो इस खेल को पलट सके? जो बुमराह के उन छह ओवरों की बौछार की तरह हो, जो दो विकेट पर 190 रन बना चुकी प्रतिद्वंद्वी टीम का खेल उलट दे?

1969 के बाद से, भारतीय राजनीति में केवल तीन बड़े आइडिया उभरे- गरीबी हटाओ (इंदिरा गांधी का ठोस समाजवादी नारा); मंडल (सामाजिक न्याय का नारा); और मंदिर (हिंदुत्ववादी नारा)। अलग-अलग समय पर ये तीनों सफल रहे। अब चुनौती यह है कि इनमें से दो में सभी बड़ी पार्टियों की हिस्सेदारी है। हिंदुत्व पर अभी भी भाजपा का एकाधिकार है। और दूसरे दल (कांग्रेस के नेतृत्व में) जब समाजवाद और सामाजिक न्याय की बात करते हैं तब कोई उत्साहित नहीं होता। वे करीब 15 फीसदी मतदाता तो नहीं ही होते, जो पाला बदल सकते हैं। आंकड़ों से हमें पता है कि 20 फीसदी मतदाता कांग्रेस के साथ हैं और करीब 25 फीसदी भाजपा के साथ हैं। बाकी 10-12 फीसदी मोदी के लिए बोनस जैसे हैं। ये मतदाता कांग्रेस से थककर दूसरे पाले में गए हैं। आप वही पुराने मंत्र जपते रहे तो वे आपकी ओर नहीं लौटेंगे। उबाऊ होना, और नीरस होना राजनीति में अपराध जैसा है।

पिछले पांच साल में हमने देखा है कि वास्तव में गैर-पारंपरिक किरदारों ने राजनीति को नया रूप देने के लिए स्थापित राजनीतिक प्रवृत्तियों को किस तरह उलटपुलट दिया है। डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति का ठेठ रिपब्लिकनों की राजनीति से कोई साम्य नहीं है। मागा (मेक अमेरिका ग्रेट अगेन) वाली यह एक अलग ही पार्टी है जिसके अपने विचार हैं, अपनी शैली तथा अपनी भाषा है, और इसे किसी स्थापित परंपरा का अपमानजनक अनादर करने से कोई परहेज नहीं है। इन सबको पसंद करने वाले मतदाता पर्याप्त संख्या में हैं। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट के बीच अदलाबदली के सामान्य चक्र के बाद अब यह एक अलग प्रोडक्ट है।

जॉर्जिया मेलोनी ने इटली में यह कर दिखाया है। अर्जेंटीना में बिलकुल बाहरी, युवा जेवियर मिले ने मानो आरी से सरकार के आकार को आधा काटकर स्थापित राजनीति को सिर के बल खड़ा कर दिया है। उनका प्रोडक्ट मूलतः इतना नया था कि घिसे-पिटे पुराने प्रोडक्ट से ऊब चुके मतदाताओं ने उन्हें एक मौका दे दिया। अपने यहां भारत में, आप ने अपने उत्कर्ष के दौर में दिल्ली को इसी तरह जीता था। और इसके उलट, बाद में पंजाब में भी धर्म जिस तरह राज्य की राजनीति के मुकाबले भारी पड़ा, उसने हथियार डाल दिया।

● इन्द्र कुमार

रुके हुए सुधार और टैक्स का भार कोई मायने नहीं रखते

आखिरकार, ज्यादातर मांग देश की सबसे बड़ी उपभोक्ता आबादी यानी मध्यवर्ग से आती है। इस वर्ग की परिभाषा भी जटिल है, लेकिन हम यह मानकर चलें कि मध्यवर्ग का व्यक्ति वह है जिसके पास अपनी जीविका के तहत अपने खानपान, बच्चों की शिक्षा, मकान, स्वास्थ्य और जरूरी आवाजाही पर खर्च करने के बाद कुछ पैसा बचता है जिसे वह किसी चीज पर खर्च कर सके। सालाना 12 लाख से लेकर 5 करोड़ तक कमाने वाला यह विशाल वर्ग आज हाथ बांधकर बैठा है और परेशान है। वह इतना अमीर नहीं है कि वैध रूप से विदेश जा बसे, वह भी अपनी संपत्ति के साथ, जिस पर भारी टैक्स देना पड़ता है और जिसके निवेशों का मूल्य भी पिछले एक वर्ष में गिर गया है। मजे की बात यह है कि इनमें से जो ज्यादा अमीर हैं यानी 2 करोड़ से ज्यादा कमा रहे हैं, वे अपनी आय पर प्रतिशत के लिहाज से टॉप कॉरपोरेट्स या अरबपतियों के मुकाबले करीब दोगुना टैक्स भर रहे हैं। भारत की गाथा बनाने वाले ये लोग वे हैं जो महत्वाकांक्षी नव-धनाढ्य हैं और जिन्होंने अपने बूते अपनी तकदीर चमकाई है, जो आमतौर पर पहली पीढ़ी वाले हैं। आज वे मानो एक साथ कई गोले दागने वाले रॉकेट लॉन्चर के हमले झेल रहे हैं।

ईंधन बदला, दिशा बदली

छत्तीसगढ़ के रायपुर में अडाणी एंटरप्राइजेज ने देश का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाला ट्रक लॉन्च कर दिया है। इस ट्रक को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हरी झंडी दिखाई। ये ट्रक राज्य की खदानों से कोयला ढोने के लिए इस्तेमाल होगा और इसका मकसद डीजल ट्रकों की जगह एक साफ-सुथरा और पर्यावरण के अनुकूल विकल्प देना है। स्मार्ट टेक्नोलॉजी और तीन हाइड्रोजन टैंकों से सुसज्जित प्रत्येक ट्रक 200 किलोमीटर की दूरी तक 40 टन तक माल ले जा सकता है। दुनिया में पहली बार, अडाणी एंटरप्राइजेज हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाले इलेक्ट्रिक टिप ट्रेलर को खनन और लॉजिस्टिक्स के लिए तैनात करने जा रहा है। बिना धुआं और बिना शोर के दौड़ने वाला ट्रक अब सड़कों पर दिखेगा। यह कदम पर्यावरण, ईंधन की बचत और लॉजिस्टिक सेक्टर में बड़ा बदलाव ला सकता है। यह ऐसे समय में हुआ है जब छत्तीसगढ़ में 100 से अधिक नए नीलाम किए गए कोयला कमर्शियल ब्लॉक निकट भविष्य में उत्पादन शुरू करने वाले हैं। इसके अतिरिक्त, ट्रक अन्य धातुओं और खनिजों के खनन में उपयोगी होगा। एक बार जब हाइड्रोजन प्रमुख मार्गों पर व्यापक रूप से उपलब्ध हो जाएगा, तो यह नई पीढ़ी का वाहन लंबी यात्रा करने में सक्षम होगा, जिससे कार्बन उत्सर्जन में काफी कमी आएगी और बढ़ते पैमाने पर हाइड्रोजन-संचालित ट्रकों के साथ परिवहन लागत कम हो जाएगी। वित्त वर्ष 2024 में, अकेले छत्तीसगढ़ ने भारत के लगभग एक बिलियन टन कोयला उत्पादन में 20 प्रतिशत यानी 205 मिलियन टन का योगदान दिया।

भारत जैसे ऊर्जा-गहन और तेजी से बढ़ते देश के लिए हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाले ट्रकों का उपयोग समय की आवश्यकता बन गया है। विशेष रूप से खनन और लॉजिस्टिक्स जैसे भारी क्षेत्रों में, जहां डीजल पर अत्यधिक निर्भरता है, ऐसे ट्रकों का उपयोग न केवल पर्यावरणीय दृष्टि से लाभकारी है, बल्कि भारत के दीर्घकालिक ऊर्जा लक्ष्यों के लिए भी बेहद जरूरी है। पारंपरिक डीजल ट्रक भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कण प्रदूषक (पीएम) उत्सर्जित करते हैं। यह न केवल वायु प्रदूषण को बढ़ाता है, बल्कि शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण का भी प्रमुख कारण बनता है। भारत के कई शहर पहले से ही विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों में गिने जाते हैं। ऐसे में हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रक, जो चलते समय केवल जल वाष्प छोड़ते हैं, एक स्वच्छ और टिकाऊ विकल्प बनकर सामने आते हैं। इन ट्रकों का उपयोग जलवायु परिवर्तन को धीमा करने में भी सहायक होगा। अगर भारत को 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करना है, तो हाइड्रोजन जैसे वैकल्पिक और शून्य-उत्सर्जन ईंधन अपनाना अनिवार्य होगा। एक अनुमान के अनुसार, एक भारी डीजल ट्रक सालाना 100 से 150 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है, जबकि हाइड्रोजन ट्रक यह उत्सर्जन पूरी तरह खत्म कर सकता है। इसके अतिरिक्त, भारत का ऊर्जा आयात 260 अरब डॉलर से अधिक है, जिसमें डीजल और अन्य जीवाश्म ईंधनों का बड़ा हिस्सा है। हाइड्रोजन आधारित ट्रकों के उपयोग से यह आयात निर्भरता कम की जा सकती है और घरेलू स्तर पर ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाया जा सकता है। साथ ही, हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी भारत को एक वैश्विक इनोवेशन सेंटर के रूप में स्थापित कर सकती है। अडाणी जैसी कंपनियों की पहल से यह संभव होगा कि भारत केवल उपभोक्ता न बनकर निर्माता और निर्यातक भी बने। इसलिए, हाइड्रोजन ट्रकों का उपयोग न केवल पर्यावरण के लिए जरूरी है, बल्कि भारत के ऊर्जा आत्मनिर्भरता और सतत् विकास के सपने को साकार करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है।

अडाणी एंटरप्राइजेज ने 2022 में अशोक लेलैंड और कनाडा की बैलार्ड पावर सिस्टम्स के साथ साझेदारी की थी। इसमें ट्रक का निर्माण अशोक लेलैंड करेगा और बैलार्ड का फ्यूल सेल इसमें जोड़ा जाएगा। अडाणी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड इस ट्रक के लिए हाइड्रोजन फ्यूलिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रहा है। यह ट्रक छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में स्थित जीपी कोल ब्लॉक में कोयले के परिवहन में इस्तेमाल होगा। यह ट्रक लगभग 55 टन वजनी होगा और इसमें तीन हाइड्रोजन टैंक लगे होंगे। एक बार फ्यूल भरने पर इसकी रेंज लगभग 200 किलोमीटर होगी। यह ट्रक टिपिंग फंक्शन से लैस होगा यानी खुद से लोड और अनलोड कर सकेगा। भारत हर साल कोयला, कच्चा तेल, एलएनजी और एलपीजी जैसी ऊर्जा सामग्रियों के आयात पर लगभग 260 अरब डॉलर खर्च करता है। ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ रही है, जबकि हमारी प्रति व्यक्ति बिजली खपत वैश्विक औसत का सिर्फ एक तिहाई है। ऐसे में भारत को ऊर्जा स्वतंत्रता के लक्ष्य को पूरा करने के लिए वैकल्पिक और हरित ऊर्जा स्त्रोत अपनाने होंगे। विकसित देशों जैसे अमेरिका, जर्मनी, जापान और दक्षिण कोरिया में हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रकों का प्रयोग सीमित स्तर पर हो रहा है, खासतौर पर लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी सेवाओं में। इन देशों में कंपनियां जैसे टाटा, टोयोटा, हुंडई और निकोला हाइड्रोजन पर आधारित तकनीक विकसित कर रही हैं। अमेरिका में निकोला और हुंडई ने कुछ हाइड्रोजन ट्रक तैनात किए हैं, जबकि यूरोप में डेमलर और वोल्वो ग्रुप ने ट्रायल प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं। हालांकि, इन ट्रकों का इस्तेमाल अधिकतर शहरी या इंटरसिटी परिवहन में हो रहा है, और वे मुख्यत: सड़क परिवहन तक सीमित हैं। इसके मुकाबले, अडाणी एंटरप्राइजेज दुनिया की पहली ऐसी कंपनी बनने जा रही है जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाले टिप ट्रेलर को खनन (माइनिंग) में उतारेगी। अडाणी द्वारा विकसित यह ट्रक पूरी तरह से भारत में तैयार होगा और इसमें अशोक लेलैंड, बैलार्ड पावर और अडाणी न्यू इंडस्ट्रीज की साझेदारी होगी। यह न केवल मेक इन इंडिया को बढ़ावा देगा, बल्कि भारत को हाइड्रोजन लॉजिस्टिक्स तकनीक में अग्रणी बना सकता है।

● रायपुर से टीपी सिंह

पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के लिए लाभ

हाइड्रोजन ट्रक जीरो इमिशन वाहन होते हैं, यानी इनसे केवल जल वाष्प निकलता है। ये न केवल वायु प्रदूषण घटाते हैं, बल्कि शोर भी कम करते हैं, जिससे शहरी और पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रों में इनका इस्तेमाल अनुकूल होता है। हाइड्रोजन रिन्युएबल सोर्स से तैयार हो सकता है, जिससे यह टिकाऊ विकल्प बनता है। भारत हर साल लगभग 900 मिलियन टन कोयला उत्पादित करता है। इसे खपत केंद्रों तक पहुंचाने में भारी मशीनरी और ट्रकों की जरूरत होती है। हाइड्रोजन से संचालित ट्रक और उपकरण इस प्रक्रिया को हरित व जिम्मेदार बना सकते हैं। इससे खनन क्षेत्र की कार्बन फुटप्रिंट में भारी कमी लाई जा सकती है। इस ट्रक में इलेक्ट्रोलिसिस तकनीक से तैयार हाइड्रोजन उपयोग होता है। फ्यूल सेल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया से बिजली बनती है जो मोटर को चलाती है। इसका एकमात्र बाई प्रोडक्ट होता है पानी।

निकाय चुनाव का रास्ता साफ

यदि राज्य चुनाव आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए महाराष्ट्र के सभी स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ कराने का निर्णय किया तो ये चुनाव मिनी विधानसभा चुनाव जैसा दृश्य उत्पन्न करेंगे। महाराष्ट्र में स्थानीय निकायों के चुनाव संपन्न कराने को लेकर आया सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय महाराष्ट्र के राजनीतिक दलों की नई पीढ़ी के लिए ताजी बयार बनकर आया है। करीब एक दशक बाद होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव सभी दलों को नई पीढ़ी के नेताओं की एक बड़ी फौज उपलब्ध कराएगी। महाराष्ट्र में स्थानीय निकायों के चुनाव अंतिम बार 2017 में हुए थे। बड़ी संख्या में ऐसे भी नगर निगम हैं, जहां 2015 में अंतिम बार चुनाव हुए थे। उसके बाद से स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण को लेकर उठे विवाद के कारण मामला सर्वोच्च न्यायालय में गया और चुनाव नहीं करवाए जा सके। इसलिए राजनीतिक दलों में चुनाव लड़कर किसी छोटे से छोटे सदन में भी पहुंचने वाले नेताओं की एक पूरी पीढ़ी बिना चुनाव लड़े ही निकल गई है। इसका असर स्थानीय विकास कार्यों पर भी पड़ता रहा है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में कोई चुना हुआ जनप्रतिनिधि है ही नहीं। ए-श्रेणी की मुंबई महानगरपालिका सहित सभी स्थानीय निकायों में प्रशासन आईएएस अधिकारियों के भरोसे चल रहा है, जिन तक आम आदमी की पहुंच ही नहीं होती।

महाराष्ट्र में महानगरपालिकाओं की संख्या 28, नगरपालिकाओं की 185 से 190 के बीच, जिला परिषद 34 एवं 385 पंचायत समितियां हैं। यदि राज्य चुनाव आयोग सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर इन सभी निकायों में चुनाव कराने का निर्णय करता है, तो लंबी अवधि के बाद होने वाले ये चुनाव मिनी विधानसभा चुनाव का दृश्य उत्पन्न करेंगे। संभवत: ये चुनाव राज्य चुनाव आयोग को दो या दो से अधिक चरणों में कराने पड़ें। क्योंकि अब राज्य में सक्रिय प्रमुख राजनीतिक दलों की संख्या ही 10 के करीब पहुंच चुकी है, और स्थानीय निकायों में तो निर्दलीय प्रत्याशियों की संख्या भी अधिक होती है। पिछले वर्ष हुए लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों को देखते हुए कई राजनीतिक दलों में तो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता तनाव की हद पहुंच सकती है। चुनाव आयोग को इसका भी ख्याल रखना पड़ेगा। सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आते ही महाराष्ट्र के राजनीतिक दलों में सक्रियता बढ़ गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट कर दिया है कि सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन मिलकर ही चुनाव मैदान में उतरेगा। फडणवीस ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर खुशी जताते हुए कहा कि मैं चार महीने के अंदर स्थानीय निकाय चुनाव संपन्न कराने के फैसले से प्रसन्न हूं। मैंने राज्य चुनाव आयोग को इसकी तैयारियां करने को कह दिया है। कांग्रेस की मुंबई अध्यक्ष एवं सांसद वर्षा गायकवाड़ ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को राज्य में लोकतांत्रिक पुनरुत्थान की शुरुआत बताते हुए कहा कि लोकतंत्र में जनता की आवाज सबसे महत्वपूर्ण होती है। स्थानीय निकायों के चुनावों के जरिए उस आवाज को मजबूती मिलती है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से महाराष्ट्र में नगर निगमों और परिषदों को चुने हुए प्रतिनिधियों के बजाय नियुक्त प्रशासकों द्वारा चलाया जा रहा है। इससे शासन में जनता की सीधी भागीदारी कम हो गई है एवं नागरिकों और प्रशासन के बीच संवाद टूट गया है। दैनिक जीवन में इसका खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है। हालांकि राजनीतिक दल सितंबर में चुनाव कराने के आदेश से संतुष्ट नहीं हैं। क्योंकि जून से सितंबर तक मुंबई सहित महाराष्ट्र के ज्यादातर हिस्सों में बरसात अधिक होती है। लेकिन उन्हें यह उम्मीद है कि चुनाव आयोग इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय से चुनाव कराने की अवधि बढ़वा सकता है।

पश्चिमी महाराष्ट्र में, महायुति पार्टियां कोल्हापुर, सांगली और सोलापुर नगर क्षेत्रों में मजबूत स्थिति में हैं। कोल्हापुर को छोड़कर भाजपा सांगली मिराज कुपवाड़ और सोलापुर के नगर निकायों में सत्ता में थी। सांगली जिले में भाजपा विभाजित है, वहीं अजित पवार ने कई नेताओं को, खासकर एनसीपी (एसपी) से, अपनी तरफ करके सांगली शहर और ग्रामीण क्षेत्रों दोनों में पैठ बना ली है। सोलापुर में, जब 2017 में आखिरी नगर निकाय चुनाव हुए थे, तो भाजपा ने अविभाजित शिवसेना के साथ गठबंधन में जीत हासिल की थी। अब महायुति में भाजपा सोलापुर में प्रमुख पार्टी बनी हुई है। स्थानीय नेता चाहते हैं कि पार्टी जिले में और अधिक जमीन हासिल करने के लिए अकेले चुनाव लड़े। उत्तरी महाराष्ट्र के स्थानीय नेताओं का कहना है कि वे पार्टियों के वरिष्ठों के फैसले का पालन करेंगे, हालांकि वे अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं।

नासिक में भाजपा इकाई ने 122 में से 100 सीटें जीतने का विश्वास जताया। भाजपा शहर इकाई के अध्यक्ष प्रशांत जाधव ने कहा कि हम अपने दम पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन गठबंधन संभव है। हम निर्देशों का इंतजार करेंगे। एमवीए के सहयोगियों के पास अब फिर से एकजुट होने और पिछले साल नवंबर में विधानसभा चुनाव में खोई हुई जमीन को वापस पाने का मौका है। हालांकि, अपने सदस्यों को बनाए रखने की बड़ी चुनौती का सामना कर रही एमवीए पार्टियां गठबंधन को प्राथमिकता दे सकती हैं। यह चुनाव एमवीए और महायुति दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। एमवीए को अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने की चुनौती है, तो महायुति को अपनी पकड़ बनाए रखने की। स्थानीय नेताओं की महत्वाकांक्षाएं भी इस चुनाव में एक अहम भूमिका निभाएंगी। कई नेता अकेले चुनाव लड़कर अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। आखिर में यह चुनाव मतदाताओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। वे अपने शहर और कस्बे के भविष्य का फैसला करेंगे। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि यह चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। मुकाबला कड़ा होगा और नतीजे अप्रत्याशित हो सकते हैं। इसलिए, अपनी नजरें बनाए रखें और देखें कि यह राजनीतिक नाटक कैसे सामने आता है।

● बिन्दु माथुर

कमबैक करने की चुनौती

कांग्रेस, शिवसेना (यूबीटी) और एनसीपी (एसपी) के एमवीए ने पिछले साल लोकसभा चुनाव में बड़ी सफलता हासिल की थी। हालांकि, छह महीने के भीतर, जब विधानसभा चुनाव हुए, तो एमवीए को लोकसभा के प्रदर्शन को दोहराने की उम्मीद थी। लेकिन, इसने कुल 288 सीटों में से केवल 49 सीटें जीतीं। भाजपा, शिवसेना और एनसीपी के महायुति गठबंधन ने 238 सीटों के साथ शानदार जीत दर्ज की। सरकार के गठन के तुरंत बाद एमवीए के सदस्यों ने पाला बदलना शुरू कर दिया। आगामी नगर निकाय चुनावों में, यह इसके लिए एक बड़ी चुनौती होगी। एक वरिष्ठ कांग्रेस सदस्य ने बताया कि महायुति को कड़ी टक्कर देने के लिए एमवीए को गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ना होगा।

प्रमोटी को नहीं मिल रही कलेक्टरी और कप्तानी

राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आरएएस) से प्रमोट होकर आईएएस-आईपीएस बने अफसरों को जिलों की कमान संभालने का मौका नहीं मिल पा रहा है। ज्यादातर जिलों और संभाग स्तर पर डायरेक्ट आईएएस-आईपीएस अफसरों को ही तैनात किया गया है। अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे सरकार के दौर में प्रमोटी अफसर ही पहली पसंद हुआ करते थे। गहलोत सरकार के पिछले कार्यकाल में तो एक समय 18 जिलों की कमान प्रमोटी आईएएस संभाल रहे थे। यह स्थिति तो तब थी, जब प्रदेश में जिलों की संख्या 33 ही थी। अब जिलों की संख्या 41 हो चुकी है। आखिर क्या कारण है, लंबा अनुभव रखने वाले प्रमोटी अफसरों को जिलों में मौका नहीं मिल पा रहा।

ब्यूरोक्रेसी के एक्सपर्ट की मानें तो 33 प्रतिशत प्रमोशन कोटा होने के बावजूद प्रमोटी आईएएस-आईपीएस को जिलों की कमान नहीं मिलने के पीछे असली वजह विवादों में नाम सामने आना है। पूर्व की सरकारों में प्रमोटी आईएएस के बीते कुछ सालों में कई घूसकांड में नाम सामने आए थे, जिससे सरकार की छवि खराब हुई।

राजेंद्र विजय: 2020 में प्रमोट होकर आईएएस बने राजेंद्र विजय को कोटा में संभागीय आयुक्त के पद पर जिम्मेदारी दी गई थी। वर्ष 2024 में एसीबी ने आईएएस राजेंद्र विजय के आवास पर रेड डाली थी। उन्हें आय से अधिक संपत्ति के मामले में एपीओ कर दिया था। गंभीर आरोपों के बावजूद राजेंद्र विजय फिलहाल सचिवालय में विभागीय जांच आयुक्त के पद पर हैं।

हनुमान मल ढाका: 2023 में प्रमोट होकर आईएएस बने हनुमान मल ढाका को गहलोत सरकार में बनाए गए नए जिले दूदू (अब जिला निरस्त) में कलेक्टर बनाया गया था। भू-रूपांतरण (जमीनों के कन्वर्जन) मामले में 25 लाख रुपए रिश्वत मांगने के आरोप में ढाका को एपीओ कर दिया था। तब से वह एपीओ ही चल रहे हैं।

इंद्रजीत सिंह राव: 2020 में प्रमोट कर इंद्रजीत सिंह राव को आईएएस बनाया गया था। उन्हें बारां में जिला कलेक्टर की जिम्मेदारी दी गई थी। पेट्रोल पंप संचालन की एनओसी जारी करने के मामले में उनका निजी (प्राइवेट) सचिव महावीर नागर 1.40 लाख रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया था। इस कांड में सीधे तौर पर तत्कालीन कलेक्टर इंद्रजीत सिंह राव के भी शामिल होने के आरोप थे। इसके बाद एसीबी ने उन्हें भी गिरफ्तार किया था। इंद्रजीत वर्तमान में रिटायर हो चुके हैं।

प्रेमसुख बिश्नोई: वर्ष 2021 में प्रमोट होकर आईएएस बने प्रेमसुख बिश्नोई को मत्स्य विभाग का डायरेक्टर बनाया गया था। एसीबी की टीम ने 19 जनवरी 2024 को प्रेमसुख बिश्नोई को 35 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। प्रेमसुख बिश्नोई अब रिटायर हो चुके हैं।

राजस्थान में आईएएस के 332 अफसरों का कैडर स्वीकृत है। पिछले कई सालों से कैडर रिव्यू नहीं हुआ है। जिलों की संख्या के हिसाब से प्रदेश को 380 से ज्यादा आईएएस की जरूरत है। महज 278 अफसर ही सेवाएं दे रहे हैं। राजस्थान में कुल कैडर स्ट्रेंथ के हिसाब से 33 प्रतिशत पद प्रमोशन से भरे जाते हैं। पहले 33 जिले हुआ करते थे, लेकिन अब 41 हैं। इनमें से 11 की कमान बतौर कलेक्टर प्रमोटी आईएएस संभाल रहे हैं। हालांकि, यह आंकड़ा गहलोत और वसुंधरा राजे सरकार की तुलना में बेहद कम है। प्रदेश में आईपीएस का 222 अधिकारियों का कैडर है, जबकि 206 कार्यरत हैं। महज 14 प्रमोटी आईपीएस जिलों की कमान संभाल रहे हैं।

गहलोत सरकार आने के बाद कोरोनाकाल में 18 से ज्यादा जिलों की कमान प्रमोटी आईएएस अधिकारियों के हाथ में थी। इसमें 15 आईएएस थे, जो आरएएस सेवा से प्रमोट हुए। 3 अधिकारी ऐसे थे, जो दूसरी सर्विस से प्रमोट होकर आईएएस बने और कलेक्टर बनाए गए। 2013 में वसुंधरा सरकार आने के बाद से साल 2021 तक गहलोत सरकार के समय तक 17-18 जिलों तक की कमान प्रमोटी अफसरों के हाथ में रही। साल 2008 से 2012 के बीच तो ज्ञान प्रकाश शुक्ला (भरतपुर), शिव कुमार अग्रवाल (बूंदी), गिरधारी लाल गुप्ता (कोटा), केके गुप्ता (जालोर) को आरएएस रहते हुए कलेक्टर बनाया गया था। हालांकि, एक्सपर्ट का कहना है कि ऐसा कोई कोटा तय नहीं है कि प्रमोटी अफसर को कितने जिलों में डीएम बनाया जाएगा। प्रमोटी अफसर काबिलियत में किसी से कम नहीं होते हैं।

आमतौर पर आरएएस से आईएएस में प्रमोशन पाने वाले अफसरों को पिछड़े जिलों में पोस्टिंग मिलती रही है। हालांकि, कई बार बड़े जिलों में भी पोस्टिंग दी जाती है। गहलोत के शासन ने प्रमोटी आईएएस जगरूप सिंह यादव को राजधानी जयपुर की कमान सौंपी गई थी। इसके बाद प्रमोटी आईएएस अंतर सिंह नेहरा भी जयपुर में कलेक्टर बनाए गए थे। गहलोत और वसुंधरा राजे के समय अफसरों की तैनाती लगभग एक जैसी रही है। अधिकांश प्रमोटी आईएएस-आईपीएस को झालावाड़, झुंझुनूं, सीकर, बाड़मेर, जैसलमेर, अलवर, चूरू और सिरोही में की कमान सौंपी गई। भजनलाल सरकार ने भी इस परिपाटी को जारी रखा है।

● जयपुर से आर.के. बिन्नानी

आखिर क्यों प्रमोटी अफसरों पर भरोसा ज्यादा?

रिटायर्ड आईजी सत्यवीर सिंह का कहना है कि प्रमोटी आईएएस या आईपीएस अफसरों का स्थानीय नेताओं से तालमेल बेहतर होता है। इस कारण नेता प्रमोटी अफसरों को अपने जिले में ले जाना अधिक पसंद करते हैं। लंबे समय तक फील्ड में रहने के कारण उनका नेटवर्क ज्यादा होता है। नेताओं के लिए ज्यादा सहूलियत होती है। एक्सपर्ट की मानें तो आईएएस या आईपीएस के राजनेताओं का ज्यादा तालमेल नहीं बैठ पाता और ज्यादा कानून-कायदों से चलने पर उनकी शिकायतें होने लगती हैं। इसके कारण नए डायरेक्ट वाले आईएएस-आईपीएस नेताओं को पसंद नहीं होते। रिटायर्ड आईजी सत्यवीर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री के आसपास रहने वाले अफसर ज्यादातर डायरेक्ट आईएएस सेवा के ही होते हैं। दूसरी वजह यह भी है कि प्रमोटी अफसरों की ऊपर तक पहुंच कम होती है। इसलिए अवसर नहीं मिल पाते हैं। मुख्य सचिव और डीजीपी भी सीधी भर्ती वाले अफसर ही बनते हैं। ऐसे में प्रमोटी अफसरों के साथ भेदभाव भी होता है। आरएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष महावीर खराड़ी कहते हैं कि जो पद प्रमोटी आईएएस के लिए आरक्षित हैं, सरकार उन्हें वहां भी नहीं लगाती है। ऐसे में कामकाज प्रभावित होता है। अफसरों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए।

उप्र में पीडीए का जलवा...

उप्र की राजनीतिक जमीन पर भारतीय जनता पार्टी अपनी अलग रणनीति के साथ उतरने की तैयारी में है। लोकसभा चुनाव में जिस पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए पॉलिटिक्स ने पार्टी को झटका दिया। अब उसी को हथियार बनाने की तैयारी है। दरअसल, भाजपा ने अगली जनगणना में जातिगत गणना का वादा किया है। इसके साथ ही पार्टी पीडीए को फिर से परिभाषित करने की रणनीति पर काम कर रही है। विपक्ष के पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक से लेकर पिछड़ा, दलित, अगड़ा यानी उच्च जाति के अपने संस्करण तक की राजनीति को विस्तार देने की योजना है। भाजपा सूत्रों का कहना है कि इस कदम से पार्टी को विपक्ष के पीडीए पॉलिटिक्स का मुकाबला करने में मदद मिल सकती है। समाजवादी पार्टी के पीडीए पॉलिटिक्स को लेकर दावा किया जाता है कि इसने 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान उप्र में भगवा संगठन को चुनावी रूप से नुकसान पहुंचाया है। पार्टी ने हिंदू समुदाय के बीच जातिगत एकता का संदेश देने के लिए विभिन्न प्लेटफार्मों पर ओबीसी, एससी और उच्च जाति को एक साथ लाकर रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है।

सूत्रों ने बताया कि दलित नेता बीआर अंबेडकर की जयंती के अवसर पर इसकी शुरुआत की गई थी, जब भाजपा ने अपने उच्च जाति के पदाधिकारियों से दलित बहुल दूरदराज के इलाकों में अंबेडकर की मूर्तियों की सफाई में दलितों के साथ मिलकर काम करने को कहा था। अब यह और भी साफ हो गया है, जब राज्य महासचिव (संगठन) धर्मपाल सिंह ने एससी समुदाय के सदस्यों का सम्मेलन आयोजित किया। धर्मपाल सिंह ओबीसी समुदाय से आते हैं। इस कार्यक्रम में प्रमुख उच्च जाति के पदाधिकारियों को आमंत्रित किया गया। उप्र भाजपा एससी मोर्चा के प्रमुख राम चंद्र कन्नौजिया ने कहा कि दलित समुदाय काफी हद तक एक भ्रमित समूह है, जो आसानी से राजनीतिक दलों के बहकावे में आ जाता है। उन्होंने कहा कि उन्हें उच्च जाति के साथ लाने से न केवल दलितों का हौंसला बढ़ेगा, बल्कि जाति-विभाजित हिंदू समुदाय के भीतर एकता का संदेश भी जाएगा। उन्होंने कहा कि दलितों के बीच व्याप्त उच्च जाति विरोधी धारणा को खत्म किया जाना चाहिए, ताकि एक एकजुट समाज का निर्माण किया जा सके। यह पार्टी की विचारधारा में माना जाता है।

विशेषज्ञों के अनुसार, पीडीए को फिर से परिभाषित करने का भाजपा का प्रयास जाति आधारित चुनावी राजनीति में एक स्पष्ट रणनीतिक धुरी होगा। खासकर उप्र में इसका असर दिखेगा। उन्होंने कहा कि अपने स्वयं के पीडीए के निर्माण के माध्यम से भाजपा का गुप्त संदेश पार्टी को विपक्ष के आक्रामक कथानक को बेअसर करने में मदद कर सकता है, जिसका उद्देश्य ओबीसी, दलित और अल्पसंख्यकों को एकजुट करना है। अपने पारंपरिक अल्पसंख्यक वोट बैंक को भुनाने के लिए जानी जाने वाली सपा ने पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के साथ बाबासाहेब अंबेडकर की तस्वीर जारी की थी। इसके जरिए ओबीसी-दलित एकीकरण का मुद्दा उठाया। इस मुद्दे पर भाजपा की ओर से तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई। सूत्रों ने कहा कि भाजपा दलित समुदाय को सपा सरकार के तहत कथित अत्याचारों के बारे में याद दिलाने की कोशिश कर रही थी।

विश्लेषकों ने कहा कि विपक्ष, विशेष रूप से इंडिया ब्लॉक के तहत, भाजपा को उच्च जातियों का पक्ष लेने और पिछड़े-अल्पसंख्यक समुदायों की उपेक्षा करने के रूप में चित्रित करके ओबीसी और दलितों के बीच बढ़त हासिल की। पीडीए को शामिल करके और फिर से परिभाषित करके, भाजपा उस बढ़त को बेअसर कर सकती है। भाजपा के पीडीए संस्करण में खास यह है कि इसमें से ए यानी अल्पसंख्यक शब्द को हटा दिया गया है। यह हिंदू सामाजिक गठबंधन पर इसके फोकस और मुस्लिम तुष्टिकरण के आरोपों को रणनीतिक रूप से दरकिनार करने का संकेत देता है। कुछ ऐसा जिसे पार्टी अक्सर अपने चुनावी संदेश में भुनाती है। अब हिंदू एकजुटता के मुद्दे को नए तरीके से पेश करने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। पीडीए को फिर से तैयार करने का भाजपा का कदम बसपा प्रमुख मायावती के सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले से मिलता-जुलता है। मायावती ने ब्राह्मणों और दलितों को एकजुट कर बहुजन से सर्वजन तक का नारा दिया था। इसने 2007 में इसे पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में पहुंचा दिया था।

● **लखनऊ से मधु आलोक निगम**

कमजोर पड़ सकता है हिंदुत्व का एजेंडा

बटेंगे तो कटेंगे जैसे धारदार नारे के साथ योगी आदित्यनाथ की राजनीति जो रफ्तार भर रही थी, जाति जनगणना उसके रास्ते में बड़ा स्पीडब्रेकर है। योगी आदित्यनाथ का ये नारा हिंदुत्व की राजनीति का असरदार नारा साबित हो रहा था, लेकिन जातीय राजनीति के हावी होने की सूरत में तो हिंदुत्व का एजेंडा कमजोर ही होगा। हिंदुत्व का एजेंडा कमजोर होगा तो ऐसे नारे अपने आप पीछे छूट जाएंगे। फिर तो हल्ला बोल और तिलक, तराजू और तलवार जैसे नारों का ही बोलबाला होगा। और वैसी सूरत में जय श्रीराम के नारे को भी मजबूत सपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है। लोकसभा चुनाव 2024 के अयोध्या का नतीजा सबसे बड़ा उदाहरण है। ये ठीक है कि समाजवादी पार्टी से मिल्कीपुर सीट छीनकर योगी आदित्यनाथ ने बदला पूरा कर लिया है, लेकिन आगे और भी ऐसी लड़ाइयां लड़नी पड़ेंगी, ये करीब-करीब पक्का है। जिस तरह लोकसभा चुनाव में भाजपा की सीटें कम हो जाने के बाद ओबीसी नेता केशव प्रसाद मौर्य सरकार और संगठन में फर्क समझाते हुए योगी आदित्यनाथ पर सीधा हमला बोल रहे थे, ऐसी चुनौतियां और भी बढ़ेंगी। कुछ दिन तक कुलांचे भरने के बाद ऊपर से इशारा होते ही केशव प्रसाद मौर्य के तेवर ठंडे पड़ गए थे, लेकिन आगे भी बिल्कुल ऐसा ही हो, जरूरी तो नहीं है। अभी तो एक ही केशव प्रसाद मौर्य हैं, जाति जनगणना के बाद तो अलग-अलग जातियों के नेता भी सामने आएंगे। और तब ये भी हो सकता है कि मप्र जैसा प्रयोग उप्र में भी आजमाया जाने लगे, और आलाकमान शिवराज सिंह चौहान की तरह वैकल्पिक इंतजाम भी कर डाले।

बिहार में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं। इसे लेकर जदयू, राजद, भाजपा और कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बिहार की इस सियासत में गठबंधन की राजनीति की बड़ी भूमिका रही है। यहां राष्ट्रीय के साथ क्षेत्रीय दलों की पैठ लंबे समय से है। आलम यह है कि बिहार में आखिरी बार किसी दल की अकेले दम पर सत्ता 1985 के चुनाव में आई थी। इसके बाद से हुए अगले आठ चुनावों में गठबंधन की ही सरकार बनी है। गठबंधन के इस दौर में क्षेत्रीय दलों का रसूख भी लगातार बढ़ा है।

आखिर बिहार में क्षेत्रीय दलों का दबदबा कहां से शुरू होता है? कांग्रेस का प्रभाव कैसे कमजोर हो गया? राजद और जदयू किस तरह बिहार के चुनावी पटल पर स्थापित हो गईं? 1990 से लेकर 2020 तक चुनावों में किस दल की क्या स्थिति रही? यह जानना जरूरी है। 1988 में कई दलों के विलय से जनता दल बना। 1990 के चुनाव में जनता दल 122 सीटें जीतकर सबसे बड़ा दल बना। भाजपा के समर्थन से सत्ता में आया और लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने। पहली बार किसी गैर-कांग्रेसी मुख्यमंत्री ने अपना कार्यकाल पूरा किया। 1990 का चुनाव इस लिहाज से भी अहम रहा कि इनके बाद राज्य में एक कार्यकाल में कई मुख्यमंत्रियों का दौर खत्म हो गया। लालू 1995 तक बेरोकटोक सरकार चलाने में भी सफल रहे। हालांकि, इसी दौर में राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर जनता दल का कमजोर होना शुरू हुआ। 1994 में नीतीश कुमार, जॉर्ज फर्नांडिस जनता दल से अलग हुए और समता पार्टी बनाई। आरोप था कि लालू प्रसाद यादव बिहार में वोटबैंक की राजनीति कर रहे हैं।

1995 के चुनाव में भले ही नीतीश और लालू साथ नहीं थे, लेकिन दोनों की अलग-अलग पार्टियां अभी भी अस्तित्व में नहीं थीं। लालू ने जनता दल का नेतृत्व जारी रखा और 167 सीटों पर फिर जीत हासिल की। इस चुनाव में भाजपा को 41 सीट और कांग्रेस को 29 सीटें मिलीं। समता पार्टी को 7 और झामुमो को 10 सीट मिलीं। लालू प्रसाद यादव एक बार फिर मुख्यमंत्री बने। हालांकि, 1997 आते-आते लालू पर चारा घोटाले के आरोप लगे और उन्हें बिहार के मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ा। लालू ने अपनी पत्नी राबड़ी देवी के हाथ में सत्ता सौंप दी। इसी दौर में लालू ने अपना अलग राष्ट्रीय जनता दल (राजद) बनाया। इसके बाद बिहार की सियासत में क्षेत्रीय दलों का दबदबा कायम है।

बिहार में साल 2000 का चुनाव मार्च में हुआ था। गौर करने वाली बात यह है कि तब तक बिहार से झारखंड अलग नहीं हुआ था। इस चुनाव में भी राजद मजबूती से उभरी। उसने 324 में से 293 सीटों पर चुनाव लड़ा और 124 सीटें जीतीं। पार्टी बहुमत से दूर रह गई। दूसरी तरफ भाजपा को इस चुनाव में बढ़त मिली और उसे 168 में से 67 सीटें मिलीं। नीतीश कुमार की समता पार्टी 34 सीट और कांग्रेस 23 सीटें जीतने में सफल रही। क्षेत्रीय दलों के लिहाज से 1999 और 2000 अहम रहा। बिहार में जनता दल पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर था। दरअसल, रामविलास पासवान अलग होकर लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) बना चुके थे। वहीं, राष्ट्रीय स्तर पर भी जनता दल का अंत करीब आ गया। बिहार में शरद यादव ने जनता दल का नेतृत्व किया, लेकिन यह पार्टी राष्ट्रीय तो छोड़िए, क्षेत्रीय स्तर पर भी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही थी।

2000 में खंडित जनादेश के चलते सरकार बनाने की जंग छिड़ गई। नीतीश कुमार ने अपनी समता पार्टी के लिए भाजपा और अन्य दलों के गठबंधन के जरिए पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। हालांकि, उनके पास कुल-मिलाकर भी महज 151 विधायकों का ही समर्थन था, जो कि बहुमत के आंकड़े 163 से कम ही था। इसके चलते नीतीश को 7 दिन में ही अपना पद छोड़ना पड़ा। बिहार की कमान एक बार फिर राजद के हाथों में आ गई और लालू के जोड़-तोड़ की बदौलत राबड़ी देवी फिर मुख्यमंत्री बनीं। बिहार में फरवरी 2005 में फिर चुनाव हुए। यह पहले चुनाव थे, जब झारखंड अलग राज्य बन चुका था और बिहार में कुल सीटों की संख्या 243 पर आ चुकी थी। राजद ने 215 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन उसे 75 सीटें मिलीं। एनडीए गठबंधन में लड़ रही जदयू ने 138 सीटों पर चुनाव लड़ा, वह 55 सीटें हासिल कर सका। 103 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली भाजपा को 37 सीटें मिलीं। इस तरह 92 सीटें जीतने वाला एनडीए भी बहुमत से दूर रह गया। इस चुनाव में 29 सीटें पाने वाली लोजपा भी प्रमुख क्षेत्रीय दल के तौर पर उभरी। लेकिन गठबंधन की कोशिशें सफल नहीं हुईं और आखिरकार बिहार में अक्टूबर में फिर चुनाव हुए।

महज सात महीने बाद हुए चुनाव में एक और क्षेत्रीय दल का जबरदस्त उभार हुआ। यह था- जनता दल (यूनाइटेड), जो कि नीतीश कुमार की समता पार्टी और शरद यादव के जनता दल के विलय के बाद बना। इस पार्टी ने एनडीए के साथ लड़ते हुए 88 सीटें हासिल कीं, वहीं भाजपा 55 सीटें पाने में कामयाब रही। यानी क्षेत्रीय दल किंग और राष्ट्रीय पार्टी बनी किंगमेकर। नीतीश कुमार बने राज्य के मुख्यमंत्री। राजद इस चुनाव में 54 सीटें ही जीत सका। लोजपा 10 और कांग्रेस सिर्फ 9 सीटें हासिल कर पाई। 2010 के चुनाव में नीतीश को अपनी योजनाओं का जबरदस्त फायदा हुआ। जदयू और भाजपा गठबंधन 243 में से 206 सीटें जीतने में सफल रहा। एनडीए का वोट प्रतिशत भी करीब 40 फीसदी तक पहुंच गया।

● **विनोद बक्सरी**

नीतीश की सीटें घटीं, लेकिन क्षेत्रीय दल ही रहा राजा

बिहार में क्षेत्रीय दलों की राजनीति पर पकड़ किस कदर मजबूत है, इसका एक उदाहरण 2020 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला। जब एनडीए में शामिल जदयू महज 43 सीट ही जीत पाई, जबकि राष्ट्रीय दल भाजपा को 74 सीटें मिलीं। इसके बावजूद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने। यानी एक बार फिर कम सीट पाकर भी क्षेत्रीय दल बना किंग और ज्यादा सीट हासिल करने के बावजूद राष्ट्रीय दल किंगमेकर बना। इस चुनाव में महागठबंधन को 110 सीटें मिलीं। राजद को 75, कांग्रेस को 19, भाकपा-माले को 12, भाकपा को 2 और माकपा को 2 सीटें मिलीं। यानी विपक्षी गठबंधन में एक क्षेत्रीय दल सबसे बड़ी पार्टी बनी और राष्ट्रीय दल का प्रदर्शन एक बार फिर खराब रहा। बिहार में क्षेत्रीय दलों का दौर शुरू होने के बाद से ही राष्ट्रीय दल कभी भी उनसे आगे नहीं निकल पाए। यानी वजह रही कि बिहार में हमेशा स्थानीय पार्टियों के ही मुख्यमंत्री बने हैं। बिहार में भाजपा का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 91 सीट हासिल करने का है, जो उसे 2010 के विधानसभा चुनावों में मिलीं। लेकिन इसी चुनाव में उसके साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही जदयू को 115 सीटें हासिल हुई थीं। इसी तरह 2020 में भले ही भाजपा ने 74 सीटें हासिल कर लीं, लेकिन राजद 75 सीटें पाकर सबसे बड़ा दल बना और बिहार की राजनीति में क्षेत्रीय दल का दबदबा कायम रखा।

बांग्लादेश में सत्ता संघर्ष गहराया

भारत के एक्शन से अब बांग्लादेश में हड़कंप

बांग्लादेश की कमान मोहम्मद यूनुस के हाथ में आने के बाद से ही भारत से उसके रिश्ते खराब होते जा रहे हैं। मोहम्मद यूनुस ने भारत के एहसानों को भूलते हुए पाकिस्तान और चीन से हाथ मिलाया है। लेकिन भारत ने भी कई कदम ऐसे उठाएं हैं जिनके बाद यूनुस को औकात याद आ गई है। भारत के खिलाफ बांग्लादेश के रुख ने नई दिल्ली को निराश किया है। हाल में पूरे भारत में रह रहे अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ भारत सरकार अभियान चला रही है। जिसमें अवैध बांग्लादेशियों को ढूंढ-ढूंढ कर वापस भेजा जा रहा है। भारत के इस कदम से यूनुस सरकार बौखला गई है और नई दिल्ली से गुहार लगाने लगी है। भारत सरकार ने जबसे अवैध बांग्लादेशियों को धक्के मार भारत से भगाना शुरू किया है। तभी से यूनुस सरकार परेशान है। इस कार्रवाई के बाद बांग्लादेश नई दिल्ली को एक राजनयिक नोट भेजा है। जिसमें इस तरीके से बांग्लादेशियों को भेजने का विरोध किया गया है और भारत सरकार से अपील की गई है कि वह ऐसा न करें। बांग्लादेश ने 7 और 8 मई को भारत की ओर से अवैध लोगों को सीमा पर छोड़ने के बाद एक राजनयिक नोट भेजा। हालांकि, खबर है कि खगराछारी जिले की सीमा पर 200 से 300 लोग जमा हो गए। इनमें से 78 को 9 मई को बीएसएफ की ओर से सुंदरवन के सुदूर मंदारबरिया चार में एक जहाज पर लाद दिया गया था।

जहां एक ओर पाकिस्तान की सेना अपने आप को यह साबित कर रही है कि जिहाद से वह पीछे नहीं हटती है, तो वहीं अब तक कथित रूप से धर्मनिरपेक्ष माने जाने वाले बांग्लादेश से भी ऐसे समाचार आ रहे हैं, जो यह बता रहे हैं कि बांग्लादेश भी अब औपचारिक रूप से कट्टरपंथ की ओर चल पड़ा है। जहां एक ओर लोग यह देख रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान की सेना और आतंकवादियों के बीच भेद मिट गया है तो वहीं बांग्लादेश में भी राजनीतिक दल और मजहबी कट्टरपंथी पार्टियों के बीच का सारा भेद मिटने जा रहा है, क्योंकि बांग्लादेश को बांग्लादेश की पहचान दिलाने वाली अवामी लीग पर मोहम्मद यूनुस की सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि, यह प्रतिबंध कहा जा रहा है कि कुछ समय के लिए है। कुछ समय अर्थात् यह तब तक रहेगा जब तक इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल एक्ट के अंतर्गत हजारों आंदोलनकारियों की मौत पर शेख हसीना और उनकी पार्टी पर मुकदमा चल रहा है और यह समाप्त नहीं हो जाता। अवामी लीग की छात्र शाखा बांग्लादेश छात्र लीग पर अक्टूबर में पहले ही प्रतिबंध लग चुका है। उसे आतंकी संगठन का तमगा देकर यह प्रतिबंध लगाया था।

बांग्लादेश की अवामी लीग के प्रति मोहम्मद यूनुस सरकार की और उनके सहयोगियों की घृणा किसलिए है, अब यह समझना कठिन नहीं रह गया है। यह शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर्रहमान ही थे, जिन्होंने पाकिस्तान द्वारा अपने ही नागरिकों पर किए जा रहे अत्याचारों के विरोध में बांग्लादेश के लिए आंदोलन किया था और भारत की सहायता से एक आजाद मुल्क पाया था, जिसका आधार इस्लाम तो था ही, परंतु भाषा भी थी। चूंकि अत्याचार का आधार भाषा थी, इसलिए जो मुल्क नया बना उसमें भाषाई पहचान ही मुख्य पहचान रही। हालांकि उस भाषाई पहचान के साथ इस्लाम की पहचान भी मुख्य थी और यही कारण है कि सरकार कोई भी रही हो, बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ अत्याचार हर सरकार में होते रहे। फिर भी अवामी लीग की छवि काफी हद तक धर्मनिरपेक्ष रही थी। ऐसा माना जाता है कि हिंदू अवामी लीग के स्वाभाविक समर्थक हैं और यही कारण है कि जब शेख हसीना देश छोड़कर गईं तो हिंदुओं पर हुए हमलों को धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक कारणों से प्रेरित बताया। बांग्लादेश ने बार-बार यही कहा कि हिंदुओं पर हिंसा तो हुई है, परंतु उनका कारण राजनीतिक है क्योंकि हिंदू अवामी लीग के समर्थक हैं और अवामी लीग के प्रति लोगों के दिल में गुस्सा था। मगर अवामी लीग के प्रति इतना गुस्सा क्यों है कि देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उसे भाग ही लेने नहीं दिया जा रहा है? उसे प्रतिबंधित कर दिया गया है? दरअसल शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग बांग्लादेश को उस पहचान से दूर करती है, जो उसने मुस्लिम लीग की स्थापना के समय हासिल की थी। इस प्रतिबंध से नोबल विजेता मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि अब नया बांग्लादेश बनेगा। इस नए बांग्लादेश में उसका वह इतिहास शामिल नहीं होगा, जो उसने वर्ष 1971 में हासिल किया था, बल्कि उसका वही इतिहास होगा जो वर्ष 1906 से आरंभ हुआ था और जिसकी परिणीति 1947 में पूर्वी पाकिस्तान के रूप में हुई थी।

कई कट्टरपंथी दल यूनुस सरकार से यह मांग कर रहे थे कि शेख हसीना की पार्टी को चुनावों में भाग लेने से रोका जाए और सड़कों पर आंदोलन भी कर रहे थे। वे मोहम्मद यूनुस को ऐसा न करने पर परिणाम भुगतने की धमकी भी दे रहे थे। अब चूंकि इस दबाव के कारण मोहम्मद यूनुस ने शेख हसीना की पार्टी को प्रतिबंधित कर दिया है, तो यह मान लिया जाना चाहिए कि अब मोहम्मद यूनुस की सरकार ने बांग्लादेश को पूरी तरह से इस्लामिक देश बनाने की तरफ औपचारिक कदम बढ़ा दिया है। शेख हसीना को देश से निकाला जाना कोई राजनीतिक कारणवश नहीं था, बल्कि वह एक पहचान की लड़ाई थी, और उसी महजबी पहचान की स्थापना की लड़ाई थी, जो 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना के साथ हासिल की थी और जिसे शेख मुजीबुर्रहमान ने वर्ष 1971 में उस मुल्क से छीन लिया था। शानबाग में गत दिनों इस बात के लिए आंदोलन जारी रहा था कि अवामी लीग को प्रतिबंधित किया जाए। सबसे हैरानी की बात यह है कि इस विरोध प्रदर्शन में कुछ लोगों ने जब बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान गाना चाहा, तो उन्हें रोक दिया गया था।

अवामी लीग पर प्रतिबंध की मांग करने वालों में मुफ्ती जसिमुद्दीन रहमानी भी शामिल था। यह एक कट्टरपंथी मौलाना है, जिसे एक समय में अमेरिका आधारित आतंकवाद विरोधी प्रोजेक्ट द्वारा चरमपंथ फैलाने के रूप में गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि वह अलकायदा का समर्थन करने वाले अनवर अल अवलकी का समर्थक था। उसने भी शेख हसीना के खिलाफ रैली की थी और भड़काऊ और उकसाने वाले भाषण दिए थे। उसने सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर वह अवामी लीग को प्रतिबंधित नहीं करेगी तो लोग मामला अपने हाथ में ले लेंगे।

● ऋतेन्द्र माथुर

डोनाल्ड ट्रंप ने जो व्यापार युद्ध छेड़ा है उसे चीन को छोड़ बाकी तमाम देशों के लिए विराम देकर और स्पष्ट कर दिया है। इस बीच चीन पर उन्होंने 145 फीसदी टैरिफ ठोक दिए, तो चीन ने भी जवाब में अमेरिका पर 125 फीसदी टैरिफ लगा दिया। चीन भारत के लिए जिस उपमा का प्रयोग करता है उसका उससे माफी मांगते हुए प्रयोग करें तो कहा जा सकता है कि यह दो महाबली हाथियों की टक्कर है। जब दो हाथी आपस में भिड़ जाते हैं तब क्या होता है यह हम अच्छी तरह जानते हैं। तब छोटे-मोटे जीव पिस जाते हैं।

दो महाशक्तियों के इस व्यापार युद्ध ने सभी प्रभावित देशों के लिए संभावनाओं के दरवाजे खोल दिए हैं। ऐसे देशों में भारत सबसे बड़ा और सबसे निर्णायक देश है। इन टैरिफों के मद्देनजर भारत कम-से-कम इतना तो कर ही सकता है कि अमेरिका के बाजारों के लिए ऐसी चीजें बनाए जिनमें चीन उसकी बराबरी नहीं कर सकता। ऐसी सबसे पहली चीज एप्पल फोन हो सकती है लेकिन, चीन अमेरिका को जो चीजें निर्यात करता है उनकी सूची पर नजर डालें और उन पर 30-40 फीसदी की ड्यूटी जोड़ दें (वैसे, 145 फीसदी की टैरिफ में अंततः कटौती की जाएगी) तो अरबों डॉलर मूल्य के निर्यातों की संभावना बनती है। इसी तरह, अमेरिका से चीन को निर्यात की जाने वाली कुछ चीजें भारत, टैरिफों में अंतर के मद्देनजर, उसे निर्यात कर सकता है।

किसी दोस्त या सहयोगी की दुविधा का लाभ उठाना आमतौर पर अच्छी बात नहीं मानी जाती लेकिन ऐसे वक्त में, जिसे ट्रंप ने असामान्य बना दिया है और जब वे अपने साथियों के प्रति आक्रामक और अपमानजनक रवैया अपना रहे हैं, इसे बुरा नहीं माना जाना चाहिए। ट्रंप बयान दे रहे हैं कि वे सब मुझे फोन करके कह रहे है कि सर, यह सौदा हमसे कर लीजिए, हम कुछ भी करने को तैयार हैं। ट्रंप यह सब चीन के लिए नहीं बल्कि बाकी उन 75 देशों के लिए कह रहे हैं जो उनके सहयोगी हैं, जिनमें यूरोप, ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख देश और भारत भी शामिल है। हम यह तो कहते रहते हैं कि किसी संकट का लाभ उठाने से मत चूको, लेकिन इधर भारत ने ऐसे अवसरों का लाभ नहीं उठाया है। कोविड के संदर्भ में जो वादे किए गए थे उन सबको भुला दिया गया है। कृषि सुधारों के कानून और श्रम कानून (जिनका इस लेखक ने स्वागत किया था) हवा-हवाई हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने 2021 में साफ-साफ कहा था कि सरकार रणनीतिक मामलों को छोड़ व्यवसाय के सभी क्षेत्र निजी क्षेत्र के हवाले कर देगी। लेकिन एअर इंडिया की बिक्री, जिसकी प्रक्रिया 2017 से चल रही थी, के सिवा निजीकरण की अब कोई बात भी नहीं की जाती।

भारत की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी

भारत को मैन्युफैक्चरिंग को संरक्षण और कृषि के मामले में इतिहास प्रदत्त हिचक के दोहरे दबाव से मुक्त होने और नई आर्थिक आजादी का दावा करने का समय आ गया है। संरक्षणवाद से मुक्ति भारतीय उद्योग, इस्पात उद्योग को भी समाजवादी दूध पी-पीकर मोटे होते जाने की बजाय प्रतिस्पर्धी बनाएगी। और इतिहास प्रदत्त हिचक से मुक्ति कृषि सुधारों की ओर वापसी की रफ्तार बढ़ाएगी, और अतिरिक्त उत्पादन कर रहे भारतीय किसान को गेहूं-चावल की गिरफ्त से बाहर निकालेगी। इस सबके लिए राजनीतिक कौशल और साहस की जरूरत होगी। इस स्तर के आर्थिक सुधार ही भारत को नुकसान से बचाकर अपने हितों की सुरक्षा तथा उन्हें आगे बढ़ाने में सक्षम बनाएंगे। इस तरह का मौका किसी पीढ़ी को एक बार ही मिलता है। दो हाथी, आपके एक सबसे अच्छे मित्र और सबसे बुरे प्रतिद्वंद्वी आपस में गुत्थमगुत्था हैं। अब फैसला आपको करना है कि आप क्या बनना चाहते हैं। आप बेशक कुचले जाने वाली घास नहीं बनना चाहेंगे।

आईडीबीआई बैंक का लगभग हो चुका निजीकरण अभी लगभग के चक्र में ही उलझा हुआ है। इस साल के बजट में 5 ट्रिलियन रुपए पीएसयू में निवेश के लिए रखे गए हैं। मोदी सरकार ने प्रशंसनीय काम यह किया कि महामारी के दौरान धैर्य बनाए रखा, कई पश्चिमी लोकतांत्रिक देशों की तरह नोट छापकर नहीं बांटे और वित्तीय घाटे को संभाला। लेकिन अफसोस की बात यह है कि लंबे समय से जिस बड़े सुधार की उम्मीद की जा रही थी वह संकट का लाभ उठाने से चूक गया। सरकार ने आत्मनिर्भरता और मेक इन इंडिया पर आधारित एक नया आर्थिक एजेंडा पेश किया। उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहनों (पीएलआई) और व्यवसाय करने की सुविधाओं (ईओडीबी) के नाम पर बड़ी राशियां आवंटित करने का वादा किया गया। पीएलआई के मोर्चे पर आधी-अधूरी प्रगति हुई है। मैन्युफैक्चरिंग गतिरोध में फंस गया है। कुछ पीएलआई आगे बढ़ी है, मुख्यतः आईफोन के मामले में। और देखिए कि इस एक चीज ने हाथियों की लड़ाई के बीच भारत को कितनी ताकत दी है।

ईओडीबी के मोर्चे पर क्या हालत है? भारत की रैंकिंग बेहतर हुई है लेकिन घिसटती हुई। इसके बारे में उद्यमी और सीरियल निवेशक मोहनदास पई आपको ज्यादा बता सकते हैं, जो सरकार के खुले आलोचक हैं। उन जैसे अनुभवी अगर इतने हताश हैं तो आप कल्पना कर सकते हैं कि नए उद्यमियों की क्या हालत होगी। जीएसटी को मोदी दशक में किया गया एक युगांतरकारी आर्थिक सुधार बताया जाता है। लेकिन मझोले और लघु उद्यमियों (एमएसएमई) से पूछिए कि इसकी प्रक्रियाएं कितनी उलझन भरी, कानूनी रूप से विवादित और आर्थिक रूप से बोझिल हैं। इसी मानसिकता वाली उसी जमात को देखें, तो उसे जो भी नई सिस्टम दी जाती है उसे वह उसी पुरानी मशीन गन का नया मॉडल ही मानती है।

घास की तरह कुचले जाने से बचने के लिए भारत को कोविड युग वाले सुधारों के विचार को अपनाना होगा। व्यापार वाला मसला पूरी तरह मैन्युफैक्चर्ड और कृषि सामान तक सीमित रहेगा। अमेरिका को हमारे कुल निर्यात में 40 फीसदी हिस्सा सर्विस सेक्टर का है लेकिन यह गिनती में नहीं है। इन पर कोई टैरिफ नहीं लगता क्योंकि कोई सामान सीमा पार नहीं जाता। चीन से जो पलायन हो रहा है उसका लाभ उठाने के लिए भारत नई मैन्युफैक्चरिंग कितनी जल्दी शुरू कर सकता है? इसके विपरीत, टैरिफों में अगर भारी कटौती की गई (जो निश्चित ही की जाएगी और की जानी चाहिए) तब हमारी मैन्युफैक्चरिंग क्या इतनी मजबूत है कि अपना वजूद बचा सकेगी? इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए? सब्सिडी देना आलसी, प्रतिगामी, महंगा कदम होगा, और ट्रंप इसे अनुचित बताकर खारिज कर देंगे।

● सुश्री नित्या

अर्थव्यवस्था में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी

सरकार की ओर से अप्रैल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी पीएमएमवाई ने पिछले एक दशक में भारतीय महिलाओं के जीवन पर अभूतपूर्व प्रभाव डाला है। यह रिपोर्ट बताती है कि मुद्रा योजना के प्रभाव से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के ऋण प्रवाह में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ध्यान रहे कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को आरंभ करने का मूल उद्देश्य माइक्रोफाइनेंस ऋण को औपचारिक रूप देते हुए हाशिए पर खड़े लोगों को सहजता से ऋण प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध कराना था। इन दस वर्षों में मुद्रा योजना ने भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार देने में ही अपनी भूमिका नहीं निभाई, बल्कि महिला सशक्तीकरण की एक नवीन पटकथा भी लिखी है। यह निर्विवाद है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था तब तक सुदृढ़ नहीं हो सकती, जब तक कि उसमें आधी आबादी की सहभागिता न हो। इसमें दोराय नहीं कि विगत दशक में देश में मजबूत सरकारी नीतियों एवं योजनाओं का ढांचा निर्मित किया गया है, जिससे न केवल भारत की अर्थव्यवस्था की मूल विशेषता यानी कुटीर एवं लघु उद्योगों को बल मिला है, बल्कि देश की आधी आबादी भी आर्थिक सशक्तता का नवीन अध्याय लिखने को उन्मुख हुई है। एमएसएमई क्षेत्र न केवल आर्थिक विकास की गति को तीव्रता देते हैं, अपितु वे महिला सशक्तीकरण के महत्वपूर्ण वाहक भी हैं। प्रधानमंत्री जन-धन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया भारत की अर्थव्यवस्था को एक सुदृढ़ ढांचा प्रदान कर रहे हैं, जिससे एमएसएमई क्षेत्र भारत की आर्थिक प्रगति की आधारशिला बनकर उभरा है।

हाल के वर्षों में राष्ट्रीय आर्थिक उत्पादन में एमएसएमई की हिस्सेदारी 2021-22 के 28.6 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 30.01 प्रतिशत हो गई, जो अर्थव्यवस्था में इसकी बढ़ती भूमिका को उजागर करती है। एमएसएमई से निर्यात में भी पर्याप्त बढ़ोतरी देखी गई है, जो वित्त वर्ष 2020-21 में 3.95 लाख करोड़ से बढ़कर 2024-25 में 12.39 लाख करोड़ हो गई। एमएसएमई के लिए मुद्रा योजना एक जीवनरेखा बनकर उभरी है। बीते वर्ष जारी अपनी एक रिपोर्ट में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी पुष्टि की थी कि पीएमएमवाई जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से उद्यमिता के लिए भारत का सक्षम नीतिगत परिवेश ऋण तक पहुंच के माध्यम से स्वरोजगार बढ़ाने में सक्रिय रूप से योगदान दे रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात है एमएसएमई में देश की महिलाओं की बढ़ती उपस्थिति। इसका सबसे बड़ा कारक उनकी ऋण तक सहज पहुंच का होना है। एसबीआई की रिपोर्ट बताती है कि बैंक के कुल ऋण में एमएसएमई की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2013-14 में 15.8 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में लगभग 20 प्रतिशत हो गई। इस विस्तार ने छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्र में व्यवसायों को वित्तीय सहायता तक पहुंचने में सक्षम बनाया, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था सशक्त हुई है। मुद्रा योजना के कुल लाभार्थियों में 68 प्रतिशत महिलाएं हैं, जो देशभर में महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्योगों को आगे बढ़ाने में इस योजना की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। वित्त वर्ष 2015-16 से 2024-25 के बीच प्रति महिला प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की वितरण राशि वर्ष दर वर्ष 13 प्रतिशत से बढ़कर 62,679 रुपए तक पहुंच गई, जबकि प्रति महिला वृद्धिशील जमा राशि वर्ष दर वर्ष 14 प्रतिशत बढ़कर 95,269 रुपए हो गई।

आखिर महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यम क्यों आर्थिकी के मजबूत चालक के रूप में देखे जा रहे हैं? इसका उत्तर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एडवांसिंग जेंडर पैरिटी इन आंत्रप्रेन्योरशिप स्ट्रैटेजी फॉर ए मोर इक्वेटेबल फ्यूचर नामक रिपोर्ट देती है। उसके अनुसार महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसाय विविध दृष्टिकोण लाते हैं, समावेशी नेतृत्व को बढ़ावा देते हैं और अक्सर सामाजिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान के लिए नवीन दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन न केवल विकास को गति देता है, अपितु निर्धनता और असमानताओं को भी कम करता है। इतना ही नहीं, बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और शैक्षणिक प्रदर्शन में भी सुधार करता है। पुरुषों की तुलना में महिलाएं अपेक्षाकृत अपनी आय का अधिक हिस्सा परिवार एवं समुदाय के उन्नयन पर खर्च करती हैं। कोविड काल में भी पीएमएमवाई योजना के जरिये महिला उद्यमियों ने बचत जारी रखी। बचत की यही प्रवृत्ति देश के बड़े आर्थिक लक्ष्यों की पूर्ति में सहायक होती है।

● **ज्योत्सना अनूप यादव**

उच्च पदों पर भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता

महिलाओं की उच्च पदों पर भागीदारी बढ़ाना आवश्यक है, क्योंकि विश्व आर्थिक मंच की नवीनतम ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट दर्शाती है कि जिन समाजों में राजनीतिक नेतृत्व में महिलाओं की भागीदारी अधिक होती है, वे अधिक समृद्ध और समानतापूर्ण होते हैं। जिन देशों में महिलाओं का उच्च पदों पर अधिक प्रतिनिधित्व होता है, वे पुरुषों और महिलाओं के बीच कानूनी असमानता को समाप्त करने में सफल रहते हैं। कानूनी भेदभाव को खत्म करने से महिलाओं के लिए नए रोजगार और आर्थिक अवसर खुलते हैं, जिससे उनकी कार्यबल में भागीदारी बढ़ती है। जब महिलाओं को समान अवसर मिलते हैं, तो इसका सकारात्मक प्रभाव न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन पर पड़ता है, बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलता है। भारत में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और वित्तीय समावेशन पर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ उद्यमिता को भी प्रोत्साहित करना होगा। इसके अलावा, उन सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाओं को दूर करना आवश्यक है जो महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी को सीमित करती हैं।

रामचरित मानस का जनमानस पर प्रभाव

तुलसीदास की रचनाओं का भारतीय जनमानस पर व्यापक प्रभाव पड़ा। रामचरितमानस का भारतीय जनमानस पर अत्यधिक गहरा और व्यापक प्रभाव पड़ा है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित यह महाकाव्य न केवल धार्मिक ग्रंथ के रूप में पूजनीय है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, समाज और जीवन दर्शन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ भी है। इसके प्रभाव को कई पहलुओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस ने भगवान राम को आदर्श पुरुष और मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रस्तुत किया। इससे भारतीय जनमानस में राम के प्रति भक्ति और श्रद्धा की भावना गहरी हुई। इस ग्रंथ ने रामकथा को जन-जन तक पहुंचाया और इसे हर घर में पूजा का एक अनिवार्य अंग बना दिया। तुलसीदास के सरल भाषा में लिखे गए दोहे और चौपाइयां लोगों के दिलों में बसीं और धार्मिक कर्मकांडों का हिस्सा बन गईं।

रामचरितमानस में राम के आदर्श चरित्र, उनके धर्म पालन, न्यायप्रियता, और सत्यनिष्ठा ने समाज में नैतिक मूल्यों की स्थापना की। राम के जीवन से प्रेरित होकर लोगों ने सत्य, धर्म और कर्तव्यपालन को अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया। इसने समाज को नैतिकता और सदाचार के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। तुलसीदास ने रामचरितमानस में सामाजिक समानता और समरसता का संदेश दिया। भगवान राम का शबरी, केवट, निषादराज जैसे निम्न वर्ग के लोगों से प्रेम और सम्मान का व्यवहार जातिगत भेदभाव को समाप्त करने का संदेश देता है। इससे समाज में समता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा मिला। रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिखा गया, जो उस समय आम जनमानस की भाषा थी। इससे हिंदी भाषा और साहित्य का विकास हुआ। इस ग्रंथ ने लोक भाषा को साहित्यिक और धार्मिक अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया, जिससे यह जन-जन में लोकप्रिय हुआ। इसने हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दी और इसे व्यापक जनसमुदाय तक पहुंचाया।

रामचरितमानस ने भारतीय लोक संस्कृति में गहरे तक अपनी जड़ें जमा लीं। रामलीला और रामकथा जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम इसी ग्रंथ पर आधारित हैं और ये भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं। रामायण की कहानियों ने भारतीय कला, संगीत, नृत्य और नाटक को समृद्ध किया और इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। रामचरितमानस ने भारतीय समाज में राष्ट्रीय चेतना को भी बल दिया। रामराज्य का आदर्श समाज और राज्य की परिकल्पना से लोगों में न्याय, धर्म और राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना जागृत हुई। इसे एक आदर्श राज्य की अवधारणा के रूप में देखा गया, जहां समाज में शांति, समृद्धि और न्याय की स्थापना होती है।

गोस्वामी तुलसीदास का योगदान सामाजिक जागरण में अद्वितीय और असीमित है। उन्होंने अपने काव्य और साहित्यिक कृतियों के माध्यम से समाज को नई दिशा, नई सोच और नई ऊर्जा दी। तुलसीदास का जीवन और उनकी रचनाएं हमें यह सिखाती हैं कि समाज की उन्नति के लिए नैतिकता, समानता और न्याय का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। उनके विचार और संदेश आज भी हमें सामाजिक बुराइयों से लड़ने और एक आदर्श समाज की स्थापना के लिए प्रेरित करते हैं। प्रागैतिहासिक युग से आधुनिक युग तक मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के शील, शक्ति और सौंदर्य विमण्डित अलौकिक व्यक्तित्व के विविध रूपों ने जनमानस को आकृष्ट किया है। भारतीय साहित्य में वाल्मीकि रामायण को राम कथा काव्य का मूल स्रोत स्वीकारा गया है। इसका रचना काल श्लेगल, मकोबी, कीथ, वींटरग्रीन सरीखे पाश्चात्य विद्वानों ने ग्यारहवीं शती ईपू से लेकर तीसरी शती ईपू के बीच माना है। प्राचीन और आधुनिक भारतीय भाषाओं में जितने भी राम काव्य रचे गए हैं, उनमें गोस्वामीजी का रामचरितमानस जनमानस द्वारा जितना समादृत है उतना कोई दूसरा राम काव्य नहीं।

गोस्वामीजी की यह भक्तिभावना मूलत: लोक संग्रह की भावना से अभिप्रेरित है। जिस समय समसामयिक निर्गुण भक्त संसार की असारता का आख्यान कर रहे थे और कृष्ण भक्त कवि अपने आराध्य के मधुर रूप का आलंबन ग्रहण कर जीवन और जगत में व्याप्त नैराश्य को दूर करने का प्रयास कर रहे थे, उस समय गोस्वामी जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के शील, शक्ति और सौंदर्य से समन्वित अद्‌भुत रूप का गुण गान करते हुए लोक मंगल की साधनावस्था का पथ प्रशस्त किया। गोस्वामीजी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। उसमें लोक और शास्त्र का ही समन्वय नहीं है- गार्हस्थ्य और वैराग्य का, भक्ति और ज्ञान का, भाषा और संस्कृति का, निर्गुण और सगुण का, पुराण और काव्य का, भावावेग और अनसक्त चिंतन का समन्वय रामचरितमानस के आदि से अंत तक दो छोरों पर जानेवाली पराकोटियों को मिलाने का प्रयत्न है। तुलसी ने राम के आदर्श चरित्र के माध्यम से भारतीय संस्कृति व सभ्यता का जो आदर्श रूप स्थापित किया है वह विश्वभर में अनुपम व अद्‌भुत है, धर्म- नैतिकता की दृष्टि से सर्वोपरि है।

आज संपूर्ण विश्व एक भयावह दौर से गुजर रहा है। हमारा वैश्विक परिदृश्य अनेक संकटों से घिरा हुआ धूमिल हो रहा है। पूरा संसार अनेक प्राकृतिक प्रकोप से घिर गया है। कहीं सुनामी, तो कहीं बर्फीली तूफान, तो कहीं रेतीली तूफान, तो कहीं सूखा अकाल, तो कहीं बाढ़-प्रलय, तो कहीं भूकंप की तांडव लीला रचकर प्रकृति कहर बरसा रही है। देवभूमि उत्तराखंड में बादल फटने से हुई तबाही तथा भूस्वर्ग कश्मीर में बाढ़ से हुई बर्बादी इसके प्रत्यक्ष गवाह हैं। प्रकृति के शाश्वत नियमों को भौतिकवादी मनुष्य ने जब से तोड़ने का कार्य शुरू किया है और विकास के नाम पर इंडस्ट्रियल प्लांट धड़ल्ले से प्रतिष्ठित होने लगे हैं तभी से प्रकृति अपना आक्रोश दिखाने लगी है। नेचुरल केलमिटी ही नहीं वैज्ञानिक तथा भौतिक आपदाएं भी मानवता के लिए विराट संकट बनकर खड़ी हैं। आज का मनुष्य वैज्ञानिक आविष्कारों का दुरुपयोग धड़ल्ले से करने लगा है। पूरी दुनिया आतंकवाद, नक्सलवाद, संप्रदायवाद, हिंसा, द्वेष, आपसी कलह, सांस्कृतिक-धार्मिक संघर्ष, हत्या, बलात्कार जैसे संगीन समस्याओं से घिर गई है।

● ओम

अंधेरे में चमकता तारा

एक छोटा सा गांव था, जहां एक लड़का रहता था जिसका नाम था रवि। रवि बचपन से ही तारों को देखने का शौक रखता था। रात को जब आसमान साफ होता, तो वह छत पर जाकर तारों को घंटों निहारता रहता। गांव के लोग उसे अजीब समझते थे। वे कहते थे, तारे देखने से क्या होगा? जाकर खेतीबाड़ी का काम कर। लेकिन रवि की रुचि तारों में ही थी।

एक दिन, रवि ने एक पुराने खंडहर में एक दूरबीन पाई। वह दूरबीन बहुत पुरानी थी, लेकिन रवि ने उसे साफ करके इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। दूरबीन से उसने तारों को और भी करीब से देखा। उसे लगा जैसे वह अंतरिक्ष में उड़ रहा हो। उसने तारों के बारे में बहुत कुछ पढ़ा। उसने जाना कि तारे कैसे बनते हैं, वे कैसे चमकते हैं और वे कितने दूर हैं।

गांव के स्कूल में विज्ञान का कोई अच्छा शिक्षक नहीं था। रवि को अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए शहर जाना पड़ा। शहर में उसने एक पुस्तकालय में जाकर खगोल विज्ञान के बारे में बहुत सी किताबें पढ़ीं। उसने कई वैज्ञानिकों के बारे में जाना जिन्होंने अंतरिक्ष के बारे में बहुत कुछ खोजा था।

रवि ने तय किया कि वह भी एक वैज्ञानिक बनेगा और अंतरिक्ष के बारे में नई-नई खोज करेगा। उसने दिन-रात मेहनत की। उसने गणित और विज्ञान में ज्ञान अर्जित किया। उसने कई प्रतियोगिताओं में भाग लिया और पुरस्कार जीते।

लेकिन रवि के सामने एक बड़ी समस्या थी। उसके पास पैसे नहीं थे कि वह महंगे उपकरण खरीद सके। उसने अपने गांव के लोगों से मदद मांगी, लेकिन उन्होंने उसकी मदद नहीं की। तब रवि ने एक योजना बनाई। उसने अपने गांव के बच्चों को तारों के बारे में बताना शुरू किया। उसने उन्हें बताया कि अंतरिक्ष कितना रहस्यमयी है। धीरे-धीरे, गांव के बच्चों में भी तारों के बारे में जानने की उत्सुकता जाग गई। रवि ने गांव के लोगों से कहा कि वे मिलकर एक छोटी सी वेधशाला बनाएं। गांव के लोगों ने रवि के जुनून को देखकर उसकी मदद की। उन्होंने मिलकर एक छोटी सी वेधशाला बनाई। रवि ने उस वेधशाला में दूरबीन लगाई और गांव के बच्चों को तारे दिखाने लगा।

रवि की कहानी पूरे देश में फैल गई। कई बड़े वैज्ञानिकों ने रवि की प्रतिभा को पहचाना और उसकी मदद करने के लिए आगे आए। आज रवि एक प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक है। उसने अंतरिक्ष के बारे में कई नई खोजें की हैं।

– अज्ञात

अब गोविंद ना आएंगे

सुनो द्रौपदी! शस्त्र उठालो
अब गोविंद ना आएंगे...
छोड़ो मेहंदी खड्ग संभालो
खुद ही अपना चीर बचा लो
द्यूत बिछाए बैठे शकुनि,
मस्तक सब बिक जाएंगे
सुनो द्रौपदी! शस्त्र उठालो
अब गोविंद ना आएंगे
कब तक आस लगाओगी तुम,
बिके हुए अखबारों से
कैसी रक्षा मांग रही हो
दु:शासन दरबारों से
स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं
वे क्या लाज बचाएंगे
सुनो द्रौपदी! शस्त्र उठालो
अब गोविंद ना आएंगे
कल तक केवल अंधा राजा,
अब गूंगा-बहरा भी है
होंठ सिल दिए हैं जनता के,
कानों पर पहरा भी है
तुम ही कहो ये अंश्रु तुम्हारे,
किसको क्या समझाएंगे?
सुनो द्रौपदी! शस्त्र उठालो
अब गोविंद ना आएंगे...

– पुष्यमित्र उपाध्याय

रेगिस्तान का फूल

एक बार की बात है, एक रेगिस्तान था। रेगिस्तान में रेत के टीले ही टीले थे। न कोई पेड़-पौधा, न कोई पानी। लेकिन इस रेगिस्तान में एक छोटा सा बीज था। वो बीज बहुत दिनों से सो रहा था। एक दिन, जब आसमान में बादल छाए और बारिश हुई तो वो बीज जाग गया। उसने सोचा, मुझे इस रेगिस्तान में कैसे पनपना है? लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और धीरे-धीरे बढ़ने लगा।

दिन बीतते गए और वो बीज एक छोटे से पौधे में बदल गया। पौधे को रेगिस्तान की गर्मी और सूखे से बहुत तकलीफ होती थी। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी जड़ों को गहराई में धकेला ताकि वो पानी ढूंढ सके। उसने अपने पत्तों को छोटा कर लिया ताकि कम पानी खर्च हो।

धीरे-धीरे वो पौधा एक खूबसूरत फूल में बदल गया। उस फूल का रंग इतना चमकीला था कि दूर से ही दिखाई देता था। रेगिस्तान में उस फूल को देखकर सभी हैरान थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इस रेगिस्तान में इतना खूबसूरत फूल कैसे उग आया।

एक दिन, एक बूढ़ा आदमी रेगिस्तान में घूम रहा था। उसने दूर से ही उस फूल को देखा। वो फूल देखकर वो बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, इस रेगिस्तान में इस फूल को उगने में कितनी हिम्मत लगी होगी। बूढ़े आदमी ने उस फूल को देखा और सोचा कि जीवन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए।

– अज्ञात

> 36 साल के विराट कोहली ने 12 मई को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया। वे अगर 1-2 साल और खेलते तो 10 हजार रन बनाकर इस फॉर्मेट में भारत के तीसरे टॉप स्कोरर बन जाते, लेकिन विराट ने रिकॉर्ड की परवाह नहीं की।

'विराट' संन्यास

विराट कोहली टेस्ट में भारत के चौथे टॉप स्कोरर रहे। देश के टॉप-5 टेस्ट स्कोरर में कोहली ने ही सबसे जल्दी संन्यास लिया। सचिन तेंदुलकर ने तो 36 साल की उम्र के बाद 9 टेस्ट शतक और लगा दिए थे। वे 40 साल तक खेले, लेकिन विराट ने इस फॉर्मेट में अपना करियर लंबा नहीं होने दिया। दरअसल, विराट कोहली ने 2019 में अपना 27वां टेस्ट शतक लगाया। अगले ही साल कोरोना वायरस आया, मुकाबले कम होने लगे और कोहली ने अपना पीक फॉर्म खो दिया। 2019 तक उन्होंने करीब 55 की औसत से 7202 रन बना लिए थे। वे अगले 5 साल के 39 टेस्ट में महज 31 की औसत से 2028 रन ही बना सके। इस दौरान उनके बैट से 3 ही सेंचुरी निकलीं। कोहली के खराब फॉर्म में कोरोना के बाद की बॉलिंग फ्रेंडली पिचों का योगदान भी बड़ा रहा। महामारी के बाद कोहली ने 37 टेस्ट में 32.09 की औसत से रन बनाए, जो उनके स्टैंडर्ड से बेहद सामान्य रहा। हालांकि, इस दौरान दुनियाभर के टॉप-7 बैटर्स का औसत महज 29.87 का रहा। वहीं कोहली को छोड़कर टीम इंडिया के बाकी टॉप-7 बैटर्स का औसत भी 31.15 का ही रहा। यानी कोहली पिछले 5 साल में दुनिया के टॉप बैटर्स में कम्पीट तो करते रहे, लेकिन उन्हें अपने ही स्टैंडर्ड में गिर जाना नहीं पसंद आया। बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी पिछली 3 सीरीज में भी कोहली आउट ऑफ फॉर्म नजर आए। वे एक फिफ्टी और एक सेंचुरी ही लगा सके। 3 से 5 जनवरी तक उन्होंने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी टेस्ट खेला और मई में संन्यास ले लिया।

गौतम गंभीर अगस्त 2024 में टीम इंडिया के नए हेड कोच बनाए गए। उन्होंने कोच बनते ही बयान दिया था कि वे टीम इंडिया के स्टार कल्चर को खत्म करना चाहते हैं। उनका मानना रहा कि फैंस और मैनेजमेंट का फोकस प्लेयर के रिकॉर्ड्स से ज्यादा टीम की जीत पर होना चाहिए। गंभीर की एंट्री के बाद बीसीसीआई ने लंबे दौरों पर परिवार के ज्यादा समय साथ रहने पर पाबंदी लगा दी। पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और टीम के कुछ सीनियर प्लेयर इस फैसले से नाराज नजर आए। गंभीर के कोच बनने के बाद टीम ने न्यूजीलैंड से घरेलू मैदान और ऑस्ट्रेलिया से उन्हीं के मैदान पर सीरीज की हार झेली। जिसके बाद अश्विन, रोहित और विराट को संन्यास लेना पड़ गया। टीम इंडिया के वनडे कप्तान रोहित शर्मा ने 7 मई को टेस्ट से संन्यास लिया। इसके 5 दिन के भीतर विराट कोहली ने फिर रेड बॉल क्रिकेट को अलविदा कह दिया। यह पहला मौका नहीं है, जब दोनों प्लेयर्स ने एक साथ किसी फॉर्मेट से संन्यास लिया। 29 जून 2024 को जब भारत ने टी-20 वर्ल्ड कप जीता था, तब प्लेयर ऑफ द फाइनल विराट कोहली ने प्रेजेंटेशन सेरेमनी में टी-20 से संन्यास की घोषणा की। जिसके कुछ देर बाद ही रोहित शर्मा ने भी जीत सेलिब्रेट करते हुए सबसे छोटे फॉर्मेट को अलविदा कह दिया था। यानी रोहित के टेस्ट रिटायरमेंट ने कहीं न कहीं कोहली पर भी संन्यास लेने का दबाव बनाया। नवंबर से जनवरी के बीच भारत ने ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट दौरा किया, जहां टीम को 3-1 से हार का सामना करना पड़ा। कोहली ने पहले ही मुकाबले में शतक लगाया, जिसके बाद उन्हें लगा कि वे अपना फॉर्म वापस पा चुके हैं। हालांकि, बाद के 4 टेस्ट की 7 पारियों में विराट हर बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद पर स्लिप में ही कैच हुए। वे एक भी फिफ्टी नहीं लगा सके और 190 रन के साथ सीरीज खत्म की। ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बाद कोहली ने कहा था कि वे इस फॉर्मेट में अपना फॉर्म खोने लगे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, तब उन्होंने अपने साथी खिलाड़ी से कह दिया था कि वे इस फॉर्मेट में खुद को और आगे बढ़ते हुए नहीं देखते। जिसके बाद मई में कोहली ने संन्यास ही ले लिया।

2019 में शुरू हुई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी कोहली के संन्यास की बड़ी वजह है। क्योंकि 20 जून से इंग्लैंड में टीम इंडिया की 5 टेस्ट की सीरीज शुरू होगी। जो 2027 की डब्ल्यूटीसी में भारत की पहली सीरीज है, यहीं से टीम इंडिया का फाइनल में पहुंचना तय होगा। कोहली कई इंटरव्यूज में कह चुके हैं कि अगर उन्हें लगेगा कि वे टीम के लिए कॉन्ट्रिब्यूट नहीं कर पा रहे तो वे संन्यास ले लेंगे। उन्हें महसूस हुआ होगा कि युवा टीम तैयार करने के लिए जरूरी है कि डब्ल्यूटीसी में नई टीम को ही मौका मिले। क्योंकि वे खुद की कप्तानी में 2 बार टीम इंडिया को डब्ल्यूटीसी के फाइनल में पहुंचा चुके हैं। कोहली जब कप्तान नहीं रहे तो टीम खिताबी मुकाबले के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी। ऐसे में संभव है कि कोहली ने टीम के भविष्य को ध्यान में रखते हुए रिटायरमेंट लिया। भारत के टॉप-5 टेस्ट रन स्कोरर में विराट कोहली चौथे नंबर पर रहे। कोहली 10 हजार रन से महज 770 रन दूर थे, वे अगर 893 रन और बनाते तो देश के तीसरे टॉप स्कोरर भी बन जाते। अब सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सुनील गावस्कर ही ऐसे भारतीय बचे, जिनके नाम टेस्ट में 10 हजार रन हैं। कोहली को छोड़कर भारत के टॉप-5 रन स्कोरर ने जब संन्यास लिया, तब उनकी उम्र 38 साल या उससे ज्यादा ही रही। गावस्कर ने 38, द्रविड़ ने 39 और लक्ष्मण ने 38 साल की उम्र में संन्यास लिया। सचिन तो 40 की उम्र तक खेले, इतना ही नहीं उन्होंने 36 साल के बाद 9 टेस्ट शतक भी लगाए। ऐसे में सवाल उठना लाजमी ही है कि कहीं कोहली ने 2-3 साल पहले तो टेस्ट रिटायरमेंट नहीं ले लिया?

● **आशीष नेमा**

टेस्ट क्रिकेट में पूरे नहीं कर पाए 10,000 रन

विराट कोहली ने वनडे क्रिकेट में अभी तक कुल 14181 रन बनाए हैं, जिसमें उनके नाम पर 51 शतक दर्ज हैं। वहीं उन्होंने भारत के लिए 123 टेस्ट मैचों में कुल 9230 रन बनाए। टेस्ट क्रिकेट में वह 10,000 रन पूरे करने से सिर्फ 770 रन दूर थे। अगर वह टेस्ट से संन्यास नहीं लेते और टेस्ट में 10,000 रन पूरे कर लेते, तो वह भारत के लिए टेस्ट और वनडे दोनों फॉर्मेट में 10 हजार से ज्यादा रन बनाने वाले तीसरे भारतीय बल्लेबाज बन जाते, लेकिन ऐसा हो ना सका। विराट कोहली ने साल 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में टेस्ट में डेब्यू किया था। इसके बाद उन्होंने धीरे-धीरे क्रिकेट के सबसे बड़े फॉर्मेट में अपनी जगह बनाई और सबसे बड़े सुपर स्टार बनकर उभरे। साल 2014 में वह भारतीय टेस्ट टीम के परमानेंट कैप्टन भी बन गए थे। उनकी कप्तानी में भारतीय टीम ने कुल 40 मैच जीते और विदेशी धरती पर अपना लोहा मनवाया। वह भारत के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट मैच जीतने वाले कप्तान रहे। विराट कोहली ने भारतीय टेस्ट कप्तान के तौर पर विदेशों में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था। उन्होंने साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट कप्तान के तौर पर दो टेस्ट जीते और इंग्लैंड में तीन मैच जीते। वह भारत के लिए विदेशों में सबसे ज्यादा 16 टेस्ट मैच जीतने वाले कप्तान रहे।

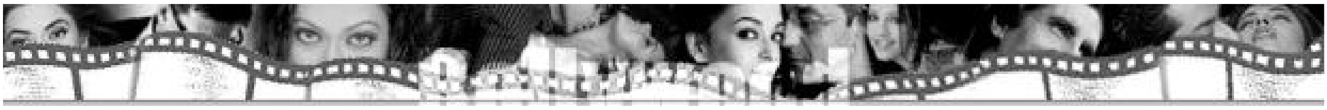

वो फिल्म... जिसकी शूटिंग के दौरान डायरेक्टर से रोज लड़ते थे ऋषि कपूर

मूवी ने झटक लिए थे 18 अवॉर्ड

ऋषि कपूर ने 70 के दशक में रोमांटिक हीरो बनकर अपने करियर की शुरुआत की। उनकी पहली फिल्म बॉबी ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। इसके बाद उन्होंने कई यादगार किरदारों को बड़े पर्दे पर उतारा। आज हम आपको साल 2016 की उस फिल्म के बारे में बताते हैं, जिसकी शूटिंग के दौरान वह डायरेक्टर से रोज लड़ते थे। उस मूवी का नाम है कपूर एंड संस।

कुछ सालों पहले ऋषि कपूर ने आपकी अदालत शो में खुलासा किया था कि कपूर एंड संस की शूटिंग के दौरान उनकी डायरेक्टर से रोज लड़ाई होती थी। उनसे पूछा गया कि आप हर दिन डायरेक्टर से लड़ते थे? जवाब में ऋषि कपूर ने कहा, मेरे ख्याल से मैंने 25-26 दिन फिल्म के लिए काम किया था। इसके बाद ऋषि कपूर ने बताया कि उनकी डायरेक्टर से लड़ाई क्यों होती थी। उन्होंने कहा, मुझे मेकअप करने के लिए साढ़े पांच घंटे लगते थे। सुबह पांच बजे से लगभग 11 बजे तक मेकअप चलता था फिर मैं सेट पर जाता था। जितने दिन मैंने काम किया, मेरा डायरेक्टर से क्रिएटिविटी को लेकर कोई झगड़ा नहीं हुआ। कपूर एंड संस फिल्म ने दुनियाभर में 147.94 करोड़ रुपए की कमाई की थी। ऋषि कपूर ने फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्मफेयर अवॉर्ड जीता था। आईएमडीबी के मुताबिक, कपूर एंड संस फिल्म ने टोटल 18 अवॉर्ड अपने नाम किए थे।

मैं कोई मेथड एक्टर नहीं हूं... ऋषि कपूर ने आगे कहा, मेरा एग्जीक्यूशन को लेकर झगड़ा होता था। मतलब कि शॉट कहां-कहां से लेंगे। वो चाहते थे कि हर एंगल से शॉट लिया जाए। मैं कोई मेथड एक्टर नहीं हूं, लेकिन मेरा स्टाइल है कि मैं कोई चीज एक ही बार कर सकता हूं। बार-बार करने में डिलीवर नहीं कर पाता हूं। मैं पूछता था कि बताओ मेरा मेन एंगल क्या है। उन्होंने आखिर में कहा, मैं खिलाफ था कि हर एंगल से मेरा शॉट ना लिया जाए, क्योंकि मुझसे ये होता नहीं था। फिर जब मैंने फिल्म देखी तो मैंने कहा कि भाई तुम सही थे और मैं गलत। हो सकता है कि मैं पुराने ख्यालात का हूं, लेकिन जो भी हो आखिर में जो रिजल्ट आया, वो बहुत अच्छा था।

महंगे तोहफे देकर बदले में कुछ चाहते थे राजेश खन्ना, पूरा न होने पर बिगड़ जाते थे रिश्ते, 80 साल की हीरोइन का खुलासा

साल 1970 और 1980 के दशक में, राजेश खन्ना बॉलीवुड में सफलता के 9वें आसमान पर थे। शर्मिला के साथ उनकी फिल्में, जैसे आराधना, सफर और अमर प्रेम ने उन्हें एक हिट ऑन-स्क्रीन जोड़ी के रूप में स्थापित किया। ऑडिबल ऑडियोबुक, राजेश खन्ना: एक तन्हा सितारा में, शर्मिला खान ने खुलासा किया कि काका ने अपने को-स्टार्स को तमाम तरह के बड़े उपहार दिए थे। अभिनेत्री का कहना है कि काका के ऐसे उदारवादी व्यवहार से कभी-कभी उनके रिश्तों में तनाव या कहें खटास आ जाती थी, क्योंकि वो भी बदले में उनसे चीजों की अपेक्षा करते थे। ऐसे में हम कह सकते हैं कि राजेश खन्ना भारतीय सिनेमा के पहले सुपरस्टार थे, जिनके अपने फायदे और नुकसान थे।

अक्सर खुद को मुश्किल स्थिति में पाती थीं... ऑडियोबुक में, यह स्वीकार करते हुए कि जब उन्होंने खन्ना के साथ कम फिल्में कीं तो उन्हें राहत क्यों मिली, शर्मिला टैगोर ने याद किया कि शेड्यूल पर रहना असंभव था, क्योंकि राजेश खन्ना सुबह 9 बजे की शिफ्ट के लिए दोपहर से पहले कभी नहीं आते थे, जिससे दिन का काम पूरा करने में देरी होती थी। ऐसे में पूरी यूनिट शेड्यूल को पूरा करने के लिए उन पर ओवरटाइम करने का दबाव बनाती थी। समय के साथ, यह उनकी एक दिनचर्या बन गई, और खन्ना से जुड़ी कई चल रही परियोजनाओं के साथ, टैगोर अक्सर खुद को मुश्किल स्थिति में पाती थीं।

बैन कर दी गई थी शशि कपूर की ये फिल्म, हीरोइन को देख दर्शकों ने पकड़ लिया माथा, 1 सीन में तो घबरा गई थीं एक्ट्रेस

राज कपूर की साल 1987 में आई फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में जीनत अमान और शशि कपूर की ऐसी केमिस्ट्री दिखाई गई थी कि लोग फिल्म देखकर हैरान हो गए थे, शशि कपूर की इस फिल्म पर अश्लीलता फैलाने के आरोप लगे थे। इसी तरह साल 1972 में शशि कपूर की एक फिल्म ने तहलका मचा दिया था। शशि की उस फिल्म का नाम है सिद्धार्थ। इस फिल्म में कई ऐसे सीन फिल्माए गए थे कि जिन पर उस दौर में खूब आपत्ति जताई गई थी। इतना ही नहीं शशि कपूर इस फिल्म में अपनी को-स्टार की खूबसूरती पर फिदा हो गए थे। शशि कपूर के साथ फिल्म में नजर आईं खूबसूरत हसीना थीं, सिमी ग्रेवाल। जिन्होंने शशि कपूर के साथ फिल्म सिद्धार्थ में काम किया था। इस फिल्म के एक सीन के दौरान एक्ट्रेस काफी नर्वस थीं। उस दौरान खुद शशि कपूर उनकी खूबसूरती देखते रह गए थे। इस बात का जिक्र एक्ट्रेस ने असीम छाबड़ा की किताब शशि कपूर: द हाउसहोल्डर स्टार में किया था।

रिलीज से पहले ही विवाद... फिल्म सिद्धार्थ 1972 में रिलीज से पहले ही विवादों में घिर गई थीं। इस फिल्म में सिमी ग्रेवाल के एक न्यूड सीन की वजह से भारत में काफी विवाद हुआ था, क्योंकि उस समय भारतीय सेंसर बोर्ड ऑन-स्क्रीन किस तक अनुमित नहीं देता था।

तिकड़म...

इस असार संसार में ऐसा भी बहुत कुछ विद्यमान है, जो ससार है, सारवान है। ऐसे ही सारवानों में एक शब्द तिकड़म है। जिससे इस संसार का बहुत कुछ उपक्रम संचालित है। अगर यह न होता तो यह संसार अपने बहुत कुछ अति महत्वपूर्ण से वंचित हो सकता था। तिकड़म की संतानों की संख्या इतनी अधिक है कि स्वयं तिकड़म को भी नहीं पता कि वह कितनी जायज संतानों की जननी है। बस उसे जन्म देते चले जाना है। इस बात की उसे कभी जिज्ञासा नहीं हुई कि उसकी यह जनसंख्या वृद्धि क्यों और किस उद्देश्य से होती जा रही है।

तिकड़म की सभी संतानों की संख्या और नाम का अभिज्ञान तो इस अकिंचन को भी नहीं है। कोई दो-चार हों तो गिना और बताया जाए, जब दिन दूना और रात चौगुना प्रजनन हो रहा है तो कोई कितना हिसाब रखे। तिकड़म के कुछ खास-खास और बड़े-बड़े बच्चों के नाम और उनकी ख्याति का गुणगान अपनी सीमा में रहकर बताने का प्रयास करूंगा।

तिकड़म के परिवार में जाने से पहले यह जानना भी आवश्यक है कि वह कौनसी अनुकूल परिस्थितियां रही होंगीं जब तिकड़म ने अवतार लिया होगा। तिकड़म का जन्म स्थान मनुष्य की बुद्धि है। इस जागतिक जगत के बहुत सारे कामकाज, व्यवस्थाएं और रीति-नीतियां सामान्य रूप से संचालित नहीं हो पा रही होंगीं तो दिमाग में किसी कुटिल कीट ने विदेह रूप धारण कर लिया, जो चुटकी बजाते ही वह असाध्य कार्य करने में तत्पर था। जिसे तिकड़म नामधारी संज्ञा से अभिहित किया गया। यह अपने वास्तविक स्वरूप में किसी सरलरता, सौम्यता, स्पष्टता, सादगी और सभ्यता के विपरीत ही था। इसे उलटे-सीधे चलने से कोई परहेज नहीं था। येन-केन-प्रकारेण अपना उल्लू सीधा करना ही इसका उद्देश्य रहा। छल, दंभ, द्वेष, पाखंड, अनीति, अन्याय आदि सबका साथ लेकर सबका कार्य साधना ही इसका लक्ष्य माना गया। निराश में आशा का संचार करना ही इसका मुख्य ध्येय था। तरीका क्या रहे, कैसा रहे-इससे कोई मतलब नहीं। बस लक्ष्य सिद्धि ही तिकड़म की चिड़िया की आंख बनी।

आपकी जिज्ञासा है तो यह बता देना भी आवश्यक है कि तिकड़म की संतानें कौन-कौन हैं और वे किस प्रकार फल-फूल रही हैं। कुछ ऐसे प्रसिद्ध तिकड़म संतति के नाम मेरी जानकारी में हैं, उन्हें बताए दे रहा हूं। इनमें राजनीति, रिश्वत, मिलावट, चौर्य, गबन, छल, धोखा, अनीति, व्यभिचार, चरित्रहीनता आदि प्रमुख संततियां हैं। यदि इनमें से किसी एक का भी कच्चा चिट्ठा खोल लीजिए तो कई-कई महाग्रंथों का निर्माण हो जाए। राजनीति को तिकड़म की सबसे बड़ी संतान समझा जा सकता

तिकड़म के परिवार में जाने से पहले यह जानना भी आवश्यक है कि वह कौनसी अनुकूल परिस्थितियां रही होंगीं जब तिकड़म ने अवतार लिया होगा। तिकड़म का जन्म स्थान मनुष्य की बुद्धि है। इस जागतिक जगत के बहुत सारे कामकाज, व्यवस्थाएं और रीति-नीतियां सामान्य रूप से संचालित नहीं हो पा रही होंगीं तो दिमाग में किसी कुटिल कीट ने विदेह रूप धारण कर लिया, जो चुटकी बजाते ही वह असाध्य कार्य करने में तत्पर था।

है। यह अनादि काल से अपने नए-नए मुखौटों में प्रकट होती हुई विरोधियों को धूलिसात करती हुई जनहित करने पर उतारू है। इसके लिए कुछ भी उचित या अनुचित नहीं है। बस सामने वाले को पछाड़ना है। यह पवित्र कार्य कैसे भी हो, किसी भी साधन से हो, हिंसा या अहिंसा से हो, यह नहीं देखना; बस सामने वाला विपक्षी धराशायी हो जाना चाहिए। नाम के साथ यों तो नीतिशब्द भी जुड़ा हुआ है, किंतु उसे नीति से कोई मतलब नहीं है; जो है सब राज ही राज है। सब राज (रहस्य) की ही बात है। यदि उनके राज की बात ही किसी के सामने खुल गई तो क्या रहा राज और क्या रही राजनीति? सब कुछ टेढ़ी चालों और छलों की मोटी दीवार के पीछे छिपा हुआ चलता है। जो जितना बड़ा राजनेता, उतना बड़ा तिकड़मी। इस तिकड़म शब्द ने तिकड़म, तिकड़मी, तिकड़मबाज, तिकड़मबाजी, तिकड़मखोर आदि अनेक शब्दों को जन्म देकर हिंदी शब्दकोष के भंडार की अभिवृद्धि की है।

सबसे बड़ी संतति राजनीति की तरह रिश्वत, मिलावट, चौर्य, गबन आदि भी उसके छोटे भाई-बहन हैं। छोटे इस अर्थ में हैं कि वे सभी राजनीति के उदर में समाए हुए हैं। कब कौन सा काम में लेना पड़े यह राजनीति और राजनेता ही जानता है। कहना यह चाहिए कि ये सभी उसी के वरदहस्त हैं। राजनीति की छत्र-छाया तले पनपते, फलते-फूलते और हंसते-मुस्कराते हैं। वैसे तो सब दूध के धोए हैं, किंतु जब पूंछ-प्रक्षालन होता है, तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है।

तिकड़म कभी भी सीधी अंगुली से घी निकालने में विश्वास नहीं करती। उसका यह अटूट विश्वास है कि घी को कभी सीधी अंगुली से निकाला ही नहीं जा सकता। उसके लिए अंगुली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। इस असार संसार में सबको जीना है, इसलिए तिकड़म भी आना चाहिए। बिना तिकड़म के आम आदमी जिंदा नहीं रह सकता। यह एक सर्वमान्य सिद्धांत बन गया है। जंगल में वही पेड़ पहले काटे जाते हैं, जो सीधे होते हैं। सीधे और सरल आदमी का जीना तिकड़मबाज दुष्कर कर देते हैं। इसलिए सबको तिकड़म सीखना और उसका सदुपयोग करना भी आना युगीन आवश्यकता बन गई है। इस तिकड़म के चलते आम आदमी शुद्ध अन्न-पानी भी नहीं ले सकता। नीति-सुनीति भाड़ में झोंक दी गई हैं। बस अनीति का ही एकमात्र सहारा है, जहां तिकड़म का हरा-हरा चारा है। जहां तिकड़म नहीं, वहां मूर्खता की नीर-धारा है। तिकड़म के आगे भला कौन नहीं हारा है! तिकड़म का एक नहीं, पैना तिधारा है। जो तिकड़म से दूर है, वही तो बेचारा है।

● डॉ. भगवत स्वरूप 'शुभम'

PRISM®
CEMENT

प्रिज़्म® चैम्पियन प्लस

ज़िम्मेदारी मज़बूत और टिकाऊ निर्माण की.

- ज्यादा मज़बूती
- ज्यादा महीन कण
- ज्यादा वर्कबिलिटी
- बेहतरीन निर्माण कार्य
- इको–फ्रेन्डली
- कन्सिसटेंट क्वालिटी
- ज्यादा प्रारम्भिक ताक़त
- ज्यादा बचत

PRISM®
प्लस
चैम्पियन
सीमेंट

दूर की सोच®

Toll free: 1800-572-1444 Email: cement.customerservice@prismjohnson.in

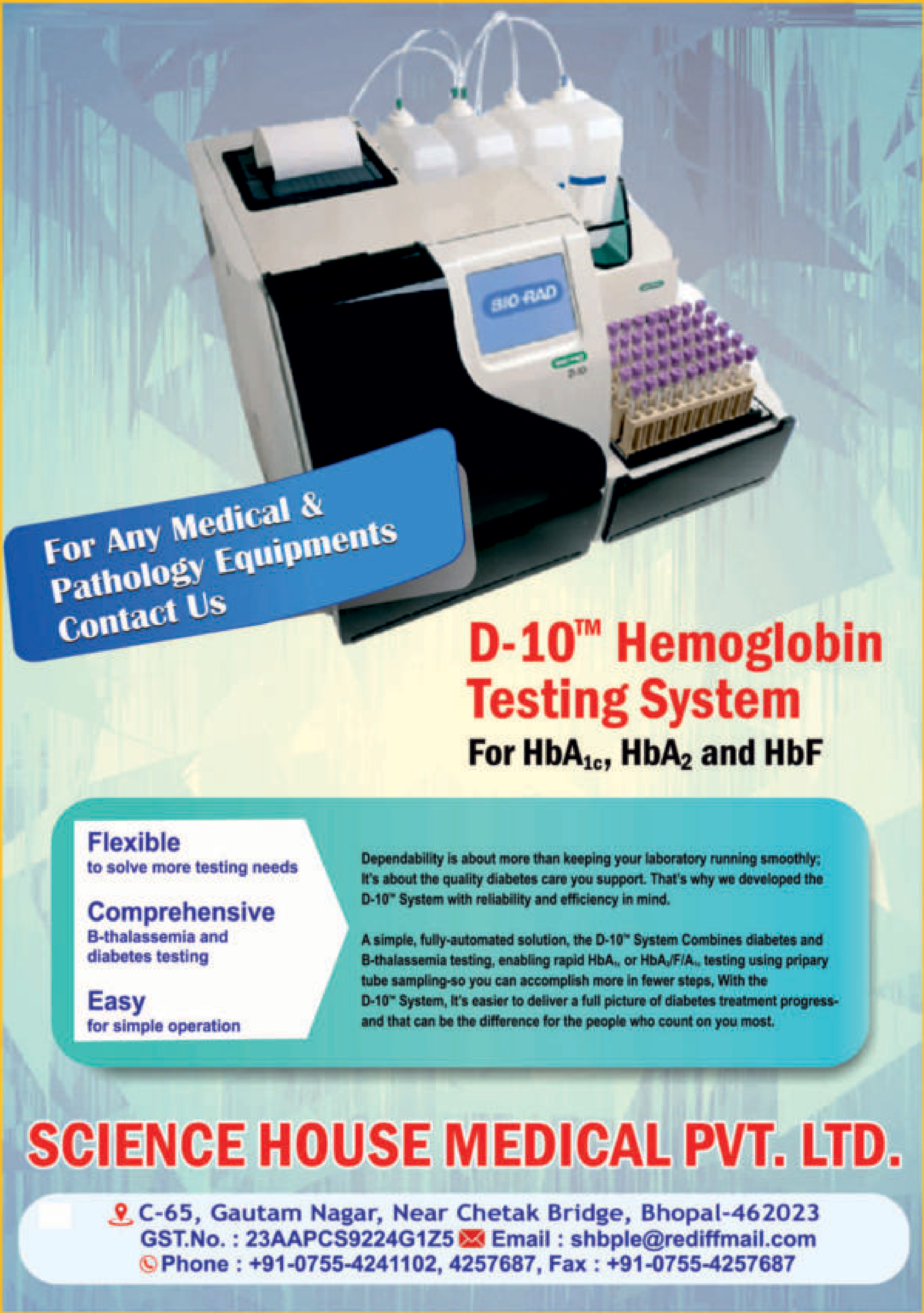
BIO-RAD
For Any Medical & Pathology Equipments Contact Us
D-10™ Hemoglobin Testing System
For HbA_{1c}, HbA_2 and HbF
Flexible
to solve more testing needs
Comprehensive
B-thalassemia and diabetes testing
Easy
for simple operation
Dependability is about more than keeping your laboratory running smoothly; It's about the quality diabetes care you support. That's why we developed the D-10™ System with reliability and efficiency in mind.
A simple, fully-automated solution, the D-10™ System Combines diabetes and B-thalassemia testing, enabling rapid HbA_{1c} or $HbA_2/F/A_{1c}$ testing using pripary tube sampling-so you can accomplish more in fewer steps, With the D-10™ System, It's easier to deliver a full picture of diabetes treatment progress-and that can be the difference for the people who count on you most.
SCIENCE HOUSE MEDICAL PVT. LTD.
C-65, Gautam Nagar, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023
GST.No. : 23AAPCS9224G1Z5 Email : shbple@rediffmail.com
Phone : +91-0755-4241102, 4257687, Fax : +91-0755-4257687